BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

FIFTY-SEVENTH REPORT

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): Sir, I beg to move:

"That this House do agree with the Fifty-seventh Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 6th January, 1976."

MR SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Fifty-seventh Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 6th January, 1976".

The motion was adopted.

12.05 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*contd*

MR. SPEAKER: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Dinesh Chandra Goswami and seconded by Shri Shankar Dayal Singh on the 6th January 1976, namely:

"That an Address be presented to the President in the following terms:—

'That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the 5th January 1976' ".

Shri B. R. Shukla may continue his speech. The time already taken by him was three minutes. The balance time which he may take is nine minutes.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं निवेदन कर रहा था कि देश में कौन सी ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, जिस से विवश हो कर राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति की घोषणा करनी पड़ी । गैरपार्लियामेंट्री तरीकों को अपना कर गुजरात की विधान सभा को भंग कराया गया । उससे प्रोत्साहित हो कर श्री जयप्रकाश नारायण ने बिहार में एक आन्दोलन चलाया कि वहां की विधान सभा को भी भंग कर दिया जाय और उस के लिए हर तरह की अशोभनीय, नाजायज और गैर पार्लियामेंटरी कार्यवाहियां की गईं । लेकिन श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन को विधान सभा को भंग कराने में कोई कामयाबी नहीं हुई । तब उन्होंने बिहार में अपना कार्यक्षेत्र छोड़ कर देश में भ्रमण करना शुरू किया, लेकिन उस में उन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई । उन का आन्दोलन लगभग समाप्त हो चुका था जब कि उसी जमाने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, के इलैक्शन के सिलसिले में फैसला दिया, और उस फैसले में उस ने यह भी आदेश दिया कि उस पर अमल-दरामद बीस दिन तक नहीं किया जायेगा ।

विरोधी पक्ष के जो नेता फाशिस्ट तरीकों में विश्वास रखते हैं, जिन का जनतंत्र में कोई विश्वास नहीं रह गया था, उन्होंने देश में एक आन्दोलन करने की घोषणा की । 25 जून, 1975 को उन्होंने एक आम सभा में यह ऐलान किया कि एक देशव्यापी आन्दोलन किया जायेगा, प्राइम मिनिस्टर के निवास स्थान पर घेराव किया जायेगा,

[श्री बी० आर० शुक्ल]

धरना दिया जायेगा और सत्याग्रह किया जायेगा। इस के अतिरिक्त सेना और पुलिस के अधिकारियो और जवानों को उकसाया गया कि वे हुक्म न मानें और विद्रोह करे। जब देश मे यह माहौल पैदा हो गया, और पूर्ण रूप से इस बात की आशंका हो गई कि देश का सामान्य जीवन अस्तव्यस्त हो जायेगा, गवर्नमेंट बिल्कुल पैरालाइज हो जावगी और लोकतंत्रीय संस्थाए नही चल पायेंगी, तब आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई।

मैं समझता हू कि 26 जून, 1975 को गवर्नमेंट ने जैसा निश्चयात्मक और दृढ़ कदम उठाया, वैसा कदम प्रशासन ने 28 साल के इतिहास मे कभी भी नही उठाया। उस समय आपातकालीन स्थिति को लागू करने के सिवाय सरकार और देश के सामने कोई अन्य विकल्प नही था। आपातकालीन स्थिति लागू करने के बाद देश मे एक चमत्कार हुआ और अनेक क्रान्तिकारी सुधार हुए। आज हम देखते है कि सारे स्मगलर जेलखाने मे बन्द है। जो प्रतिक्रियावादी शक्तिया देश की स्थिरता को भग करने पर तुली हुई थी, जो लोग देश के प्रशासन के मार्ग मे हर तरह के गैर-कानूनी रोड़े अटकाने में लगे हुए थे, आज उन का स्थान पार्लियामेंट मे नही है, बल्कि दूसरी जगहो मे है।

हम लोगो को यह तकलीफ जरूर है कि हमारे कई भाई, जो निर्वाचित सदस्य हैं, आज इस डीबेट में शरीक नहीं हैं। लेकिन इस की जिम्मेदारी किस पर है? इसकी जिम्मेदारी सरकार या कांग्रेस पार्टी पर नहीं है। इस की जिम्मेदारी उन के अपने कारनामों पर है। श्री समर मुकर्जी ने कल यह क्वोटेशन पेश किया

Absolute power corrupts absolutely.

मैं उस में इतना संशोधन करना चाहता हू:

Absolute irresponsibility also corrupts absolutely.

जनतंत्र चलाने की जिम्मेदारी केवल शासक दल पर ही नही होती है, बल्कि विरोधी पक्ष के नेताओं पर भी उतनी ही जिम्मेदारी है। डेमोक्रेसी की गाड़ी दो पहियो पर चला करती है। अगर एक पहिया बेकार हो जाता है, या ठीक तरह से काम नही करता है, तो जनतंत्र की गाड़ी के चलने में जरूर बाधा पड़ती है। यह एमरजेंसी जो लागू की गई है यह एक असाधारण परिस्थिति मे लागू की गई है। अब सवाल यह उठता है कि इस से क्या क्या लाभ हुए? कारखानो मे उत्पादन बढ़ गया। शिक्षा संस्थाओं मे शांतिपूर्वक हमारे बच्चे पढ़ रहे है। प्रोफेसर अपने काम का अजाम दे रहे है। रेलगाडियां ठीक समय पर सब चल रही है। सारे देश मे एक व्यवस्था और अनुशासन के शासन का सूत्रपात हो गया है।

इस एमर्जेंसी के कारण देश मे स्थिति तो अच्छी आई लेकिन क्या इस को हमे हमेशा के लिए कायम रखना चाहिये या कितने

दिनों के लिए कायम रखना चाहिये । यह सवाल बहुत मुश्किल है और इस का जवाब केवल वही लोग नहीं दे सकते हैं जो शासन की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं । मैं अपने उन विरोधी मित्रों से भी पूछना चाहता हूं कि कितने दिन आप को लगेंगे अपने दिमाग को ठीक करने में, कितने दिन आप को लगेंगे ठीक ठीक रास्ते पर आने में ? कितने दिन में आप इस हाउस में बैठे कर रचनात्मक कार्य मे सहयोग देने के लिए तैयार हो जायेंगे ।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : हमारा दिमाग बिलकुल ठीक है ।

श्री बी० आर० शुक्ल : आप के दिमाग का रवैया चूंकि ठीक है इसीलिए आप यहा पर बरकरार बैठे हुए हैं । लेकिन आप समय और मौका ले कर के जेल में जा कर जो लोग वहां नजरबन्द हैं उन के दिमाग की भी जांच कर के यहा पर रिपोर्ट करें . . . . (व्यवधान) . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर । आप सामने चेयर की तरफ अपनी बात कहिए ।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Burdwan): May I know who will decide whether somebody's *dimag* is all right or not? Who will decide?

श्री बी० आर० शुक्ल : दूसरी बात यह है कि नौकर-तंत्र के ऊपर काफी टीका-टिप्पणी की गई है । यह ठीक है, जब एक बड़ा कदम, असाधारण कदम उठाया जाता है और सारे मुल्क में उठाया जाता है तो उस में कहीं न कहीं खामियां और त्रुटियां होंगी। लेकिन सवाल यह है कि इन छोटी छोटी त्रुटियों और खामियों की वजह से एमर्जेंसी जिस को केवल छः महीने बीते हैं उसे इतनी जल्दी उठा लिया जाय ? स्थिति इस बात का तकाजा करती है कि इस आपत्कालीन स्थिति को और कुछ समय के लिए जारी रखा जाय जिस से कि अनुशासन की प्रवृत्ति जो जनता मे आ रही है वह सुदृढ़ हो कर के उन के दिल और दिमाग मे बैठ जाय और अनुशासन हमारे जीवन का एक अंग बन जाय जिस से जनतंत्र और समाजवाद सुरक्षित हो सके । इसलिए मैं चाहता हूं कि यह स्थिति फिलहाल कायम रहे ।

अब दूसरा प्रश्न यह पैदा होता है. इस के कार्यान्वयन के बारे में एतराज किया गया है । विरोधी पक्ष के मित्रों ने कहा कि सीमेंट के कारखानों मे सीमेंट पड़ा हुआ है, कपड़े के कारखानों में कपड़े की बहुतायत है, लोहे के कारखानों मे लोहा बहुतायत में है यह क्यों ? यह इसलिए कि जो जखीरेबाज और ब्लैक-मार्केटियर्स हैं उन को आज यह एहसास हो गया है कि कोई कानून, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट उन के काले कारनामों के नतीजे से उन को बचा नहीं सकता है ।

मैं केवल दो मिनट और चाहता हूं । मैं यह चाहता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन समिति का गठन जल्दी से जल्दी हो । हम पार्लियामेंट के सदस्यों के ऊपर यह एतराज किया जाता है कि वे केवल भाषण देना जानते हैं । मै आप के माध्यम

[श्री बी० और० शुक्ला]

से सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूं कि भाषण देने के अलावा और हम लोगों को अधिकार ही क्या दिए गए हैं ? हम किस प्रकार से इस देश के निर्माण में और इस के अंदर समाजवादी व्यवस्था को लाने में शामिल होकर अपना योगदान दे ?

विज्ञान और टैकनोलाजी की तरक्की इस देश मे जोरो से हो रही है। आर्य भट्ट हजारो चक्कर गगन मे लगा चुका है। टेलीविजन हर जगह लगाए जा रहे है। लेकिन मेरे अपने जिले मे मेरे क्षेत्र मे पाच वर्ष से यह तकाजा है कि वहा पर एक्सपरिमेटल तरीके से कुछ रयूबवेल्स बना दिए जाय। उस के लिए पाच वर्ष के आश्वासनो और वायदों के बावजूद, मेरी प्रार्थनाओं के बावजूद, आज तक वहां पर उस के लिए कोई काम नही हो रहा है। देश मे बडे बडे काम हो रहे हैं। लेकिन रिग जैसी छोटी मशीन वहां नही दी जा सकी।

मै आप का और अधिक समय नही लेना चाहता हू मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हू और अपने विरोधी मित्रों से यह पुन. निवेदन करना चाहता हू कि अपने कारनामों से, अपने दिलो दिमाग मे और अपने रवैये मे जाहिर कर दे कि उनका विश्वास शान्तिमय, ससदीय तरीको मे है जिस से हमारे वे बिछडे मित्र जो ऊची दीवारो के पीछे निवास कर रहे है वह भी जल्द से जल्द यहा आ जायं। हम इस दिशा मे उन का सहयोग चाहते हैं। गवर्नमेंट उन को पूरी तरह से एकमोडेट करना चाहती है और इस असाधारण स्थिति को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है।

SHRI P. M. MEHTA (Bhavnagar): Mr. Speaker, Sir, we are living here under the emergency which was clamped on 25th June, 1975.

Now, Sir, this House, I think, must review the whole position—firstly, I would ask why was it clamped? The declaration of emergency was made under Article 352(1). I would like to read that Article for the benefit of the Members I quote —

> "If the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or internal disturbance, he may, by a Proclamation, make a declaration to that effect"

Two issues now arise—first of all, was there any disturbance or real apprehension of internal disturbance? To this the reply is in the negative There was no apprehension of any real disturbance There was no disturbance at all, it was absolutely imaginative I had stated in my speech during the debate on emergency in the last session that the emergency had resulted out of the creation of the fear complex, there was no danger or apprehension of the internal disturbance at all Six months have passed We have not found a single incident of any violence in the country Even to-day, to justify the emergency, they say that the danger is not over Actually there was no danger at all. So where is the question of danger being over? It is in order to justify the continuance of emergency that such statements are made.

Now, Sir, I have listened to the hon. Members from those benches very attentively and I find efforts are made by some Members to link it with Nav

Nirman movement launched by the students in Gujarat in the year 1973-74, that is, two years or so earlier. Now, they have tried to justify this Emergency by linking those incidents and that movement with Nav Nirman agitation of Gujarat by the students in the year 1973-74. But, Sir, it would be interesting to know and note that the then PCC chief of ruling party, Shri Darji, had seen Mahatma Gandhi spirit in that Nav Nirman movement. He had made a statement to that effect that I see Mahatma Gandhi spirit in this movement.

Sir, I would like to bring to the notice of this House that the whole movement was financed from the Centre because the then Chief Minister came to power against the wishes of the Centre. That is why that movement was encouraged and financed by the Centre to oust the unwilling Chief Minister. Now, Sir, I would also mention that when Shri Darji stated that he saw Mahatma Gandhi spirit in that movement no action was taken against him and he was allowed to encourage that movement. Therefore, it is futile to say it here to justify the emergency linking with that Nav Nirman movement.

Sir, some noise was created from the members sitting there about the present law and order situation in Gujarat. I would be failing in my duty if I do not apprise the House of the factual and real position as I know and which has been conveyed to the Prime Minister in the letter addressed by the Chief Minister of Gujarat. I would like to read two or three paragraphs from the Chief Minister's statement on election happenings in Gujarat. I quote:

"News agencies have issued reports of the observations made by the Prime Minister in an interview over election happenings in Gujarat

I was deeply pained and surprised to read these statements. It is a matter of deep regret that the Prime Minister of India has been receiving, and takes them as correct, so many false reports. Which part of the country may I ask is free from stray cases of untoward incidents during election times?

There is absolutely no truth in the reports that there has been violence during elections in Gujarat, that Congress workers are being arrested, their houses and belongings burnt and that Congress workers are being murdered."

I further quote:

"As the head of the Gujarat Government, I am prepared to furnish replies on each and every incident, if the Prime Minister were to give the particulars about the incidents mentioned by her in her statement and we will welcome the visit of an all party investigation committee, if the Indian Parliament appoints one, and sends it to Gujarat to enquire into the matter about the manner in which elections were held and the extent to which violence took place in the State."

Now, Sir, the Chief Minister has made an offer. He has asked for the appointment of an all party enquiry committee by this Parliament, to go into the question of violence which has been reported to the Prime Minister. Therefore, Sir, I would like you to consider this proposition of the Chief Minister and appoint an all party enquiry committee and send that committee to Gujarat. Then only, this House will know the real position. He has also asked the journalists to visit Gujarat and find out the truth, to what extent violence has taken place. Sir, I would also request you to convey this invitation to the Press.

I have also heard the hon. Members have trying to justify this Emergency and in the same breath heaping

[Shri P. M. Mehta]

calumnies on the Opposition leaders. I do not find Mr. Shukla here. Sir, I would also ask, if any of the Opposition leaders or all of them were found responsible for the subversive or the anti national activities, why none of them has been produced before the Court of Law and why no chargesheets have been framed against them? Simply, under the Emergency powers, extra powers, you are detaining these national stalwarts in jail. It is a shame on the Democratic Republic of India that the national leaders of the Opposition are under detention in jail. Sir, they have detained the leaders under MISA which is in violation of the assurance given to Shri Morarji Desai by the Prime Minister, in April 1975, in a communication sent through Shri Uma Shankar Dikshit, wherein the Prime Minister assured Shri Morarji Desai that MISA will not be used against legitimate political activities. Now, the question is, whether the Members of Parliament and other political leaders and workers were indulging in illegal activities? The reply is negative They never indulged in illegal activities What they were to do was to offence Satyagraha, by giving notice, in a peaceful and constitutional manner Satyagraha is considered to be a peaceful and constitutional means to ventilate the grievances of the people and the injustice done to them. They were to carry out that programme in June after the judgement of the Allahabad High Court.

Now here members are trying to justify the emergency equating it with the economic programme I have heard members saying that now trains have became punctual, bank clerks are regularly going to their offices at the appointed time, they say that this emergency has given discipline to the nation. Now, I would ask whether Government needs emergency powers to make clerks go punctually to the banks, whether Government required emergency powers under art. 352 for the trains to run according to the timetable. Did they require emergency powers to curb the student movement or the expression given by the students to unrest against their academic problems and the unrest of youth against unemployment? If it is so, if any Government requires emergency powers to regulate the banks, to make the clerks go at the appointed time to the banks or to make trains run according to schedule or to make the students silent, then that Government is not worth the name 'Government'. It is a useless Government and that Government has no right to run the country—if they require emergency powers for all these things. As I stated, art. 352 clearly mentions the specific reason for declaring an emergency, that is, if there is real internal disturbance or apprehension of disturbance.

Now, what is the economic situation today? Today some of the textile mills have been closed and thousands of workers are thrown out of employment It is not coming in the press because you have imposed sensorship and you do not allow the people to know about the factual and real economic position in this country. Nearly twelve mills have been closed. The same about jute mills. Thousands of workers are thrown out of employment and jute growers are not getting a due return. Similarly in the engineering industry, thousands of workers are either retrenched or laid off. In the automobile industry, the same is the position In tea plantations also, the same situation prevails This is not a rosey economic picture.

On the contrary it is good that inflation has come in check. But the Economic Survey says that again prices have started to show an upward trend. Recession has started. There is unemployment. Unemployment is in-

creasing. The workers are retrenched or laid off. But because you have held the press silent by the emergency, by the censorship, nothing goes to the people. With these marks, I conclude. Thank you.

DR. V. K R VARADARAJA RAO (Bellary): Mr Speaker, I should like not to dwell on the political aspects of the debate which we have been having during the course of a day and half. Only the speech made by my hon. friend from behind has provoked me to say one or two words on the subject of the political aspects of the emergency before I go on to deal with the economic aspects He was asking the question: Did it need an emergency to make trains run punctually, to make everybody come to office at 10 O'clock to have students go to their classes, attend them and so on?

I do not know if it was a rhetorical question that he was putting but I think that all of us who had been watching what was happening in the country during the last two or three years know, that for right or wrong reasons, I think wrong reasons, possibly based on frustration, every act of indiscipline in this country was being encouraged and no act of violence was condemned, every act of indiscipline, whether there was a strike for getting free bus tickets or a strike for not getting free cinema tickets, every kind of disorder was being supported and there was nobody from outside the Government who was prepared to take a responsible position and say: Well, we have a fight with the Government and while we want to get this Government out of power, we condemn violence and disorder; they were not prepared to condemn the happenings and movements that were going on. I think that this is something which must not be forgotten There is no good saying: why did not the students go in peace to schools and colleges and so on before? Because in those days, the movement there was some strike, irrespective of going into the fact whether it was proper, what were the reasons, was it ideologically motivated or was it ideally motivated or was it motived by some anti-social reasons, there would be support for disorder and it was the kind of support for such disorder, and the non-condemnation of violence, which brought about the kind of encouragement to the forces of disruption which, I am afraid, was one of the major reasons behind the declaration of the emergency. I have great respect for the hon friend who spoke just now and I should like to ask him to reflect on this matter and not to take what I should call a rhetorical view of the question: he should go, into it as a practical person, living in this country and working in this country.

Having said that, I should like to turn to a different line of approach. I should like to say very clearly and categorically that merely making speeches against fascism and reaction and, if I may say so, even jailing fascists and reactionaries, by themselves those steps are not going to bring about a restoration of the kind of conditions which we want, namely, economic growth mass welfare, social changes and the eventual establishment of a socialist society in this country I think we should do some deep thinking in this matter: why did those people get encouragement? Why did they think that they had a sense of power? Why did they feel that some persons were behind them? Because the economic situation was one of great distress There was inflation on a fantastic scale, inflation of a kind which we had not witnessed for as long as I can remember, after Independence There was drought; there were floods and othr kinds of economic happenings which were hitting the masses not only masses in the sense of agricultural labourers, small farmers

[Dr. V. K. R. Varadaraja Rao]

and urban workers but also the lower middle class people and large sections of urban population. There was this economic unrest and distress and the Government was making all possible effort to deal with it. I am not here to defend the Government; but this is not the forum to talk about it. Certainly if I were speaking in another platform, in an academic platmorm, I could find fault with the Government's economic policy in regard to food procurement, in regard to inflation and so on. But this is not the place for me to discuss the faults of Government. All that I want to say is that there was a national economic crisis; what we had in 1973 and 1974 was a national economic crisis; inflation was rising by 3 or 4 per cent per month. If we only look back to the years 1973, 1974, right upto September 1974, there was such an inflation: It is a party Government but it did appeal to all sections of the people to treat the economic crisis as a national crisis and stop using it for creating disruption and disorder and unrest in the country and to bring about a state of affairs which will make it possible to effectively control the economic crisis.

And they did not get this co-operation. Therefore, I want to lay down this proposition that we should turn our attention to what we do with the economic situation. If we are not able to improve the economic situation, if we are not able to increase production, if we are not able to make this country self-sufficient, if not surplus in food supplies, if we are not able to deal with the problem of poverty and sub-standard living in large pockets in this country, if we are not able to deal with the problem of unemployment, educated unemployment and urban unemployment, then I am afraid no number of speeches however vociferously and passionately made even by my own party colleagues about facisms and reaction, is going to destroy fascism and reaction. India is not a fascist country, India is not a country that harbours reactionaries. Reactionaries and facists flourish in this country only when the atmosphere is ripe for them and if we want to stop facism and reaction and have a non-violent and good society in this country, call it Sarvodaya, call it Socialism, makes no difference to me, we can do so by giving our people a better deal. If we want to have a good society and a good society in our opinion has to be a non-violent society as well, if we want to have a good society, a prosperous society in this country, then we have got to tackle the problems of the Indian economy. I would therefore like to appeal to the opposition and also to those who are speaking on behalf of the Government that while it is quite important to stress political side because I do not know about the politics, Mr. Speaker, and may be.. . ...

SHRI S. A. SHAMIM (Srinagar): That is avoiding the issue.

SHRI V. K. R. VARADARAJA RAO: Mr. Shamim is so amusing that I forget the trend of my talk. But I would like to stress that even at this stage, let us take, what exactly are we going to do about the economic situation and I think if we look at the President's Address, will find that the bulk of the President's address deals with economic situation. The bulk of the President's address gives us cause for economic hope because things have happened, I do not think they have happened because of emergency, they are not because of emergency but there is no doubt that people are far more reasonable under emergency than they were before the emergency came including the Chief Ministers of Congress States, if I may say so with all my political recklessness. For example, we have found some river disputes which had been

pending with us for almost decades and preventing irrigation and preventing the increase of food supplies have been settled. The President says:

> "Disputes between States have delayed a number of projects."

And then he says:

> ".....some projects in the Narmada basin, the Rajghat project on the Betwa River and the Kadana project on the Mahi river."

They have all been cleared and a major portion of the waters of the Godavari river has also been cleared.

Now, it seems to be, therefore, that what we should concentrate upon is this. If we want to castigate the Government, castigate them on the subject. What are we doing? How effectively are we doing? Are we trying to solve the ecenomic problems? Are we going ahead with the increase in irrigation, going ahead with the increase in agricultural production, going ahead with the increase in industrial production? Are we trying our best to see that there is more labour intensive methods employed in production so that there is more employment? Of course, nobody would ask: have you abolished poverty? Poverty cannot be abolished so easily. It is not like King Canute asking the waves to recede You cannot abolish poverty in a day, not when our 240 million people are supposed to be below the poverty line. But there is a question to be asked. Are we doing anything? Are we doing something substantial, something significant? Are we making any dent in poverty or are we letting poverty remain as it is? It seems to me, Sir, that if the debate could turn on such concrete questions of economic policies and the programmes, the country will be very much benefited. I do not know whether the country will be benefitted because I do not know what the censor does. Whether the censor understands the economics or not, the moment they see a word 'revolution' or something, then they cut the whole paragraph. I have no 'revolution' or something, then they all respect for him because he is an unknown quantity! But I am pretty certain about one thing. There is room for opposition in a democracy. I do not think the Prime Minister ever denied the right of the opposition to exist. On the contrary, she wants a responsible opposition, not in the sense of supporting the government but in the sense of making constructive suggestions and dealing with things that matter, responsible opposition does not mean interruption of the kind that sometimes Mr. Shamim makes. It does not mean witch-hunting or character assassination or talking all the time of corruption, corruption and corruption. But it does mean this: You take a particular project. You discuss whether it has succeeded or failed: how much irrigation has been brought about in the last two years; what has been the input of fertilisers; what is the increase in production and so on. These are the types of questions on which we should turn our attention if we want to make full use of the opportunities we have as a result of the peaceful and nonviolent atmosphere which we should turn our attention, ry as a result of the emergency. Let concentrate on the economic measures to cut at the roots of fascism in this country. We have seen what happened in Germany or Italy. We have seen how fascist forces have come into prominence in other countries whenever there is economic distress and no economic hope. Therefore, we should judge the record of the government by what they have done to deal with this economic problem and what they propose to do.

Even our friends in the opposition have conceded that inflation has stopped. Some are doubtful whether it has really stopped or it has just hidden

[Dr V K R Varadaraja Rao]

itself behind the curtain That nobody knows, but there is no doubt that inflation has come down Nobody talks about it as they used to do about 18 months ago But as an academic economist, I do not like the term 'negative inflation' It does not sound right in my ears What the Reserve Bank has said namely, declaration of inflation or a gradual attempt at stablisation of prices at a lower level would be more correct expression to use But by whatever name you call it, prices have come down I know this fall has not been completely reflected in retail prices, but why not mention it where it has been reflected? I stay in the university—not in New Delhi—and I meet many Class IV people For the last four years I have been asking them this question and till about 8 months ago, their reaction was very bad They used to say, "Prices are rising This Commodity cannot be had or that cannot be had" Now the reaction is, things can be had, but the prices have not fallen as much as it in claimed Therefore, we have to give full credit to the Government for the various fiscal and monetary measures which enabled them to bring down prices But there is one thing which I want to say, which fourtunately or unfortunately, has not been said by anybody as to why prices have fallen I congratulate the Reserve Bank on their latest report made available a month ago I saw a press summary and then I got the full report, which I read I am saying this for the special benefit of the treasury benches During 1974-75 we had a net inflow of external assistance of Rs 480 crores and withdrawals from the I M F to the tune of Rs. 485 crores giving us a total financial inflow of Rs 965 crores as compared to Rs 316 crores in the previous year

The Reserve Bank Report says: "Clearly without the contribution of this massive dose of external assistance, the impact of monetary and fiscal policies to containing the rate of growth of money supply would have been much less effective" We have done a very wonderful job, better than any othr country in the world. In other countries, 8 per cent or so rate of inflation is still going on and we can hold our head high in all international bodies because we have control on inflation. In this control on inflation, we have had to rely on large loans from the IMF apart from increase in external assistance. The Reserve Bank of India has forecast a better outlook for 1976-77 The Aid India Consortium has promised larger amounts than they did in the previous years. The oil facility is still there and, therefore, we will not have any constraint on our policy because of lack of foreign resources Sir, I think, this is a good thing as far as reality is concerned But I ask how long can we rely on foreign resources because we have to pay back What we get from the IMF has to be paid back What we get from private sources has to be paid back Sir you know very well because you are a distinguished student of economics that something like 30 per cent of our exports have been going for merely servicing the debt payments and quite a big part postponed by the re-schedulmg which we have been able to effect Therefore I want to strike a note of warning that we cannot allow our economic growth and economic recovery and the satisfaction of our economic needs to lean so heavily continuously on foreign loans or foreign assistance I do not say we should not take foreign assistance If we have no choice, we should do it. I am glad, we did it But how do we do away with foreign debt? How do we reduce the payment of foreign debt? I think it is a question which is important Why should we have deficits in our balance of payment? Last year the deficit in balance of payments was of the order of Rs 1096

crores as compared to Rs. 402 crores in the previous year I understand, again there are expectations that in 1975-76 the deficit will be a little large and certainly not smaller than Rs. 1096 crores in the previous year. Why do we get this big payment deficit? It seems to me that this is a matter on which we should concentrate lot of our attention within the party, within the government and within the Parliament. And if we do that, we will know that it is mainly because we import foodgrains, we import fertilisers and we import oil. These are the three major things which are responsible for this big deficit.

About oil, I would not say anything because we are doing our best. Oil cannot be produced by reciting mantras. Oil has to be found and it takes time. Fortunately for us, the expectations are that in another four or five years the position would be better because of Bombay High and because of possible discoveries both in the East and in the North particularly in Jammu & Kashmir. But about food. I would really ask: why are we importing food? How long are we going to import food? Already, people are telling me; yesterday I heard people telling me: "You know, we are worried." He was not a Minister; he was an ordinary person. Why were they worried? They said: "Rains should have come by now. Rains have not come. Therefore, we do not know what will happen to the rabi crop." I said: "Why? we had such a good monsoon. All the rivers are full; all the reservoirs are full and all the tanks are full." He said: "Yes, may be; that may be so in the South; but in the North, there are many places where there are more tanks; and where water is required at a particular tank. if rain does not come, the rabi crop is going to be affected." In other words, we are still depending upon rain. I think once upon a time Rajaji described the Communists as the major enemy. I do not mean that. They may or may not be. I am expressing no opinion on that; but I would certainly say that the rain god—I would not call him an enemy because I am afraid—is a person who determines my destiny. A long, long ago, I think the first Finance Minister of India, Mr. James Wilson in 1860 had said that the Indian budget was a gamble in rains. And the Indian economy seems to be still a gamble in rains. I would say: let us go all out, let us go all out at any cost to see that our food production, (a) increases and (b) (*Interruptions*) ... Sir, would you like me to conclude?

MR. SPEAKER: Please continue.

DR. V. K. R. VARADARAJA RAO: I would say that the major economic problem that we should tackle is the problem of food. In another place, I even went to the length of saying, some what stretching my neck out—I hope my friend Mr. Chandrajit Yadav does not consider that I am saying something which is wrong—that we would rather imoprt steel, then imported food. If we have to import anything, I would rather import steel than import food. Once I have my food, once I am surplus in food and once I am not dependent on food—apart from balance of payments and foreign loans and foreign assistance—my position, my moral position, my economic position and my strategic position in the international world becomes very much stronger, than if I do not have my own food: and a detailed programme for it, this is not the place to discuss about. I would say that the recent agreements are a welcome step. I am glad that the 20-point programme has a very important item on 5 million hectares of land to be brought under irrigation. I think within the next five years. I do not know; when people are talking about the 20-point programme—I have forgotten it, even though I have read it several times; I went back and referred to it—they talk only about distribution, bonded labour, moratorium on debts and so on.

[Dr. V. K. R. Varadaraja Rao]

But the 20-point programme is a programme essentially with an accent on increasing production. I want to make that clear. The 20-point programme is not merely a populist programme. It is not a programme merely for helping the weaker sections Of course, it wants to help the weaker sections To the extent we can, we should try and do that. No question about it But essentially, the 20-poin programme has emerged with an accent on both agriculture production and industrial production. Therefore, when my friends say that they were all for the 20-point programme—not only my friends who are represented in this House, but even my friends who are not fully represented in this House—I would like to understand it. Almost within a few days of its declaration, a delegation led by the most important industrialists and businessmen came to the Prime Minister and said that they were all for the 20-point programme. I am still to find someone who is against the 20-point programme. Everybody is for the 20-point programme But what happens is this, like the six men looking at the elephant..

MR. SPEAKER: I think the hon Member will continue after lunch The House will now adjourn and meet again at 2 P.M.

13.00 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENTS ADDRESS—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Rao may continue. Only five minutes more. He will please bear that in mind.

SHRI S M BANERJEE (Kanpur): Yesterday I requested this House and also the Business Advisory Committee.. .

MR DEPUTY-SPEAKER: Then, why bring it up here?

SHRI S. M. BANERJEE: Thousands of workers have recently been declared laid off or retrenched, and closure is going on. Today I got the news that in a place like Kanpur 13,000 workers have been laid off. The hon. Prime Minister herself has stated that some remedy must be found for this I would, therefore, request you to ask the Minister of Labour to make a statement

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore) Very important.

DR V K R VARADARAJA RAO (Bellary) I was mentioning this morning how the twenty point programme was being looked at I said I was reminded of the story of six people who described an elephant each differently The story is known to everybody. One concentrated on the trunk, another on the tail, a third on the legs etc I want to say in all earnestness before this House that the 20-point economic programme is a balanced integrated programme It cannot be taken apart by bits and accepting only what one likes and discharging what one does not like. It is a programme for increasing production, agricultural production and industrial production; it is a programme for trying to see that prices remain stable by a system of organising public distribution; it is a programme for bringing social justice, especially to the most neglected sections of the Indian population who live in rural areas. The whole gamut of programmes like abolition of bonded labour increasing agricultural labourers' wages, housing, distribution of surplus land, is intended to do something for the most disadvantageous classes in the rural areas in our country. If I may say so, if this programme is implemented, it is going to break the

current rural power structure which is one of the biggest impediments in the way of social transformation of our society. Therefore, it is very important that this rural programme is implemented. I find that my business friends are for implementing the rural programme. But when it comes to their own programme, they say that they accept the 20-point programme but where is the workers' participation. I have still to read, unless the news has been censored, the programme of the big industrial companies, private sector, the big houses where they are having workers' participation, giving workers a sense of not only participation at the floor level, but also in the decision making, management, product-mix and so on.

Similarly, if I may say so, as I said this morning, rightly or wrongly, as long as our exports do not increase sufficiently and our imports do not decline sufficiently we are dependent on the loan from IMF and other foreign agencies—I do not want to use the word 'Aid'. If that is so, we cannot afford to go and quarrel unnecessarily with all the people from whom we expect to receive loan. I do not say we should not quarrel with them when it is right to do so; and in that connection, I very much regret, if I may say so with great deference my respected friend Mr. Indrajit Gupta, yesterday made a reference to Iran and objected to the signing of the Kudremukh project. On this project, the whole Karnataka depends for its economic growth. Apart from that, Iron is a country from whom we are importing a lot of oil which is playing a very important role in the production of fertiliser in Madras So far as I know, I am not a student of international affairs, Iran is a country with whom we have good relations, economic relations and is also a country that needs our economic and good relations. Strategically, it is also a somewhat difficult position. Therefore, I suggest that when we come to the programme, le us understand that it is a programme taken as a whole. Let us not try to ditch the bout. Our economy is just recovering from a crisis, thanks to the firmness shown by the Prime Minister in imposing an emergency, because without that, I doubt very much, if we could have an atmosphere and the will and all other capacity for doing some of the things which we have been able to do. The economy is now getting a break-through; it is on the verge of a break-through.

We also know, for example, as compared to the rate of growth of last year, in 1976, it is going to be higher. Our infrastructure facilities have increased. There is more power, more water more power supply, more supply of agricultural labour, more foreign exchange and more discipline all-round in the country. There are no strikes, no *harta's*. My friends in the Advisory Committee talked about recession I told them in Bombay the other day that after all some prices had to fall If the workers can accept a cut in their bonus, if many agricultural labourers and others can live on the sub-human standard of living and if they are not in a position to do anything immediately, why should the businessmen think that their profit has to remain where it was remained before. After all, reduction in profit is as much a part of the emergency as reduction in other disbursible incomes, because we want to save more and invest more

Therefore, I would like to suggest that if all of us take the 20-point economic programme as on integrated whole one and not pieces out of it, I think the party must move to break the rural power structure and go all out to implement the reforms in the countryside

I think, the country must go all out to see that the production is increased; the business community has got to go all out to see that it increases production. Actually, the things are rather better now.

[Dr. V. K. R. Varadaraja Rao]

About recent disclosures—I am not too sure if I am very much in love with the morality behind it; the morality is not something which can bring an unqualified passion in the political, economic and industrial world—it has been a grand success. It has reached a figure of Rs. 1500 crores. My guess is, out of Rs. 1500 crores, at least Rs 750 crores will be concealed income and Rs. 750 crores will be concealed wealth. I am not so much bothered about the fact that you will get about Rs. 250 crores or Rs. 300 crores to the Central Exchequer. But so much money has been legitimatised. It can go into trade; it can go into industry; it can go into investment. It can break the back of so-called recession. That is again a good point on our side.

I want to end my speech on a very optimistic note as far as the economy is concerned. I think, the economy is really, for the first time, after several years, not excluding the good harvest of 1970-71, on the verge of a breakthrough. If it breaks through, we need not be afraid of the reactionary forces; we need not afraid of fascist forces; we need not be afraid of trouble makers and violence-*walas*. If the economy breaks through, if there is increased production, better distribution and stabilisation of prices, we need not be afraid of all these forces.

In conclusion, I would urge upon all my colleagues both on my side and on the opposition side, irrespective of the personal and sectional grievances, to treat this 20-point Economic Programme as a national cause and an integrated programme and go all out to see that the economy recovers and, by the time we come to the next year, we will be having the General Elections and there will be a fresh opportunity to the opposition to come in large numbers.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): Mr. Deputy-Speaker, Sir, after the speech made by Prof. V. K. R. V. Rao, I have been called to speak. When Prof. Rao began his speech, he complained that most of the speeches made in this House were pertaining only to the political aspects and that the economic aspects had not been dealt with as much as they deserved. For a change, I will start my speech from the economic end

As Prof. Rao rightly pointed out, the 20-point Economic Programme has been unanimously and universally welcomed by every section not only inside the House but outside also. We also welcomed it. Not only after Emergency but even earlier, before Emergency, whenever any economic programmes were brought in this House or outside, my party has been very enthusiastically supporting the progressive measures.

This 20-point Economic Programme dominates the scene in the political life of the country today. I do concede that the slogans create enthusiasm, focus the attention of the people, give directions to the people and also prepare the country and the economy for better days. But I doubt very much if by themselves they can solve the problem If words were to fulfil our requirements, our country should have been the most prosperous under the sun.

After announcing the 20-point Economic Programme, more than six months have elapsed. By the week end, 200 days would have been over. At this stage, I want to know what the plan of action is to implement the 20-point Economic Programme I have gone through the President's Address very carefully. I find that the word "Five Year Plan" does not find a place anywhere in this Address. The only thing it talks of is Annual Plan, not the Five Year Plan When the idea of planning was mooted in the country in '50s, when the country after Independence decided that development can be brought about only by planning, not by giving a free hand to anybody who wants to produce or distribute, when this idea was mooted by late Pandit Jawaharlal Nehru, he said that

by process of planning, we should bring up the standard of the people in this country. Accordingly, the Planning Commission was set up with which our learned Prof. Rao was also associated very intimately. In 1950, when this idea was put through, the objectives were laid down (1) that the citizens should have adequate means of livelihood, (2) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subverse the common good, and (3) that the operation of the economic system does not result in concentration of wealth and means of production to the common detriment

After this, we have had four Five Year Plans In the Fifth Five Year Plan also, which has been approved and should have gone into implementation the very first sentence of the Draft says·

"Re noval of poverty and attainment of economic self-reliance are the two strategic goals the country has set for itself."

I would like to know how the twenty-point programme is going to be dovetailed into the Plan already made —whether we are going to keep to the Fifth Five Year Plan or going to attend only to the 20 point programme Now, we may feel frustrated that the Plans did not come up to expectations and the twenty-point programme may be a departure from them But even then, we must have planed action as to how the twenty-point programme is going to be out through. In implementing some of these things They may not be put in the regular Plan document itself. For example, fixing of minimum agricultural wages--which is point No 6 in the programe—, abolition of a bonded labour, (Point 4 confiscation of smuggled properties (Point 13), Income-tax Relief (Point 17) etc. may be done even without having a regular plan, but there are many other things which have already been put in our Plans since the First Five Year Plan: for example, land ceiling has been there from the First Five Year Plan. What happened to it? Where did it fail? Where did the Plan or the Government fail in fulfilling the targets and objectives set forth as early as in the First Five Year Plan?

Item No 7, you will see, relates to land to be brought under irrigation— to which Prof Rao also referred. It has been proposed to bring under the twenty-point programme, five million hectares land under irrigation. If you look at this Ffith Fve Year Plan, in Chapter III, para 11, p. 106, it has been stated·

"During the Fourth Plan, it is anticipated that Rs. 1170 crores would have been spent in the major and medium irrigation sector and the additional potential to be created is expected to be 3.3 million hectares. As compared to this, a substantially higher outlay of Rs 2401 crores and a target of 6 2 million hectares are being aimed at during the Fifth Five Year Plan."

So, the Fifth Five Year Plan has planned for 6 2 million hectares and now the twenty-point programme has reduced it to five million hectares! I am not worried even about that; but what are the resources? Even for achieving this twenty-point programme what is the plan that we have evolved? I would like to know whether we have set out priorities on the basis of this, whether we have ascertained the enormity of the problem under each of the points of this programme, whether we have assessed the resources available to us, whether we have fixed up a time bound scheme for each, whether we have located and removed the handicaps in our plannng all along wherever we have failed, and whether we have allocated the necessary funds

SHRI M RAM GOPAL REDDY (Nizambad): We have removed all obstacles.

SHRI SEZHIYAN: I would like to know what the obstacles were and how you have removed them (as he has answered on behalf of the Government, I expect him to give an answer to this also) and whether effective implementation and follow-up will be there in the twenty-point programme.

It is good to create enthusiam in this country, to focus the attention of the people and to set priorities but, in the long-term perspective, how are we going to implement them? We should come to brass tacks.

Now I come to Emergency on which many hon. friends, both on this side and on the other side, have spoken. Emergency was imposed on 26th June, 1975, as you all know, and the 20-point programme. Emergency, as its very Emergency is sought to be continued for implementation of the 20-point programme; Emergency, as its very name suggests, is for abnormal conditions. We would like to know when normalcy is going to come, how to know that the normalcy has come and the Emergency should end When somebody starts on a 100-metre dash, if he is asked to go on a 30-kilometre long distance run, either he will not be able to keep up the same speed or if he keeps up the same speed, he will not be able to reach the goal and may collapse in the middle quite exhausted. For good or bad, for ill or well, you say that the Emergency has produced good results. But what is the guarantee that the means that have been opened now, that the floodgates that have been opened now, will not be utilised in future by somebody who does not use these things to obtain good results? Where is the guarantee that these things will not be utilised by people for their own ends in a despotic or undemocratic way?

I concede that the provision for Emergency is a must in any Constitution worth its name; no constitutional government can function without the provision in the Constitution, if it is a written one, for Emergency. But, because it is to be done only for a temporary period, the people and the constitutional government accept to for go their rights. The constitutional government itself gets restricted and the rights of the citizens are suspended and these rights are to be resumed once the Emergency is over. There is a famous maxim by Cicero, "*inter arma silent leges*", that is when there is clash of arms, laws become silent. In a democratic country, Emergency can be proclaimed and continued, perhaps with the best of intentions. But where is the check? Who is to say that the Emergency is not there, that the conditions of Emergency do not prevail any longer and that the Emergency should be lifted?

I will quote only two classical systems of Government which we follow or try to follow. One is U.K.'s which we try to adopt to the extent possible, to the best of our genius. In U.K., the Parliament has got the power, the Sovereign does not have, Parliament endows the Executive with powers to interfere with the most cherished rights of citizens which may be necessary and proper in a grave national danger. But, there, the courts go into the cases of abuse, *mala fide* use of power and where there is *prima facie* wrong application of the power. During World War I and World War II, courts were never barred to any aggrieved party, anybody could approach the courts against any *mala fide* use or wrong application of the powers, even in the heat of War, in 1942, there have been cases of detenus—persons detained by the Government—being released by the courts in U.K

In the USA there is the Presidential form of Government there, the President does not have the power, it is the Congress which has got the power to impose conditions in times of emergency, to prevent filling in court the writ of habeas corpus; but it is for the courts to determine whether conditions have arisen to justify suspension of the rights. Therefore, we have got another party there to decide this.

My basic approach or appeal is this. You may change the Constitution in any way; whether it is Parliamentary form of Government or Presidential form of Government or any other form of Government, as long as you have a written Constitutions—of course, there are countries where they do not have fully written Constitutions and where democracy thrives. I am not on that question—what does it mean? Having a written Constitution itself means that you are putting limitations. After all, why do you want to have a Constitution? You want to have a Constitution because You want to put limitations on the functioning of the Legislature and the Executive. Whenever there is a trespass or whenever there is an encroachment by one sector into another, who is to decide? There comes the judiciary. As long as you provide for a system of Constitution or Government—whether it may be, whether it is as in the USA or in the UK, I do not have any quarrel—please see to it that there is an independent body which checks; if the Legislature goes beyond its limitations, there should be some checks; if the Executive goes beyond its limitations, there should be some check on that. That is what we call the rule of law and impartial judicial review.

The majority rule alone cannot decide what is just or not Gandhiji himself while writing in *Young India* on 26-1-1922, rightly said:

> "Claiming the right of free opinion and free action as we do, we must extend the same to others. The rule of majority when it becomes coercive, is as intolerable as that of a bureaucratic minority. We must patiently try to bring round the minority to our view by gentle persuasion and argument."

Therefore, democracy has to be governed by discussion not only inside the House, but outside the House also. Hence my demand for a round-table Conference for discussion with all leaders.

Whatever opinion is formed about the functioning of a democracy, as rightly pointed out by the learned Professor, criticism should be welcome as long as you do not incite violence, as long as you do not lead to violence, and as long as that does not lead to any extra-constitutional measures. My point is that if any speech leads to violence, leads to extra-constitutional measures, put that person in the court.

Regarding the majority rule, Pandit Jawaharlal Nehru also said:

> "With all my admiration and love for democracy, I am not prepared to accept the statement that the largest number of people are always right."

The largest number of people sometimes in their anxiety to do the best of things may act and go in the wrong way. That is why, we always rely on a measure that is the rule of law and the independent judiciary.

Once Aristotle said,

> 'Man, when perfected, is the best of animals, but when separated from law and justice is the worst of all."

My plea, therefore, is that whatever you plan is not going to be there for the day, is not for this year or for this Lok Sabha alone; it is going to bind the coming generation The directions that you give, the basic alterations that you suggest are going to be imprinted in the political history of our country for the future citizens. It is said that the politician looks at the next elections, whereas the statesman looks at the next generation. I know, you are all very eminent statesmen. As you are, you should see the shape of things to come. I do not expect the same sort of good people to adorn this very House. After all, man is mortal. Whenever you do these things, think of the possibilities of abuse Even now you may not be aware, what the distant bureaucrat, or the distant officer may do. The officers who clamp the censor may allow one thing to be published in one paper; if the same thing is published in another paper, they simply strike it down. I cannot go to any court or anywhere.

[Shri Sezhiyan]

Whenever you think of any constitutional change, or implementation of the 20-point programme, whenever you want to use the emergency powers or the extraordinary powers to protect the sovereignty, that very instrument should not be used to thwart and subvert the very Constitution itself and the democracy in this country

I would also say to the Members here that you have been associated with a very glorious record of freedom movement, you have been trained more than I under Gandhiji, and you have been associated with Pandit Jawaharlal Nehru. All these people have left a very rich legacy—a legacy to the nation, a legacy to the present generation. The same legacy we should be able to pass on untarnished though not enriched in a great measure, to the coming generation

I would quote from an erudite scholar on the legacy that has been left to us by Pandit Jawaharlal Nehru It has been said:

> "An essential ingredient of the new India of Nehru had to be political democracy Free India could not, therefore, be a dictatorial India or an oligarchic India or a feudal India And in political democracy, he included free speech and free press, civil liberty, adult franchise and the rule of law"

This was said in one of the very good books brought out in recent years. 'The Nehru Legacy' by Dr. V. K R. V. Rao. Therefore, I appeal to him. I rededicate the rich legacy to him and others in the House and ask whether or not he is going to accept and continue the free India founded by Jawaharlal Nehru wherein he wanted free speech, free Press, civil liberty, adult franchise and the rule of law

SHRI SYED AHMED AGA (Baramulla). I want to associate myself with the Motion of Thanks to the President for his Address.

The President said in one of the paragraphs that there is a continuing challenge of forces of disruption and that the nation should remain vigilant and disciplined. In this context, I feel that the emergency has to remain because the danger is still there. I feel that the vested interests are very much afraid of any change in the socio-economic structure. I again feel that the forces of external disruption are active. I am reminded that when the Ananda Marg was banned, foreigners came to man it and they even shifted the headquarters of the organization to Bangkok and also operated at Calcutta I also learnt from the papers sometime later that there was an international religious organization which has also come to Calcutta whose members believe in Hindu Gods It is significant that foreigners should come here from far off places telling us that they believe in our Gods. Can't they find God in their own country? If they want to become Hindus, what prevents them from becoming Hindus and following Hinduism in their own country On the other hand, coming to Calcutta to find spiritual satisfaction is significant This is rather intriguing

Then, Sir I am reminded of a magazine by name *'Watch Tower'* which is printed in 78 languages and prints something like 9 700,000 copies from Pennsylvania and Philippines. This magazine says that nations should surrender their sovereignty and accept an authority that could tell them what they should do in international affairs It is very obvious who wants this Aga n I became suspicious about all these things when I read that the Chairman of the Theosophical Society, Shri Sriman Narayan said more or less the same thing. He said that there should be a world government to which individual nations would surrender their sovereignty All these things put together would make one feel that we should be vigilant because all these things are happening in a covert way' Perhaps he might have said in an honest way that there should be an

world government but, read with the *'Watch Tower'*, it has a different meaning in actual practice. So, because of these things I feel that the emergency has to remain so long as the external dangers are there.

I feel, there are powers who do not want that we should be self-reliant or that India should emerge as a country that matters in the World Comity.

Our non-alignment policy has made us great under the very dynamic leadership and guidance of Madam Indira Gandhi who has very much become—the leader of the non-aligned countries.

We have sided with and we have always talked of African unity We have also said that Arab land occupied by Israel should be vacated We have favoured the Palestinian cause. We have favoured the just cause of 'still to be liberated' countries We are therefore not liked and, therefore the campaign is there The danger is there and we have got to be alert

They have not liked our launching Aryabhata, our emergency strong

When King Faisal used oil as a weapon, he was assassinated We also know that only last year Mujib was instrumental for Dacca declaration for Asian security where 27 countries had participated. We then found that Mujib was assassinated. We should therefore know that these are not accidental things. We know that the U.S. Ambassador in Bangla Desh at the time of assassination of Mujib was Mr. Davis Boster, who was Charge-d' Affairs in Chile at the time of assassination of Mr. Allende. Again I say that when American senate exposed CIA, President Ford did not condemn assassination and never said 'stop it'. He only said, avoid assassination.

Again on 30th December, 1975, I read in the paper a few days ago that there was a threat to kill U.S. politicians and Chairman of the Committees of Investigation into CIA working. They are not going to spare their own people.

In 1961 there were 3,700 intelligence men working under diplomatic titles. We do not know how many are working in our country. We also see that many religious organisations from outside help the various religious organisations here in India What I want to stress is that Government should have a sort of audit check on the money that is received by the various religious organisations here. They must also see as to how the money is spent by them

All this is happening when in Japan throwing of dummy atom bomb is being practised. We also see that the base Diego Garcia has been built as a very great offensive base. We also see that the Gwadar base has been built at Makran coast. They are almost controlling our oil channel. We have got to be vigilant that way. We have to devise ways and means so that our Bombay high receives very great attention

We also see that the Chinese are provoking at our northern side. We also see that implementation of Simla Agreement is slowing down. We also see that the Indian navy—I read two days ago—is under constant surveillance by some foreign power by long range aircraft.

When all these things are there, I feel that we have got to be vigilant.

The Simonstown can see the Bay of Bengal on its radar. China and USA had asked for bases in Chittagong and I don't know whether they have got it. Sir, in the General Assembly of the United Nations, the Chinese spokesman said that he feared that there may be a third world war. When all these things are going on, we cannot be less vigilant. We have got to be more and more vigilant.

[Shri Syed Ahmed Aga]

In respect of our economy, we have got to see that the inequality is not more pronounced We have got to see that the 20 point programme of the hon Prime Minister is implemented properly and in a satisfactory manner It cannot be implemented unless people's participation is there unless people are associated with it This is a must Unless people are associated the implementation of the 20 point programme may not be that perfect If the Constitution becomes a hurdle in removing inequalities and disparities, we should review the constitutional provisions and the Constitution should be amended if necessary We must remove the economic disparities and this is a must We must see also that there are no lockouts and lay-offs in private sector We must also see that the Report of the Hathi Committee is implemented because the drug industry is in the hands of multinationals and they must be taken over With these words Sir I think you for having given me the permission to associate myself with the Motion of Thanks on the President's Address

SHRI K MANOHARAN (Madras North) Mr Deputy Speaker Sir let me start my speech by quoting a relevant portion from the Narora Document of the Congress I quote It says

> 'The basic question is whether the process of social and economic changes will take place within the matrix of democratic institutions or whether the vested interests would succeed in thwarting the process of change by imposing their will on the masses through extra Constitutional means.'

In para 36, the President has expressed this view and I quote

> 'Honourable Members In view of the uncertainties of the International situation, especially on our subcontinent and the neighbourhood, the continuing challenge of forces of disruption at home and the need to accelerate our social and economic programmes the nation should remain vigilant and disciplined There must be constant effort to improve performance and bring about changes and reforms in every sphere of national life

Before me, my friend Mr Era Sezhiyan made a philosophical speech today Before that, my friend, Mr V K R V Rao the learned professor, spoke I listened with rapt attention to these two speeches Professor Rao said that if there is any economic breakthrough then we need not worry about the fascist and reactionary forces in the country My humble submission to Prof V K R V Rao is this Unless and until the reactionary forces are crushed completely we cannot have an economic breakthrough and political stability in the country

Now I want to draw the atention of Mr Deputy-Speaker and thereby, the House that we are passing through a critical stage we have democracy and democracy is our creed, it is a way of life and we accepted democracy because of two reasons as a constitutional pundit Mr Fauser pointed out and I quote —

> Two cheers for Democracy one because it admits variety and two because it permits criticisms"

That is why we welcome the democracy for our country Now coming to emergency why and what for was it proclaimed It has been amply clear and explained to the nation at large not only by the Prime Minister but by the responsible political parties and responsible leaders Of course emergency is a kind of cruelty no doubt. It is like a scalpel in the hands of a doctor for operating a patient for his life but not to kill him That is precisely why this emergency has been declared; it has been declared to discipline the country The process is going on in this country, but the disruptive forces which have gone under ground are trying to undermine the

basic structure of our democracy, the infrastructure of our Parliamentary democracy is being threatened not only by the fascist forces inside but in collusion with the fascist forces outside the country as well—I do not like to mention the names of those countries But it is very clear to anybody that the imperialist forces and their 'Funkies and toadies', in collusion with the reactionary forces here, are determined to see that Indira Gandhi's Government is completely demolished and thereby they can introduce chaos and confusion in the country and out of which they want to do something That is why we think that the Prime Minister, Indira Gandhi very rightly, has taken this step of introducing the emergency Whether this emergency will be there till eternity or whether it would be lifted, this question has been put by my friend, Shri Sezhiyan, it is not left to him to be a competent authority or to Shri D K Barooah of the Congress party to decide The Prime Minister of this country is the only competent person who can judge the situation whether the emergency is to be lifted or not So, we are hoping that when normalcy is restored, everything will be all right I now want to draw the attention of the House to one thing Much has been said about the constitutional changes So far as we are concerned, we think that the Constitution must be a living document and it must reflect the true spirit and aspiration and the rising expectations of the people of the nation, Constitution is not only a mere scheme or arrangement to regulate the administrative, political economic and social activities but it is a forward looking instrument—a powerful weapon—to abolish the larger pockets of poverty existing in the midst of plenty The Constitution must be flexible and it is amendable I do not consider the Constitution as a Bible of the nation or the Quoran of the country or Bhagwat Gita of the nation. Constitution is there to see that there is transformation in our society and economic regeneration for which we must change it.

The Prime Minister has said that she was for changes in the Constitution. Certain objections from certain quarters came. What sort of changes does the Prime Minister want to introduce? Certain people are saying that the basic structure of the Constitution should not be touched The fundamentals of the Constitution should not be allowed to be changed So far as I am concerned I am not bothered about the basic structure or the fundamentals of the Constitution, I am more concerned about the basic needs or requirements of the needy people of this country

If any constitution stands in the way of achieving our laudable objectives then without any sense of remorse and mercy that constitution should be thrown lock, stock and barrel in the Arabian or the Indian ocean Before concluding that part of the aspect I request the Prime Minister to come forward and spell out what sort of changes she wants to introduce in the Constitution For her my suggestion is that she must have a conference of constitutional pundits and political leaders wherein these changes must be placed for discussion and dialogue After that we can conveniently have our constitution changed and the constitution reshaped.

Next, maybe this point might be unpleasant to some but I must bring to the notice of the Prime Minister, that is about language issue. So far as the President's Address is concerned it is silent. There is a lurking doubt or apprehension in the minds of the people in my part of the country that Hindi is being cleverly imposed on the people of non-Hindi speaking areas. This is against the spirit of the assurance given by late Pandit Jawahar Lal Nehru. In the year 1959 he said: The question of Hindi must be decided not by Hindi speaking people but by the non-Hindi speaking people. In the year 1962 the same assurance was repeated by

[Shri K. Manoharan]

the late Prime Minister, Pandit Jawahar Lal Nehru. In the year 1971 the illustrious Prime Minister, Pandit Jawahar Lal Nehru's daughter, the illustrious Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi gave a positive assurance in the House that it will not be imposed on the non-Hindi speaking people. Recently in the defence consultative committee meeting while I raised this issue she again promised that it will not be imposed and the apprehension according to her own words is baseless and unfounded. She said, "You need not have any apprehension at all." Then in order to reaffirm the faith I once again asked: Shall I take it as an assurance from you? She said, "This is my assurance."

In spite of all these assurances, I am sorry to tell that without her knowledge some people in different Departments and the Ministries are creating and doing some mischief. Some circulars are being sent where the stink of imposition is there. I think these people are creating some impossible conditions for the Prime Minister or to put her in an awkward situation thereby to create some sort of ill-feeling against the Prime Minister from the non-Hindi speaking people. So, I request the Prime Minister that she must intervene and see that the apprehension is completely removed and thereby we must concentrate on the 20-point programme announced by her. While the country is passing through a difficult phase for heaven's shake let us not bring controversy so far as the language issue is concerned. Let us leave this matter to the future generation to decide because we are not competent enough to decide this issue at present.

Lastly, Sir, emergency is being opposed very cleverly by my friend, Mr. Sezhiyan. The same speech must be addressed not to the Prime Minister of India but to the Chief Minister of Tamil Nadu. I tell you one thing.

AN HON. MEMBER: Because he imposed emergency.

SHRI K. MANOHARAN: What he cleverly did is he opposed emergency on the one side and on the other he is utilising the emergency provisions to curb the rights of the opposite political parties and periodicals, journals and what not which publish the factual political situation of the country. Shri Viswanathan, MP, was also arrested. There is such a mis-use and abuse of powers in Tamil Nadu. Not only that. I would like to say this for the information of the Prime Minister. If any Member of Parliament comes to Madras—I can be his translator or anybody can be his translator—he will see what are the things written on the walls. 'Indira Gandhi is a fascist.' 'Prime Minister Indira Gandhi is a fascist.' 'Indira Gandhi is a dictator.' 'Democracy is being raped.' These are the types of slogans written on the walls. Not only that, Sir. I am very sorry to tell you that in order to create confusion in the country, one fine morning, I see a poster saying 'JP is dead.' Clandestine pamphlets are being issued criticising the Government of India and criticising the imposition of Emergency.

SHRI C. T. DHANDAPANI (Dharapuram): This is all done by the MGR party to malign the DMK.

SHRI K. MANOHARAN: We can show the publications. Pamphlets after pamphlets are being issued. But, these people have no cheeks to mention the name of the press. Without mentioning the name of the press, these clandestine pamphlets are being printed and distributed to various countries of the world through their Embassies functioning here. I can prove this.

The second thing which I would like to mention is a very important thing. The Prime Minister should not take it very lightly. We have already submitted a memorandum to the Prime Minister as well as the President to see that the (Tamil Nadu) Government is streamlined. So many charges have been levelled. I think all the documents are conveniently sleeping in the Home Ministry or somewhere else. I am not worried about it. But, what I would like to say is this. There is an impossible situation in Tamil Nadu. Emergency is not to be found at all. Law and order situation is out of control. My friend, the Organiser of Anna DMK South Madras, Mr. J. P. R., was arrested under MISA. Of course, no reason has been assigned. But, he is still behind the bars. Here is a very interesting and important point. Had the Tamil Nadu Government any sense of shame, elementary sense of shame, after the Chingleput judgement, after the Magistrate's pronouncements, it would have resigned. I will explain the circumstances. While the Chief Minister of Tamil Nadu was visiting Chingleput, which is 35 miles away from Madras, a black-flag demonstration was organised. Why was it organised? I will tell you the reason.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. I have almost given double your time.

SHRI K. MANOHARAN: Thank you very much for your generosity! I am on my last point. A black-flag demonstration was organised. Do you know why? When Mr. Jayaprakash Narayan came to Madras, the Congress Party, the Youth Congress, organised a black-flag demonstration. These people were brutally beaten up—shall I say—by the DMK-employed goondas. In order to protest against that, the leader of the Anna DMK, MGR said that wherever Karunanidhi goes, we should express our dis-satisfaction by waving black-flags. It was very peaceful. But, the Treasurer of my party, Mr. S. M. Dorairaj was beaten up and he was taken to the hospital with head injuries. So many Anna DMK members were arrested. They were helpless. After having done all this, false cases were foisted on them.

15.00 hrs.

This is a judicial pronouncement:

"The Chief Judicial Magistrate observed that the materials placed before the Court led him to suspect very strongly that the Inspector of Police for reasons best known to him and without properly investigating rushed to lay a charge-sheet against the accused leaving the real culprits....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Vidyalankar.

SHRI K. MANOHARAN: Let me conclude. Then only it will be a total one.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is crossing the limit.

SHRI K. MANOHARAN: "The very fact....

SHRI C. T. DHANDAPANI: May I quote another thing?....

SHRI K. MANOHARAN: I am not yielding.

"The very fact that the Inspector rushed to lay the charge-sheet even without examining the accused, who had to be sent to the Government General Hospital, Madras, on account of his dangerous condition indicates that the Inspector was not interested in fair investigation but was bent upon charging the accused somehow. It is not known what prompted him to act like that.

"Those who were attacked had been brought before the Court as accused, leaving the attackers, who

[Shri K Manoharan]

took law into their own hands, to go scot-free "

MR DEPUTY-SPEAKER Shri Vidyalankar

SHRI K MANOHARAN I must conclude I am concluding

MR DEPUTY-SPEAKER You can conclude in one sentence

SHRI S A SHAMIM Mr Vidyalankar will conclude on his behalf

SHRI K MANOHARAN This is the judgment This shows very clearly how false cases are being foisted on us Therefore I am requesting the Prime Minister I am not requesting her to dismiss that Ministry through the President—I am requesting her for heaven's sake after the expiry of the term of that Assembly under the Constitution not even a single minute should be allowed for the D M K Government to continue I hope the Prime Minister would help us in that

SHRI S A SHAMIM The same should be done after the term of the Parliament here

SHRI K MANOHARAN I hope she will do it

SHRI C T DHANDAPANI After he becomes President!

SHRI S A SHAMIM You have not given him enough time He had so much of material

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष जी, डी०एम० के० माननीय के सदस्य ने सवाल किया था कि यह इमरजेंसी कब खत्म होगी। उनका कुछ जवाब तो अभी अन्ना डी०एम०के० के माननीय सदस्य दे चुके हैं उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इस बात का जिक्र किया है कि इमरजेंसी आखी कैसे। जो हालत इमरजेंसी के पहले थी उस को सब लोग भली भांति जानते हैं। डैमोक्रेसी के क्या माने हैं और उस को किस दृष्टि से देखते हैं? अगर डैमोक्रेसी के बारे में यह धारणा है कि मेजोरिटी को सिर्फ वोट देने का अख्तियार है और वह कि माइनारिटी को यह हक है कि मेजोरिटी के रास्ते में जितनी अड़चने खड़ी कर सके कर शोर करे घेराव करे काम न करने दे जैसा कि विरोधी दलों के नेता यहां सदन में करते थे और जिस के बारे में अक्सर लोग जो कि यहां की कार्यवाही देखने आते थे पूछते थे विद्यार्थी पूछते थे और आप को अच्छी तरह से याद होगा कि 12 बजे के बाद यहां पर कैसा शोर होता था अगर इसी को हम डैमोक्रेसी समझें तो मैं समझता हूं कि वह डैमोक्रेसी नहीं है। इमरजेंसी के पहले जो कुछ गुजरात और बिहार में होता रहा और जो कुछ यहां पर दिल्ली में विरोधी दल के बड़े बड़े नेता करते जा रहे थे अगर उस बात की इजाजत देते और जो कुछ होता है उस को होने देते अगर यही डैमोक्रेसी के माने है तो सचमुच डेमोक्रेसी को खत्म किया। लेकिन अगर डेमोक्रेसी के मायने यह है कि हर व्यक्ति संयम रखते हुए अपनी आजादी का इस्तेमाल करे मेरी आजादी वहां खत्म होती है जहां दूसरे की आजादी शुरू होती है अगर मुझे बोलने का हक है तो दूसरे को भी बोलने का हक है अगर डेमोक्रेसी के यह माने है कि जो सरकार बनती है उस को अपनी मर्जी के मुताबिक कानून के मुताबिक अपनी नीति के मुताबिक काम करने देना है और उस के रास्ते में अड़चन डालना नहीं है, तो मैं समझता हूं कि हम ने जो कुछ किया है वह सही किया है और जो एक गलत वातावरण बनता जा रहा था उस को खत्म किया है। डैमोक्रेसी के जो गलत माने निकाले जा रहे थे और आजादी का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा था जो कि डेमोक्रेसी को खत्म करने जा रहा था, तो डैमोक्रेसी को हमने खत्म नहीं किया, बल्कि वह लोग खत्म कर रहे थे जो कि औरतों के और यहां पर बोलने वालों के रास्ते में

अड़चनें डालते थे। वह लोग रुकावट डाल रहे थे डेमोक्रेसी के रास्ते में।

26 जून के पहले जो यहां पर वातावरण पैदा किया गया था अगर वैसा वातावरण किसी देश में हो तो वहां पर न सिर्फ डेमोक्रेसी बल्कि आजादी भी नहीं रह सकती है। हमारी आजादी खतरे में थी, विदेशी ताकतें, सी०आई०ए० के लोग जो काम कर रहे थे, मैं यह नहीं कह सकता कि विरोधी दल के लोग उस में क्या मदद देते थे, लेकिन जो भी काम हो रहे थे वह एक ऐसा वातावरण पैदा कर रहे थे जिस के अन्दर कोई भी शक्ति अगर सरकार को फेल करना चाहती है, हमारी आजादी को खतरे में डालना चाहती है तो बड़ी आसानी के साथ खतरे में डाल सकती थी।

आलोचना का हक सब को है, लेकिन आलोचना नीतियों की होनी चाहिये एक्शन्स की होनी चाहिये, न कि व्यक्तियों की आलोचना होनी चाहिये। यहां पर विरोधी दल के लोग सरकार को पोलिसियों की, एक्शन्स की आलोचना की आजादी नहीं बल्कि व्यक्तियों की आलोचना की आजादी चाहते थे, जो कि किसी भी डेमोक्रेसी में सम्भव नहीं है। उन की आलोचना व्यक्ति विशेष को ले कर होती थी, विशेष रूप से प्रधान मंत्री को ले कर और कुछ चुने हुए नेताओं के बारे में, जैसे स्वर्गीय एल०एन० मिश्र पर कितने कितने लांछन लगाये गये। एक पोलिसी विरोधी दल ने अख्तियार कर रखी थी कि इतने लांछन लगाओ जिस से सरकार की इमेज देश में और दुनिया के सामने खत्म हो जाय। एक ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने रखी जाय कि यहां की सरकार करप्ट है। ऐसी नीति वह लोग अपनाते हैं जो री-ऐक्शनरी सरकारें लाना चाहते हैं। अब देखिए कि बांगला देश में क्या हुआ। वहां जिस प्रकार से नेताओं का कत्लेआम हुआ वह हमारे सामने है, उस से हमें सबक लेना चाहिए। वहां मजीब और उन के साथियों पर इतने लांछन लगाये गये कि वह करप्ट हैं और उस की आड़ में कत्लेआम हुआ। करप्शन का शोर ज्यादातर वही मचाते हैं जो खुद करप्ट होते हैं, जैसे कि जो चोर चोरी करता है और जब लोग चोर चोर कह कर भागते हैं तो चोर भी लोगों के साथ चोर चोर का शोर मचाता है तो यहां पर एक ऐसा वातावरण था कि यहां की सरकार कुछ नहीं करती है, सभी तरफ भ्रष्टाचार है, अगर ऐसा ही वातावरण यहां चलने दिया जाता तो डेमोक्रेसी आगे नहीं चल सकती थी।

आप जरा ठंडे दिल से सोचें, या जनता से पूछें तो वह कहेगी कि उस ने आराम की सांस ली है। आप देहात में, शहर में गरीब आदमियों से पूछें तो वह यही कहेंगे कि इस इमरजेंसी के लागू होने के बाद उन को आराम मिला है, देश में अमन चैन कायम हुआ है। तो यह एक अच्छी बात हुई, और विरोधी दलों ने जो एक गलत वातावरण देश में पैदा किया था उस को रोकना बहुत आवश्यक था।

सरकार ने जो कदम उठाया वह सही उठाया। बहुत सी बातों की नुक्ताचीनी कर सकते हैं, कुछ गलत बातें भी हुई हैं। लेकिन आम तौर से जैसा माननीय वी० के० आर० वी० राव ने कहा, आम तौर पर अगर देखें तो इस इमरजेंसी के कारण हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी है, औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन बढ़ा है। क्राइम का हव्वा, सालों से जो ब्लैक मनी की पैरलल अर्थ-व्यवस्था चल रही थी उस को खत्म किया गया। आज वह नहीं है।

वह जो स्थिति थी या उस की ताकत थी वह टूट गई, खत्म हो गई। तो मैं समझता हूं कि ये सब बातें इन कुछ महीनों के अन्दर, इन छ महीनों के अन्दर हुई हैं। क्या इस बात से कोई इन्कार कर सकता है? जो बाकायदा हैं उन से आप इन्कार नहीं कर

[श्री अमरनाथ विद्यालंकार]

सकते हैं। इमरजेन्सी से देश को फायदा हुआ है और देश इमर्जेन्सी के बाद आगे बढ़ा है। ये ऐसे वाकयात है, ऐसी घटनाए है जोकि साफ दिखाई देती है जैसे कि सूरज की रोशनी मे चीजे साफ दिखाई देती है। अगर विरोधी दलों के कुछ लोग पक्षपात की बात करे और इस बात से इन्कार करते है तो दूसरी बात है लेकिन विरोधी दल जनता के सामने यह बात कहेंगे तो लोग इस बात को नही मानेंगे और कहेंगे कि इमर्जेन्सी के जमाने मे देश आगे बढ़ा है और हमारी काफी समस्याए हल हुई है और हल होने जा रही है। यह ठीक है और मैं इस बात को मानता हू कि जहा हम ताकत अपने हाथ मे लेते हैं तो उस पर काफी अंकुश रखना पड़ता है और जरा सभल कर चलना पड़ता है और उस मे डिजिलेंस की जरूरत है। इसीलिए मैं यह कहूगा कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे मिनिस्टरों को काफी विजिलेंस की जरूरत है।

मै यह देखता हू कि हमारे दिल्ली शहर के अन्दर काफी सफाई हुई है और चंडीगढ के बारे मे भी मुझे मालूम है कि वहा पर काफी इस बात की कोशिश हो रही है कि जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है पब्लिक की जमीन पर, उन को वहा से हटाया जाए। रेगुलेट करना अच्छी बात है लेकिन उस के अन्दर भावना सही होनी चाहिए और मैं समझता हू कि इस के अन्दर हमारे जो सरकारी अफ़सर है उन की मनोवृति पर निर्भर करता है कि वे कैसे उस का इम्पलीमेंटेशन करते है। शायद उन की मनोवृति वैसी नही है जिस भावना से हम वे यह इमर्जेन्सी लगाई है। उन की भावना यह होनी चाहिए कि अगर 15 या 20 साल से कोई आदमी बैठा हुआ है और वह नाजायज कब्जा किये हुए बैठा है, अगर वह गरीब आदमी है और उस के पास दूसरे साधन नहीं हैं, तो हमारा मकसद उस को बसाने का होना चाहिए। हमारा मकसद बसाना है, उजाडना नही है। यही बात चडीगढ मे मैं ने वहां की सरकार से की थी और दिल्ली में भी की थी। इस प्रकार से जितनी जगहों से लोगों को हटाया गया है और कालोनीज को साफ़ किया गया है और वहां पर लोगों के पास घरबार नही है या काम नही है, तो हमारी कोशिश यह होनी चाहिए और हमारे सरकारी अफसरों को खास तौर पर इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि उन को बसाए। मैं समझता हू कि हमारे जो मत्रीगण है उन को भी इस में काफी सावधानी बर्तनी चाहिए और जहा पर इमर्जेन्सी का गलत इस्तेमाल हुआ है, उस को रोकना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हू कि यह बात ठीक है कि कृषि जन्य पदार्थों की कीमतें काफी गिरी है लेकिन जो औद्योगिक कारखानों में माल बनता है या जो उद्योगों मे चीजे बनाई-जाती है उन की कीमतें उतनी नही गिरी है जितनी कि और चीजों की गिरी है और इस के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए और कुछ कोशिश करनी चाहिए। देहात के लोगों की यह शिकायत है कि उन की जिन्सों की कीमत तो काफी गिर गई है लेकिन जो चीजे वे बाजार से खरीदते है उनकी उतनी नही गिरी। इस लिए इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए।

इसी प्रकार जो हमारा बीस सूत्रता प्रोग्राम है, यह प्रोग्राम आखरी नही है। यह बुनियादी प्रोग्राम है और एक स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे है और जैसा कि श्री वी० के० आर० वी राव ने कहा कि हम देहातो का स्ट्रक्चर ठीक करने जा रहे हैं। मैं समझता हू कि इस स्ट्रक्चर के चेन्ज होने से हमारी जो एकोनामी है, हमारे देश का जो आर्थिक ढाचा है, वह बहुत इम्प्रुव होगा और हम जो समाजवाद की तरफ कदम उठाना चाहते हैं वह भी बढ़ सकेगा लेकिन उस में तेजी आनी चाहिये। यह बात मैं खास तौर से कहना चाहता हू कि कांग्रेस

दल के लोग तो इस से सहमत हैं ही लेकिन विरोधी दल के लोगों ने भी इस प्रोग्राम को मानने से इंकार नहीं किया है और उन्होंने यह नहीं कहा कि लैंड रिफार्म्स नहीं होने चाहिए या कीमतों के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए । यह मैं ने जरूर देखा है कि कुछ लोग जो विरोधी दलों में हैं, वे विरोध करना ही अपना धर्म समझते हैं और इस बारे में करना कुछ नहीं चाहते हैं । वे कहते हैं कि यह बात तो ठीक है लेकिन हो नहीं रही है । वह यह समझते हैं कि डैमोक्रेसी के अन्दर जहां तक काम को करने का ताल्लुक है, जहां तक देश को बढ़ाने का ताल्लुक है, देश को अच्छे नतीजे दिलाने का ताल्लुक है; उस की सारी जिम्मेदारी सरकार की है । डैमोक्रेसी के अन्दर विरोधी दल भी अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकते हैं । विरोधी दल अगर यह समझते हैं कि तमाम अच्छी बातें करना सरकार का काम है और उन का काम बैठ कर उस के ऊपर नुक्ताचीनी करना है, सरकार की टांग खींच कर उसको गिराना है, तो मैं समझता हूं कि वे विरोधी दल का पार्ट अदा नहीं कर रहे हैं । डेमोक्रेसी के अन्दर विरोधी दल अगर जिम्मेदारी से काम करे तो मैं समझता हूं कि देश काफी तरक्की कर सकता है । जो काम हम देश के लिए करना चाहते हैं उन में उन को हमारा साथ देना चाहिए, लेकिन इस समय तक मैं नहीं जानता कि सिवाय एक दो दलों को छोड़ कर बाकी जो विरोधी दल है उन्होंने सिर्फ नुक्ताचीनी करना ही अपना कर्तव्य समझा है और इस 20 सूत्री कार्यक्रम में, जिन में अच्छे अच्छे काम हैं, अपना कोई योगदान नहीं दिया है । एक भी मिसाल मुझे नजर नहीं आती है । आज जो देश में भावना बनी है, उस भावना को वे खराब करना चाहते हैं । वे यह कहते हैं कि उन की तमाम आजादी खत्म हो गई है । इमर्जेन्सी को खत्म करने का एक ही तरीका है और जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है, वह तरीका यह है कि वातावरण ठीक हो और जब वातावरण ठीक हो जाएगा तो एमर्जेन्सी नहीं रहने दी जाएगी । हम चाहते हैं कि एमर्जेन्सी न रहे और हरेक यही चाहता है कि यह न रहे लेकिन नार्मल हालात होने चाहिए । जो लोग शोर करते हैं उन का भी यह काम है कि हालात सुधरें और क्लाइमेट अच्छी बने लेकिन उन का काम तो हालात को बिगाड़ते रहने का है । उन की भावना तो टांग खींचने की है और काम न करने देने की है । वे चुपचाप पर्चे बांट कर और चुपके चुपके गाली-गलोज दे कर लोगों को बहकाते हैं और अफवाहें फैलाते हैं । अगर वे लोग इस तरह के कार्य करेंगे तो एक अच्छी क्लाइमेट पैदा नहीं होगी और यह तो देश को खतरे में डालेंगे और समाजवाद को खतरे में डालने की बात होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझ बोलने का मौका दिया ।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) मि० डिप्टी स्पीकर साहब, सब से पहले मैं यह बात कहना चाहूंगा कि जब सदर साहब ने अपना खुत्बा पढ़ा था, उस वक्त मैं मौजूद नहीं था । मैं ने वह खुत्बा सुना नहीं । उस के बाद जब यह कापी मिली, तब भी मैंने इस को पढ़ा नहीं, इसलिए कि मैं नहीं समझता कि इस के पढ़ने की कोई जरूरत है । मैं अन्दाजा कर सकता हूं और मेरा अन्दाजा सही साबित हुआ है कि इस में वही बातें कही गई होंगी, जो मैं ने सोची थीं कि सदर साहब कहेंगे क्योंकि सदर साहब का एड्रैस अपना लिखा हुआ एड्रैस नहीं होता है । उन की खिदमात जो हैं, वे सिर्फ खुत्बे को पढ़ने के लिए हासिल की जाती हैं । इसलिए सब से पहली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि एमर्जेन्सी को जस्टिफाई करना सदर साहब का काम था और उन की सदारत का यह एक हिस्सा था ।

मैं आप को याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे यहां पांच, छ साल के कयाम के दौरान एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ, आप रिकार्ड

[श्री एस० एम० शमीम]

कन्सल्ट कीजिए, जबकि मैंने मारुति का जिक्र किया हो, एक भी ऐसा मौका नही आया है जब मैं ने श्री एल० एन० मिश्रा के मुताबिक एक भी लफ्ज इस्तेमाल किया हो । यह भी एक वाक्या है कि जब यहां हाउस मे सत्याग्रह हो रहा था, आई वाज नाट ए पार्टी टु इट । मैं यह भी याद दिलाना चाहूगा कि जब मुरारजी देसाई तकरीर करने के लिए खडे हुए और उन्होने यह दावा किया कि वे सारी अपोजीशन की जानिब से बोल रहे है तो मै ने कहा था कि आप सारी अपोजीशन की जानिब से बोलते रहे लेकिन मेरी जानिब से आपको बोलने का हक नही है । यह सब कहने के बाद मैं यह कहूंगा कि आज वे लोग भी मिसेज इन्दिरा गाधी की तारीफ कर रहे हैं जो इमर्जेन्सी मे पहले उन की मुखालफत करते थे मसलन मुस्लिम लीग मसलन मि० मनोहरन । अगर वे आज हिदायत कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं तो क्या वजह है कि मैंन अपने ऊपर यह फर्ज सौपा है कि मैं उन की मुखालफत करू । फक्र इसलिए जाहिर करना चाहता हू कि इस से पहले हर नाजुक मसले पर मिसेज गाधी के कहे बगैर उन की हिदायत के बगैर मैंने अपने दिल की आवाज पर उन की हर पालिसी की, जो सही पालिसी थी, हिमायत की है और अक्सर यहा झगडे होते थे । स्वर्गवासी श्यामनन्दन मिश्र जी ने एक बार मुझे कहा था कि आप तो जबर्दस्त लायलिस्ट है । यह ताना मैंने बर्दाश्त किया था ।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): This is not proper. It should be expunged.

श्री एस० एम० शमीम स्वर्ग ही समझ लीजिए । . . . (व्यवधान)

उस की वजह यह है कि उस वक्त मिसेज गांधी के पास एक मोरल ताकत थी ।

स्वर्ग के माने जन्नत के हैं, पैरेडाइज के हैं । काश्मीर को भी लोग जन्नत कहते हैं । मैं वहां का बाशिंदा हू । मुझे भी कोई स्वर्ग मे रहने वाला कहता है तो मैं उसको गाली नही समझता हू । उसको मैं अपनी तारीफ समझता हू । मुझे मालूम हुआ है कि श्याम नन्दन बाबु वहा इत्मीनान से बैठे हुए हैं । मुझे इससे बड़ा इत्मीनान हुआ है । वह वहा बडे मजे लेते हैं, इसलिए किसी को एहतराज करने की जरूरत नही है ।

उस वक्त मिसिज गाधी के पास एक जबर्दस्त मारल शक्ति थी ।

She was running the world's greatest democracy.

लेकिन 26 जून के बाद जो कुछ हुआ है उससे मैं अपने आपको कनविंस नही कर सका हू और अपने आपको समझा नही पाता हू कि अब उनके पास मारल स्ट्रैन्थ बाकी रह गई है । इसलिए मैंने अपने ऊपर यह फर्ज अदा किया है कि सिर्फ इसलिए कि मुल्क में एमरजेंसी का दौर दौरा है डर है खौफ है इस वास्ते मैं डर के सामने हथियार डाल दू उसके लिए मैं तैयार नही हू । मैं अदाजा कर सकता हू, समझ सकता हू कि इस बात को कि मुल्क मे ऐसा वातावरण था, इस हाउस मे ऐसा वातावरण था जो बहुत खराब था, बहुत ज्यादती हो रही थी, एक किस्म की गुंडागर्दी थी । आलम यहा तक था और मैं अपने आप को फिर दोहराता हू कि एमरजेंसी के बाद यह जाहिर नही होता कि मिसिज गाधी सिर्फ उन लोगो के खिलाफ थी या उन से नाराज थी जो हाउस मे हल्ला किया करते थे लेकिन मिसिज गाधी बैक्वर्ड नाराज हैं अखबारात से, पूरी पार्लियामेंट से नाराज है, मुल्क की ज्युडिशरी से नाराज हैं, विधान से नाराज हैं । उनको बन्द करने के बाद उन्हें यहा हल्ला करने की इजाजत नही दी जाएगी, मैं मान सकता हू । और बात करने की जरूरत नहीं थी । लेकिन ज्युडिशरी के

मुताल्लिक, सारे लाज के मुताल्लिक, कांस्टीट्यूशन के रिव्यु के मुताल्लिक उन्होंने कहा है और इसलिए कहा कि ज्युडिशरी इज टु इंडिपेंडेंट । इसके माने यह है कि सिर्फ बहाना था जो यहां हुल्लडबाजी कर रहे थे उनका और जो बन्द हैं जिन को मैं स्वर्गवासी नहीं कह सकता हूं लेकिन वे बन्द हैं । नाराजगी किस पर है ? प्रैस पर है । खबरदार यहां कोई बात कही जाती है तो उसको मेरी इजाजत के बगैर कोई शाया न करे । सिर्फ इस मुल्क की प्रेस से नाराज नहीं हैं, सारी दुनिया की प्रेस से नाराज हैं ।

अकसर हवाला दिया जाता है कि विदेशी मुल्कों के अखबारात हमारे खिलाफ लिखते हैं । कहा जाता है कि सी आई ए ने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया गैर मुल्कों मे, वहां की हकूमतों का तख्ता पलटने के लिए मैं पूछना चाहता हू कि इसकी इत्तिला आपको किस ने दी कि सी आई ए गैर मुल्कों मे आप्रेट कर रहा है । इत्तिला क्या जासूस ब्रह्मानंद रेड्डी जी ने दी, क्या उन्होने यह कहा, क्या ओम मेहता जी ने कहा ? उन्होंने नही कहा । यह इत्तिला आपको विदेशी अखबारात ने ही दी । न्यु यार्क टाइम्स में छपी थी, वाशिंगटन पोस्ट में छपी थी ।

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : जब कहा था उस वक्त कही नही छपी थी ।

श्री एस० ए० शमीम आपको याद नही है । सी०आई०ए० ने सब से पहला स्कैंडल कब किया था क्या इसके बारे मे सब से पहले इत्तिला आपको न्युयार्क टाइम्स ने नहीं दी तश्नअजवाम ? बगला देश के बारे मे आपको इनफर्मेशन क्या न्यु यार्क टाइम्ज ने नही दी थी । तमाम सी आई ए की एक्टिविटीज के मुताल्लिक आपको अमरीकन प्रैस के जरिये इत्तिलायें मिलीं वगर्नेकि आपके पास वगैरहगास्त कोई रास्ता न हो जिस को मैं नहीं जानता हूं । आपने कबूल किया है, आपने सहारा लिया है । जब आपको सूट करता है तब आप उसी मुल्क के सिस्टम को यटिलाइज करती रही हैं वहां के मुताल्लिक इनफर्मेशन के लिए ।

You are paying compliments to them but we want that the very compliments should be paid to the Press.

इशूज साटे आउट कीजिये । मिसिज गाधी डिक्टेटरशिप के रास्ते पर जा रही है । अब इसका फैसला करने का हक मिसिज गाधी को नही है मुझे है । उनके बयानात पढ कर, उनकी गफ्तगू ..., उनकी तकरीरो को सुन कर मैं यह बात कह सकता हू । उनकी तकरीरें मैंने बडी तवज्जह से सुनी है पढी हैं । आपको मालूम होना चाहिये कि क्रिमिनल ला और सिविल ला का एक बेसिस होता है ।

The burden is on who is accused.

मिसिज गाधी चाहती हैं कि सी आई ए के एजट यहा काम कर रहे हैं । अगर वे काम कर रहे है तो उसके बाद वह कहती हैं कि मुझ से इसके प्रूफ के बारे मे क्यो पूछते हो, यह उनका काम है जो कहते हैं कि हम नही कर रहे है और वे इसका प्रूफ दे । ।

That is not the language of a democrat because the fundamentals of Jurisprudence are that the burden is on who is accused

लेकिन लहजा बदल गया है, आवाज बदल गई है । यह किसी डैमोक्रेट की आवाज क्या हो सकती है ? मैंने अपने कानो से उनको सुना है । उन्होंने यह कहा है कि मैंने कोई गलत बात नही कही है, कोई है मुल्क मे जो कह सके कि मैंने कोई गलत बात कही है, कोई है मुल्क में जो कहे कि मैंने कभी कहा है कि यह होगा और वह नही हुआ ? खुदा को जिस की किताब हम पढते हैं, कुरान और गीता वह भी यह नही कहती है ।

श्रीमती इंदिरा गांधी कौन सा बताया है कि ऐसा होगा इसको आप बता दीजिए ।

श्री एस० ए० शमीम आपने कहा कि गुजरात मे हम इलेक्शन जीतेंगे आप हार गई....

[شری ایس - اے- شمیم (شری نگر): مسٹر ڈپٹی سپیکر صاحب -سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب صدر صاحب نے اپنا خطبہ پڑھا تو اس وقت میں موجود نہیں تھا- میں نے وہ خطبہ سنا نہیں - اس کے بعد جب یہ کاپی ملی تب بھی میں نے اس کو پڑھا نہیں اس لئے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے - میں اندازہ کر سکتا ہوں اور میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا ہے کہ اس میں وہی باتیں کہی گئی ہونگی جو میں نے سوچی تھیں کہ صدر صاحب کہینگے کیونکہ صدر صاحب کا ایڈریس اپنا لکھا ہوا ایڈریس نہیں ہوتا ہے - اُن کی خدمات جو ہیں وہ صرف خطبے کو پڑھنے کے لئے حاصل کی جاتی ہیں - اس لئے سب سے پہلی بات میں کہنا چاہوں گا کہ ایمرجینسی کو جستیفائی کرنا صدر صاحب کا کام تھا اور ان کی صدارت کا یہ ایک حصہ تھا -

میں آپ کو یاد دلانا چاہونگا - کہ مجھے یہاں پانچ چھہ سال کے قیام کے دوران ایک بار بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا—آپ ریکارڈ کنسلٹ کیجئے— جبکہ میں نے مارروتی کا ذکر کیا ہو- ایک بھی ایسا موقعہ نہیں آیا ہے جب میں شری ایل این مشرا کے متعلق ایک بھی لفظ استعمال کیا ہو - یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جب یہاں ہاؤس میں ستیہ گرہ ہو رہا تھا - آئی واز نوٹ اے پارٹی ٹو اٹ- میں یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ جب مرارجی ڈیسائی تقریر کرنے کیلئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ دعوہ کیا کہ وہ ساری اپوزیشن کی جانب سے بول رہے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ آپ ساری اپوزیشن کی جانب سے بولتے رہیں لیکن میری جانب سے بولنے کا آپ کو کوئی حق نہیں- یہ سب کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ آج وہ لوگ بھی مسز اندرا گاندھی کی تعریف کر رہے ہیں جو ایمرجینسی سے پہلے ان کی مخالفت کرتے تھے- مثلاً مسلم لیگ، مسٹر مدھون - اگر وہ آج حمایت کر رہے ہیں - تعریف کر رہے ہیں - کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر یہ فرض سونپا ہے کہ میں ان کی مخالفت کروں - یہ فرق اس لئے ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہر نازک مسئلے پر مسز گاندھی کے کہے بغیر ان کی ہدایت کے بغیر میں نے اپنے دل کی آواز ان کی ہر

پالیسی کی جو صحیح پالیسی تھی حمایت کی ہے - اور اکثر یہاں جھگڑے ہوتے تھے - سورگ باسی للت نارائن مشرا جی نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ آپ تو زبردست ٹاٹولسٹ ہیں- یہ طعنہ میں نے برداشت کیا تھا -

SHRI S. M. BANERJEE: This is not proper. It should be expunged.

شری ایس- اے- شمیم : سورگ ھی سمجھ لیجئے - اس کی وجہ یہ ھے کہ اس وقت مسز گاندھی کے پاس ایک مورل طاقت تھی - سورگ کے معنی جنت کے ھیں - پیراڈائیز کے ھیں - کشمیر کو بھی لوگ جنت کہتے ھیں - میں وہاں کا باشندہ ھوں - مجھے بھی اگر کوئی سورگ میں رہنے والا کہتا ھے تو میں اس کو گالی نہیں سمجھتا ھوں - اس کو میں اپنی تعریف سمجھتا ھوں - مجھے معلوم ھوا ھے کہ شام نندن بابو وہاں اطمینان سے بیٹھے ھوئے ھیں - مجھے اس سے بڑا اطمینان ھوا ھے - وہ وہاں بڑے مزے لیتے ھیں - اس لئے کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ھے - اس وقت مسز گاندھی کے پاس ایک زبردست مارل شکتی تھی -

She was running the world's greatest democracy.

لیکن ۲۶ جون کے بعد جو کچھ ھوا ھے اس سے میں اپنے آپ کو کلوبلس نہیں کر سکا ھوں - اور اپنے

آپ کو سمجھا نہیں پاتا ھوں - کہ اب ان کے پاس مورل سٹرینگتھ باقی رہ گئی ھے - اس لئے میں نے اپنے اوپر یہ فرض عائد کیا ھے کہ صرف اس لئے کہ ملک میں ایمرجینسی کا دور دورہ ہے ڈر ھے، خوف ھے - اس واسطے میں ڈر کے سامنے ھتھیار ڈال دوں اس کے لئے میں تیار نہیں ھوں - میں اندازہ کر سکتا ھوں، سمجھ سکا ھوں - اس بات کو کہ ملک میں ایسا واتاورن تھا، اس ھاؤس میں ایسا واتاورن تھا - جو بہت خراب تھا، بہت زیادتی ھو رھی تھی، ایک قسم کی غلقہ گردی ھو رھی تھی - عالم یہاں تک تھا اور میں اپنے آپ کو پھر دوھراتا ھوں کہ ایمرجینسی کے بعد یہ ظاہر نہیں ھوتا کہ مسز گاندھی صرف ان لوگوں کے خلاف تھیں یا ان سے ناراض تھیں - جو ھاؤس میں ہلا کیا کرتے تھے - لیکن مسز گاندھی ٹھیک وقت ناراض ھیں اخبارات سے - پوری پارلیمنٹ سے ناراض ھیں- ملک کی جیوڈیشری سے ناراض ھیں - ودھان سے ناراض ھیں - ان کو بند کرنے کے بعد انہیں یہاں ہلا کرنے کی اجازت نہیں دی جائیگی - میں مان سکتا ھوں اور بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن جیوڈیشری کے متعلق سارے لاز کے متعلق، کانسٹیٹیوشن کے ریویو کے متعلق انہوں نے کہا ھے اور اس لئے کہا کہ جیوڈیشری از ٹوو

[شری ایس اے - شمیم]

انڈیپنڈینٹ- اس کے معنی یہ ہیں کہ صرف بہانا یہ جو یہاں ھلڑ بازی کر رہے تھے - ان کا اور جو بند ہیں - جن کو میں سورگ باش نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن وہ بند ہیں - ناراضگی کس پر ہے ؟ پریس پر ہے - خبردار یہاں کوئی بات نہ کی جاتی ہے - تو اس کو میری اجازت کے بغیر کوئی شائع نہ کرے - صرف اِس ملک کی پریس سے ناراضگی نہیں ہے ساری دنیا کی پریس سے ناراض ہیں - اگر حوالہ دیا جاتا ہے کہ بدیشی ملکوں کے اخبارات ہزا ہمارے خلاف لکھتے ہیں- کہا جاتا ہے کہ سی آئی اے نے کیا کیاکیا اور کیا کیا نہیں کیا غیر ملکوں میں، وہاں کی حکومتوں کا تختہ پلٹنے کے لئے - میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی اطلاع آپ کو کس نے دی کہ سی آئی اے غیر ملکوں میں اوپریٹ کر رہا ہے- اطلاع کیا جاسوس پرمانند ریڈی جی نے دی- کیا انہوں نے یہ کہا، کیا اوم مہتہ جی نے یہ کہا- انہوں نے نہیں کہا- یہ اطلاع آپ کو بدیشی اخبارات نے ہی دی ہے - نیویارک ٹائمز میں چھپی تھی، واشنگٹن پوسٹ میں چھپی تھی -

شریمتی اندرا گاندھی : جب کہا تھا اس وقت کہیں نہیں چھپی تھی

شری ایس اے شمیم : آپ کو یاد نہیں ہے - سی آئی اے نے سب سے پہلا سکنڈول کب دیا تھا - کیا آپ اس کے بارے میں سب سے پہلے اطلاع آپ کو نیویارک ٹائمز نے نہیں دی تھی - بنگلہ دیش کے بارے میں انفورمیشن آپ کو کیا نیویارک ٹائمز نے نہیں دی تھی - تمام سی آئی اے کی ایکٹیویٹیز کے متعلق آپ کو امریکن پریس کے ذریعے اطلاعیں ملیں بشرطیکہ آپ کے پاس بوا راست کوئی راستہ نہ ہو جس کو میں نہیں مانتا آپ نے قبول کیا ہے - آپ نے سہارا دیا ہے - جب آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ اس ملک کے سسٹم کو پوپیولائز کرتی رہی ہیں وہاں کے متعلق انفورمیشن کے لئے -

You are paying compliments to them but we want that the very compliments should be paid to the Press

ایندوز سورت آوٹ کہیئے مسز گاندھی ڈکٹیٹر شپ کے راستے پر جا رہی ہیں - اس کا فیصلہ کرنے کا حق مسز گاندھی کو نہیں ہے مجھے ہے - ان کے بیانات پڑھکر، ان کی گفتگو سے - ان کی تقریروں کو سن کر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں - ان کی تقریریں میں نے بڑی توجہ سے سنی ہیں پڑھی ہیں - آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ کریمنل لا اور سول لا کا ایک بیسر ہوتا ہے -

The burden is on who is accused.

مسز گاندھی کہتی ہیں کہ سی آئی اے کے ایجنٹ یہاں کام کر رہے ہیں - اگر وہ کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتی ہیں - کہ مجھ سے اس کے پروف کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو - یہ ان کا کام ہے جو پوچھتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں - اور وہ اس کا پروف دیں -

That is not the language of a democat because the fundamentals of jurisprudence are that the burden is on who is accused.

لیکن لہجہ بدل گیا ہے - آواز بدل گئی ہے - یہ کسی ڈیموکریٹ کی آواز کہاں ہو سکتی ہے - میں نے اپنے کانوں سے ان کو سنا - انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے - کوئی ہے ملک میں جو کہہ سکے کہ میں نے کوئی غلط بات کہی ہے - کوئی ہے ملک میں جو کہتے کہ میں نے کبھی کہا ہے - کہ یہ ہوگا اور وہ نہیں ہوگا - خدا کی جس کی کتاب ہم پڑھتے ہیں - قرآن اور گیتا وہ بھی یہ نہیں کہتی ہیں -

شریمتی اندرا گاندھی : کون سا بتایا ہے کہ ایسا ہوگا - اس کو آپ بتا دیجئے -

شری ایس اے شمیم : آپ نے کہا کہ گجرات میں ہم الیکشن جیتیں گے - آپ ہار گئیں -]

SHRIMATI INDIRA GANDHI: When this question was asked, I replied "I never prophesy about the result of election", not once but many times.

SHRI S. A. SHAMIM: मैं दर्जनों बातें ऐसी बता सकता हूं जिन से पता चल जाएगा...

एक माननीय सदस्य : यह बात तो गलत साबित हो गई, दूसरी बताइये।

SHRI S. A. SHAMIM: I told Mrs. Gandhi that she was proved wrong. Mrs. Gandhi made a categorical statement, "I will never bow before Mr. Morarji's demand for Gujarat elections." She had to bow.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: If he quotes me wrongly, how can I just sit quiet.

SHRI S A SHAMIM: Mrs. Gandhi said a hundred times, "I will have no takes with the Opposition leaders. (Interruptions) It will not happen." (Interruptions) Gujarat Assembly was dissolved. She has not been proved wrong once. She has been proved wrong 101 times. (Interruptions) आप तो डिसिप्लिन की देवी हैं। कम से कम आप तो सुनें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : डिसिप्लिन की बात नहीं है। जब आप मुझे गलत कोट कर रहे हैं तो जरूर मैं आपको टोकूंगी।

श्री एस० ए० शमीम : आप बुरा न मानें

श्रीमती इंदिरा गांधी : जब आप मुझे कोट कर रहे हैं तो गलत कोट नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप खत्म करें।

श्री एस० ए० शमीम :

I was interrupted by no less a person than the Prime Minister herself.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No interruptions please.

श्री एस० ए० शमीम : गलत कोट करने का हक भी मुझे है और उसके लिए डिप्टी स्पीकर साहब मौजूद हैं । इसी एवान में आपने कहा था कि गुजरात में इलैक्शन वक्त के पहले नहीं करवाऊंगी, गुजरात असैम्बली डिसाल्व नहीं करूंगी, गुजरात असैम्बली को आपने डिसाल्व किया । बहरहाल यह बात नहीं है । अगर आपको इस में मसरत—

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Mr. Shamim, please conclude.

SHRI S. A. SHAMIM: Let me conclude, Sir.

मैं अर्ज कर रहा था कि आपने कहा था कि मैं कभी गलत साबित नहीं हो सकती और आप गलत साबित हुई चाहे आप लाख कहे कि मैं गलत साबित नहीं हुई हूं ।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : एक तो सही उदाहरण दें । जितने दिए हैं सब गलत साबित हो चुके हैं । दस मिसालें आपने दी हैं वे सब गलत साबित हुई हैं ।

श्री एस० ए० शमीम : इमरजेंसी नाफिज हुई । एमरजेंसी के बड़े गुण है, बड़े फायदे हैं । उन्होंने खुद कहा था कि एमरजंसी इज ए बिटर मेडीसिन और यह मेडीसिन तब दी जाती है जब मरीज की सेहत खराब हो । जितनी देर मरीज की सेहत खराब रहती है तब तक दी जाती है । अगर ज्यादा देर खराब रहती है तो उसके दो ही नतीजे हो सकते हैं । एक तो यह कि दवाई गलत दी गई है और मरीज की सेहत ठीक नहीं हो रही है और दूसरा यह डाक्टर गलत है, डाक्टर ने सही अंदाजा नहीं किया है । आज लोग बात कर रहे हैं कि एमरजंसी इंडफिनिट होनी चाहिये । इसलिए यह बात कर रहे हैं कि मुल्क में डिबेट और डिसेंट खत्म हो जाए । आज मुल्क में यह खत्म होता तो मुझे मातम नहीं होता । लेकिन खुद कांग्रेस पार्टी में डिबेट खत्म हो गया है । जिस देश में कांग्रेस पार्टी के मैम्बर गिरफ्तार किए जाएं इसलिए कि पार्टी में डिबेट न हो तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है ? अपोजीशन के मैम्बर राइट रिएक्शनरी हो सकते है, गलत हो सकते हैं लेकिन आपने चंडीगढ़ का तमाशा देखा होगा । वहां वन वायस आफ डिसेंट नहीं हुआ । मिसिज गांधी ने जगजीवन राम को बिठा दिया कि उन्होंने डिफेंड इनको नहीं किया मुल्क में यह हालत है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI VASANT SATHE: On a point of order, Sir. A Member is wrongly quoting a case. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am listening to the point of order.

SHRI VASANT SATHE: If whatever has happened outside, is quoted here wrongly, knowing that it is wrong, and quoted here purposely to scandalize the convention of a political party, it is completely unparliamentary; and this will not be allowed to go on record.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please, order please.

SHRI S. A. SHAMIM: I said there was... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, order. Well, Mr. Shamim, a point of order has been raised. Allow me to dispose it of. We should speak with utmost responsibility and whatever we say in the House, we must be sure

that what we say is correct. Now, order please, order. In this case, I am not in a position to say what is correct, what is not correct. If he has made some statement and that has been strongly repudiated from the other side....

SHRI S. A. SHAMIM: What is that statement?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Both are on record, and what Mr. Shamim has said has been refuted by the Congress side that it is not true. The matter should end there. How am I to decide what is right?

SHRI VASANT SATHE: Once it has been refuted categorically, he should not be allowed to continue it.

SHRI R. S. PANDEY (Rajnandgaon): He says that he has got every right to speak wrongly.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is not right. Knowing that it is wrong, if he makes a statement, that is not fair.

श्री राम सहाय पांडेय : यह कह रहे थे कि अगर यहां पर गलत बोलने का हक भी है तो मुझ को है, मैं गलत बोल सकता हूं ।

SHRI S. A. SHAMIM: If you check up the record, I said and I repeat, "Whether I said the truth or the untruth, you are nobody to decide it, the hon. Deputy-Speaker will decide it."

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not correct. Unless I know what is the truth, how can I decide whether it is correct or not?

SHRI R. S. PANDEY: Please see the record.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have already upheld your point, that no Member can say that, knowing that it is wrong, he can make a statement.

SHRI S. A. SHAMIM: I said that when I make a statement, if somebody says that it is not true, I will not accept his word that it is not true. When I make a statement, I make it with the fullest responsibility. If somebody says that it is not true, it is for him to prove it. This logic should not be carried to its illogical end that it is I who have to prove it.

मैं अर्ज कर रहा हूं कि एमरजेंसी कितनी देर जारी रहेगी ? एमरजेंसी के लिये अगर यही है कि हर अपोजिशन लीडर यह लिखकर दे दे कि वह कोई ऐसी इन-कंवीनियेंट बात नहीं करेगा जिससे हुक्मरान जमात को तकलीफ हो तो यह फिर समझ लेना चाहिये कि एजरजेंसी 100 साल तक कायम रहेगी । जिस तरीके से और जिस तौरपर कांग्रेस मेम्बरर्स ने एमरजेंसी की हिमायत की है उससे यह जाहिर होता है कि

They have decided to change the system, they are on the path of dictatorship.

इस्पात खान मंत्री (इन्द्रजीत यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, जी, लगभग 6 महीने हुए, जब हमारे देश आपातकालीन स्थिति लागू की गई । इस 6 महीने के बीच में हम इस सदन में दूसरी बार मिल रहे हैं । यह इस बात का प्रमाण है कि आज भी हम अपने देश में संसद् की प्रभुता को स्वीकार करते हैं और इस देश की उन्नति में, इसके प्रशासन में और इस देश की जनता के आर्थिक और सामाजिक जीवन में जो कुछ भी हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम समझते हैं कि उसका माध्यम यह हमारी संसद् है । और इसीलिए हमने इस देश में जो कुछ भी किया है, हमें इस बात का गर्व है कि पिछले 27 वर्षों में इस देश की जनता का विश्वास प्रजातंत्र में और इस देश की संसदीय व्यवस्था में निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है ।

[श्री इन्द्रजीत यादव]

15.54 hrs.

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

श्रीमन्, आपातकालीन स्थिति देश मे क्यो लागू की गई ? लागू करने के दिन ही प्रधान मंत्री ने अपने बहुत मुख्तसर भाषण मे देश की जनता को अपना सन्देश दिया था कि कैसी स्थिति थी। हम जानते थे, उस समय हमारा देश हमारी जनता एक सकट के दौर से गजर रही थी। हमारे देश मे बहुत बडी महगाई थी मुद्रास्फीति थी, जनता के लिये जरूरी सामान का बहुत बडा अभाव था और उससे हमारे देश की जनता म गहरा असन्तोष था। वह स्थिति इसलिए थी कि दुनिया मे और हमार देश के अन्दर बहुत सी ऐसी घटनाये घटी, जिन पर हमारा काबू नही था। उदाहरण के लिये दुनिया म तेजी के साथ महगाई बढी, मद्रास्फीति हुई। दुनिया के उन देशो ने जो पेट्रोल जैसा पदार्थ पदा करते है उन्होन उसकी कीमत बढाई और हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर लाजमी तरीके से उसका एक गहरा असर पडा। हमारे देश म बाढ और सूखे की ऐसा स्थिति पदा हुई जो पिछले कई वर्षों मे नही हुई थी। हम जानते थे कि हमारी जनता सकट म है। हमारी परा कोशिश थी कि हम उसे उस सकट से निकाल उसकी सहायता करे और बिगडती हुई आर्थिक स्थिति पर काबू पाय और उस समय जो भी सरकार और देश के सामने सम्भव था किया जा रहा था। यह मामूली बात नही थी। लगभग 25 करोड देश की जनता सूखे और बाढ की शिकार थी। उसकी मदद करन के लिए सरकार ने कोई साधन नही उठा रखा था मदद करने की कोशिश की गई। हमने मद्रास्फीति को रोकना चाहा।

अभी डा० वी० के० आर० वी० राव ने सही कहा। हम अपने देश म नही दुनिया के मच पर अपना सिर ऊचा कर क इस बात को कह सकते हैं कि जब एक ऐसी स्थिति आई कि यहा 31 फीसदी मुद्रास्फीति हुई तो हमने जो भी सम्भव था किया। हमने अपने देश के अनावश्यक खर्चों को काटा। इस देश की उन ताकतो पर जो बैंको के साधनो का नाजायज फायदा उठाती थी, हमने उन पर नियत्रण लगाया और दूसरे कदम उठाये। हमे इस बात का एहसास है कि हमने कुछ एसे भी कदम उठाये कि उससे हमारे गरीब मजदूरो तक को थोडी कठिनाई और मुसीबत हुई। लेकिन देश के हित मे, राष्ट्र के और उनके खुद के भविष्य के हित मे कदम उठाये गये। नतीजा यह हुआ कि हमने मुद्रास्फीति पर काबू पाया। हमने देश मे साधनो को बढाने की कोशिश की उत्पादन बढाने के लिये कोशिश का ताकि जनता मे अभाव की स्थिति को हम दूर कर सके।

अपनी आर्थिक स्थिति से हमे आज भी सन्तोष नही है हमारे प्रयास जारी है प्राथमिकताए तय हो रही है सरकार अपने साधन इकट्ठे कर रही है। सरकार अपनी पूरी शक्ति से काम कर रही है। हमारी जनता का सहयोग हमे उसम मिला है। हम सकट, भय महगाई और मद्रास्फीति के दौर से निकले है और एक नये दौर की तरफ हमार देश न चरण रखा है। आज प्रकृति ने भी सहयोग दिया है हमारी फसल अच्छी है। हमार किसान और हमार मजदूर अपने देश के उत्पादन के काम म लगे हुए है। एक नया वातावरण आज हम अपने देश म पैदा कर रहे है।

लेकिन श्रीमन जब एक राष्ट्रीय सकट का जमाना था, मुझे याद है, प्रधान मत्री जी ने एक बार नही अनेक बार इस देश की जनता से अपील की कि इस समय एक रहो हम सब मिलकर काम करे। सूखे पर हमारा काबू नही, बाढ पर काबू नही, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर काबू नही। यह राष्ट्रीय सकट है, हम अपने मतभेद भुलाकर जनता की सहायता करे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, कम्युनिस्ट पार्टी को छोडकर तमाम विरोधी दलो ने अभाव की स्थिति का, महगाई का और देश

में आये हुए संकट का अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिये लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की । हड़तालें ही नहीं कराई गई, हिंसा, टकराव, तोड़फोड़, और चरित्रहनन का वातावरण इस देश में पैदा किया गया और एक ऐसी स्थिति पैदा की गई कि देश और सरकार लुजपुंज हो जाये ।

आखिर में आपने देखा कि इस खुले मंच से बरसों से आह्वान किया जा रहा था--फौजों को बगावत का, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों और नौजवान विद्यार्थियों को बगावत का आह्वान कर देश में बगावत का माहौल पैदा किया जा रहा था । उन्मादन को रोकने के लिए क्या नहीं किया गया ? आखिर में हमारे एक सहयोगी की हत्या की गई । ऐसी शक्तियां खुलेआम उसमें काम कर रही थी । प्रधान मंत्री पर तानाशाह होने का आरोप लगाया गया । अगर प्रधान मंत्री तानाशाह होतीं और उनका देश की जनता में विश्वास न होता तो जो आपतकालीन स्थिति 25 जून को उन्होंने इस देश में लागू की मजबूर होकर, जब ऐसे षडयंत्र किये जा रहे थे, देश में प्रजातंत्र समाप्त करने के लिये, आदर्शों को समाप्त करने के लिये, आजादी को खतरे में डालने के लिये, विदेशी ताकतों को इस देश में दखल देने का मौका देने के लिये, तब उनके पास कोई चारा नही रह गया था । देश की आजादी, आदर्श, जनता के भविष्य के हितों का जब इन ताकतों के जरिये ध्यान नही रखा जा रहा था, जिन पर जनमत का कोई असर नही पड रहा था, जिनको देश के हितों को कोई ज्ञान-अज्ञान नही रहा था तो प्रधान मंत्री ने इस कदम को उठाया ।

शमीम साहब यहां नही है । प्रधान मंत्री के बारे मे जो भी उनका एहसास हो, जो भी उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन उनको हो वह कहे । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि काश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता यह अहसास करती है कि प्रधान मंत्री हमारी प्रिय नेता हैं, उनके हाथ मे हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है । देश की जनता कहती है कि जिस काम को प्रधान मन्त्री ने 25 तारीख को किया वह पहले क्यों नहीं किया । प्रधान मन्त्री ने यह नही किया, वह सोचती थी कि शायद वह दल सोचेंगे, जनता के हितों को देखेंगे, शायद उन पर जनमत का कोई असर पड़ेगा । बडी-बडी प्रार्थनाएं की गई अनुरोध किया गया, उनसे बातचीत की गई लेकिन कुछ नही । उनके पीछे षडयंत्र था, एक चाल थी इसलिये बात को नजरन्दाज कर दिया गया ।

मुझे अफ़सोस है कि शमीम साहब ने कहा है कि अखबारों की स्वतन्त्रता को समाप्त कर दिया गया है । प्रश्न यह कि क्या हम ने 27 साल तक अखबारों के लिए कोई बाधा उपस्थित की । वे चाहे जिस तरह से कार्य करें, इसके लिए उनको हर प्रकार की सहूलियत और सुविधा देने की कोशिश की गई । हम सब जानते है कि पिछले कई बरसों से

[श्री चन्द्रजीत यादव]

कुछ अखबार किस तरह की भूमिका अदा कर रहे थे। इसीलिए इस सदन में बार-बार यह मांग की गई कि उन के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए और उन पर नियंत्रण होना चाहिए। ये अखबार इस देश की जनता का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे थे।

उदाहरण के लिए एक पार्टी का अखबार इसी दिल्ली में निकलता था---जनसंघ का **मदरलैंड**। वह अखबार लगभग एक साल से प्रधान मंत्री के निजी व्यक्तित्व और उन के परिवार के बारे में अपने मन से घड़ कर गैर-जिम्मेदार झूठी और अनर्गल बातें प्रकाशित कर रहा था। उन को पढ़ कर एक साधारण नागरिक का खून भी खौल उठता था कि आखिर यह क्या हो रहा है, क्या यही अखबारों की आजादी है। लेकिन प्रधान मंत्री ने एक बार भी उस अखबार के खिलाफ कुछ नहीं किया कोई कदम नहीं उठाया।

हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री एक मामूली मवक्किल की तरह चार साल तक अपने विरुद्ध इलैक्शन पेटीशन के केस की पैरवी करती रहीं, और उन्होंने इस सम्बन्ध में किसी विशेष अधिकार का प्रयोग नहीं किया। इससे बढ़ कर प्रजातंत्र का क्या प्रमाण हो सकता है? प्रधान मंत्री के खिलाफ फैसला हुआ, और उनको अपील करने का मौका दिया गया। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि उन को अपील नहीं करने दी जायेगी, प्रधान मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, जब प्रधान मंत्री का केस सुप्रीम कोर्ट में जायेगा तो वहां बैंच में कौन कौन जज होंगे, कौन उस बैंच की सदारत करेगा, आदि। कौन लोग ये बातें कह रहे थे। इस तरह की तानाशाह की भाषा दूसरे लोग बोल रहे थे।

श्री समर मुकर्जी इस समय सदन में नहीं हैं। इस देश में एक सम्पूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। वह सम्पूर्ण क्रांति नहीं थी, बल्कि प्रति क्रांति थी---वह टोटल रेवोल्यूशन नहीं था, बल्कि काउंटर-रेवोल्यूशन था। उस को ले कर इस देश में हिंसा, तोड़-फोड़ और अराजकता की कार्यवाहियां की जा रही थीं। मैं बड़ी नम्रता से श्री समर मुकर्जी से पूछना चाहता हूं कि कौन उसके नेता थे। दुनिया जानती है कि जनसंघ और आर० एस० एस० के नेता उसके नेता थे। पूर्ण क्रांति के नेता ने उस के सम्मेलन में जा कर कहा कि अगर आर० एस० एस० फासिस्ट ताकत है, तो पहले मैं फासिस्ट हूं। आज माननीय सदस्य उन के साथ हमदर्दी प्रकट कर रहे हैं और उन की वकालत कर रहे हैं। क्या इस देश में समाजवाद का माध्यम केवल जनसंघ और आर० एस० एस० ही रह गए हैं? क्या सी० पी० आई० (एम०) की यही नीति और यही सोचने का ढंग है?

लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं इस देश के लाखों करोड़ों मजदूरों को, सी० पी० आई० (एम०) के नेता अपने आप को जिन के नेता होने का दावा करते हैं। जब सी० पी० आई० (एम०) के नेता सम्पूर्ण क्रांति की कतार में खड़े थे और जनसंघ तथा आर०

एस० एस० के साथ कदम से कदम मिला कर चल रहे थे। उस समय इस देश के मजदूर वर्ग ने प्रति-क्रांति की इस साजिश को समझा और उस से अलग रहा, और इस प्रकार उस ने देश की प्रभुसत्ता और आजादी की रक्षा की।

इस सदन में सदस्य कुछ भी बात कह सकते हैं। लेकिन सी० पी० आई० (एम०) के माननीय सदस्य ने अपने भाषण में शुरू से आखिर तक केवल आरोप ही आरोप लगाये हैं। वह भले ही हमारी राष्ट्रीय नीतियों की आलोचना करते, मगर प्रधान मंत्री ने पिछले चन्द बरसों में देश में और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो भूमिका अदा की है वह उस की सराहना के कुछ शब्द भी कह देते। प्रधान मंत्री ने साम्राज्यवादी चालों का खंडन किया है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की बढ़ती हुई ताकतें दुनिया के गरीब और अविकसित देशों के आन्तरिक मामलों में दखलअंदाजी करती थीं। प्रधान मंत्री ने अपनी नीतियों से उन का मुकाबला किया है। उन्होंने वियतनाम की बहादुर जनता का समर्थन किया है। उन्होंने अरब जनता का उस की आजादी, उस की भूमि और अधिकारों की रक्षा के संघर्ष में समर्थन किया है। प्रधान मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका की जनता का समर्थन किया है, जो अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही है। हमारे प्रधान मंत्री ने देश की साठ करोड़ जनता की आशा-आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो कदम उठाये हैं, और देश के सम्मान को जिस तरह से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उठाया है, एक राष्ट्र और देश के नाते हम को उस पर गर्व है।

लेकिन माननीय सदस्य ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। उन्होंने केवल आलोचना की है और केवल कमजोरियों और खामियों की चर्चा की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने किस की वकालत की है। उन्होंने जनसंघ, आर० एस० एस० स्वतंत्र पार्टी और श्री मोरारजी देसाई की वकालत की है, उन तत्वों की वकालत की है, जो हिंसा और तोड़फोड़ की नीति पर चल रहे हैं।

आज इस देश में दो विचारधारायें हैं, दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो वह है, जिस पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। हम लोग जनवाद, संसदीय व्यवस्था और जनता की शक्ति में विश्वास करते हैं। हम इस बात में विश्वास करते हैं कि शान्तिपूर्ण तरीके से अहिंसा के रास्ते पर चल कर देश में विकास हो सकता है, प्रगति हो सकती है और समाजवाद आ सकता है। समाजवाद की रूप-रेखा हमारी धरती में उत्पन्न होगी, हमारे देश की प्रतिभा से उत्पन्न होगी। समाजवाद हमारे किसानों और मजदूरों की मेहनत से आयेगा। हां, दुनिया के अन्य लोगों के अनुभव से भी हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे।

दूसरी विचारधारा उन लोगों की है, जो प्रति क्रांति, हिंसा और तोड़फोड़ के मार्ग पर चल रहे हैं जिन का अपने आप में विश्वास नहीं है, बल्कि जो दूसरों की मदद में विश्वास करते हैं। विरोधी दलों को आन्दोलन करने, सत्याग्रह करने और सरकार को अपदस्थ करने का अधिकार है। लेकिन मुझे इस बात से गहरी ठेस लगती है कि जब देश उन संकटों में से गुजर रहा था, जिन पर हमारा बस नहीं था, जब देश की जनता के हौसले को बुलंद करना चाहिए था, देश की जनता के मनोबल को ऊंचा उठाना चाहिए था, देश की एकता को मजबूत करना चाहिए और राष्ट्रीय आत्मविश्वास को जगाना चाहिए था, उस समय इन दलों ने सब से बड़ा राष्ट्रीय अपराध यह किया कि उन्होंने देश के मनोबल और राष्ट्रीय आत्मविश्वास को तोड़ने और चारों तरफ बुराई ही बुराई दिखाने का प्रयास किया। और जिस देश की जनता का मनोबल, आत्मविश्वास और एकता टूट जाये, वह देश गुलाम बन जाता

[श्री चन्द्रजीत यादव]

है। वही प्रयास, वही कोशिश इन दलों द्वारा इस देश मे की गई।

हमारे सामने कठिनाइयां थी, लेकिन क्या हम इन दो सालो मे हाथ पर हाथ रख कर बैठे थे? हम उन कठिनाइयो से जूझ रहे थे। जब पैट्रोल पैदा करने वाले देशों ने तेल की कीमत बढा दी, तो हम को उस पर 1,000 करोड रुपया ज्यादा देना पड़ा। श्रीमती इन्दिरा गाधी के नेतृत्व मे चलने वाली सरकार द्वारा हमारे देश के विशेषज्ञो मे कहा गया कि अगर हिन्दुस्तान की धरती मे तेल नही है, तो हिन्दुस्तान के चारो तरफ समुद्र मे निगाह डालो, शायद वहा तेल मिल सके, क्योंकि यह देश एक हजार करोड रुपया अपने विकास की कीमत पर दूसरे देशों को नहीं दे सकता है। क्या हमे इस बात पर गौरव नहीं होना है?

इसी बीच मे हमारे इजीनियरो ने समुद्र का सीना फाड कर तेल के सोते निकाले हैं, और हमे आशा करनी चाहिए कि आठ दस साल मे वह समय आयेगा, जब भारत अपने पैरो पर खडा होगा, और हमे एक बद भी तेल बाहर से नहीं मगाना पडेगा। लेकिन हमारे मित्र ने इस बारे मे कोई चर्चा नही की है।

इसी बीच मे हम एक न्यूक्लियर पावर और स्पेस पावर बने। इस के अतिरिक्त हमने काश्मीर जैसी गम्भीर समस्या को बातचीत के जरिए हल किया। शमीम साहब कहते हैं कि प्रधान मत्री तानाशाह हैं। लेकिन उन्ही के सूबे मे बातचीत के जरिए एक पुरानी और गम्भीर समस्या का हल निकाला गया। प्रधान मत्री ने कई बार कहा है कि मैं अपनी पार्टी और राष्ट्रीय आन्दोलन की गोद में पली हूं, लेकिन अगर कही पार्टी और देश मे टकराव होगा, तो मै देश को चुनूंगी, पार्टी को नहीं। उन्होंने काश्मीर मे इस बात को साबित कर दिया। उन्होंने वहा अपनी पार्टी की सरकार से अलग हो जाने के लिए कहा, क्योंकि उन का मत रहा है कि काश्मीर और देश बड़ा है, हमारी पार्टी की सरकार उन मे बड़ी नहीं है।

सिक्किम के माननीय सदस्य इस सदन में आये है। इससे भी हमारा गौरव बढता है। सिक्किम के इतिहास मे पहली बार वहां की जनता को अधिकार प्राप्त हुआ और उसने एक राय से यह तय किया कि हमारा भविष्य हमारा मुस्तकबिल हिन्दुस्तान के करोडो लोगो के साथ है। हमारे मित्र ने इसकी भी कोई चर्चा नहीं की है। वास्तव मे इस देश मे राष्ट्र के गौरव, सम्मान और आत्मविश्वास को तोडने की कोशिश हुई और यह सबसे बडा अपराध है।

मैं कहना चाहता हू इस मौके पर वियतनाम मुझे बार बार याद आता है—छोटा सा देश एशिया का, उस पर दशको से हमला हुआ, दुनिया के बडे बडे बम गिराये गए। वियतनाम के पास कोई न्यूक्लियर पावर नहीं कोई एटम शक्ति नहीं लेकिन उसके पास एक शक्ति थी—देशभक्ति। जनता का मनोबल ऊचा था। जनता के अन्दर एकता थी और इसलिए वियतनाम ने दुनिया की बडी भारी ताकत को परास्त किया। कोशिश की जा रही थी इस देश के अन्दर जनता के मनोबल को तोडने के लिए। यह एक राष्ट्रीय अपराध था जिसको क्षमा नही किया जा सकता था और प्रधान मन्त्री ने 25 जून को जो कदम उठाया, मैं इस बात को कह सकता हू, भारत की करोड़ों जनता इस बात को जानती है और भारत की करोड़ों जनता को इस बात का अगर सन्तोष है, अगर

इस देश में शान्ति है, इस देश में आत्म-विश्वास फिर से जागा है तो वह इसलिये कि इस देश का सर्वोत्तम देशभक्त जिस काम को कर सकता है ऐसी स्थिति में, प्रधान मन्त्री ने 25 जून को उसी काम को किया है। देशभक्ति का इससे बड़ा दूसरा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है।

इस देश के अन्दर आज आपातकालीन स्थिति है। एक नया वातावरण है सहयोग का और अनुशासन का, आगे के लिए विकास का और प्रगति का वातावरण है। लेकिन हम उन कमजोरियों को नहीं भूले हैं। हमारी कमजोरियां भी है। हमारी नीतियों में दोष भी रहे हैं। हम उन को लागू नहीं कर पाए हैं। उन कमियों को दूर करने की और उसका हल निकालने की कोशिश की गई है।

कहा गया है कि देश तो बिल्कुल पीछे जा रहा है। पिछले कुछ आंकड़े मैं देना चाहता हूं। जुलाई से दिसम्बर 1974 तक इस देश में जितना कोयला पैदा किया गया ठीक उसी काल के अन्दर जुलाई से दिसम्बर, 1975 तक उसमें 12 प्रतिशत ज्यादा कोयला पैदा किया गया। एल्युमिनियम इस देश में जुलाई से दिसम्बर, 1974 तक जितना पैदा हुआ ठीक उसी काल में 1975 के साल में उसमें 44 प्रतिशत ज्यादा पैदा हुआ। उसी काल में फर्टिलाइजर 1975 के साल में 43 प्रतिशत ज्यादा हुआ, स्टील 18 प्रतिशत ज्यादा पैदा हुआ, बिजली 12 प्रतिशत ज्यादा पैदा हुई, वनस्पति आयल 12 प्रतिशत ज्यादा पैदा हुआ, क्रूड आयल 10 प्रतिशत ज्यादा पैदा हुआ, सीमेंट 11.1 प्रतिशत ज्यादा पैदा हुआ। इस देश के अन्दर आज एक प्रगति का, उत्पादन बढ़ने का वातावरण पैदा हुआ है और मुझे खुशी है कि सभी वर्गों ने उसमें सहयोग दिया है।

आज हमारा विद्यार्थी किस तरह अनुशासित है। शमीम साहब होते तो मैं उनसे पूछता कि किस कालेज के, किस यूनिवर्सिटी के ऊपर हमने फौज बैठाई है? इस देश में कालेज और यूनिवर्सिटियों की संख्या सौभाग्य से आजादी के बाद सैकड़ों में नहीं हजारों और लाखों में है। कहां हमने फौज बैठाई है? कहां हमने पुलिस बैठाई है? आज वह विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं, उन्होंने समझा है इस बात को और एक अभूतपूर्व अनुशासन उनके अन्दर आया है। किस कारखाने पर हमने फौज बैठाई है? लेकिन हमारे मजदूर आज समझते हैं अपने कर्तव्य को। आज उन्होंने जिस तरीके से उत्पादन बढ़ाया है वह इस बात का प्रमाण है। हमने उन पर थोड़ा बोझ भी डाला फिर भी उन्होंने उसको बर्दाश्त किया इसलिए कि उन्होंने राष्ट्र के हित को देखा। हम उनकी पैट्रियाटिज्म की, उनकी देशभक्ति की सराहना करते हैं और प्रधान मन्त्री ने खुद कहा था कि हमें यह काम करना पड़ा है और बड़े कामों के लिए। यह हमारे लिए कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है। लेकिन हमने मजदूरों का हित जितना किया है उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं।

इस बीच में श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने अपना भाषण दिया। मुझे खुशी है कि उन्होंने जिस तरीके से जो बात सही थी उसको सही तरीके से कहा और जो बातें उनकी दृष्टि में ऐसी थीं जिनमें कमजोरी है उनको उन्होंने एक संयमित तरीके से कहने की कोशिश की। लेकिन कुछ तथ्य भी इस देश के अन्दर हैं। पिछले दिनों में 60 लाख परिवारों को मकान बनाने के लिए हमने जमीन दी। मैं नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ा काम हमने किया। अभी हमने जमीन दी है। मकान बनाने के लिए उनको सामान चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन हमने एक शुरूआत की है। उस तरफ कदम हमने बढ़ाया है। उसकी कोशिश हम कर रहे हैं।

हमने इसी बीच यह कोशिश की कि हमारे ऐसे अपरेंटिस जो ट्रेनिंग लेकर बैठे रहते हैं, 1 लाख 23 हजार व्यक्ति ऐसे थे,

[श्री चन्द्रजीत यादव]

उसमें से 1 लाख 17 हजार को हमने स्थान दिया ।

इस देश के अन्दर हमने पब्लिक सेक्टर को बढाया है । बडी आलोचना इस देश मे सार्वजनिक क्षेत्र की हुई । जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता, उनकी सूझबूझ इस राष्ट्र ने देखी है, दुनिया ने देखी है । जो उन की देन है हमारे राष्ट्र के लिए, जो उनकी देन है अन्तर्राष्ट्रीय जगत मे वह कोई छिपी हुई नही है । एक दार्शनिक की तरह वह ऐसे व्यक्ति थे जिसको विज्ञान था 25 साल पहले, पचास साल पहले वह देखते थे । आज वही पब्लिक सेक्टर हमारे आर्थिक ढांचे की बुनियाद है । आज जिस तरीके से वह हमारी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, पिछले वर्षों मे 15 प्रतिशत उत्पादन उन्होंने इस देश मे बढाया है । मैं आशा करता हू कि इस देश का जो प्राइवेट सेक्टर है क्योंकि हम मिक्स्ड एकानामी को मान कर चल रहे हैं तो हमने उनको कहा है कि उनकी भी अपनी भूमिका है और यह बार बार उनको कहा गया है कि उन्हे देश का हित, जनता का हित ध्यान मे रखना होगा, हम आशा करते है कि वह इसे ध्यान मे रखेंगे और अगर वह नही रखते हैं तो सरकार अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल करेगा जिससे देश के हित मे उत्पादन हो सके ।

हमारे विद्यार्थी, देश के नौजवान भी इन कठिनाइयों के शिकार हुए है । हम जानते है कि उनकी जरूरी चीजे उन्हे नही मिलती थी । एक ऐसा भी समय आया जब उनके लिए कागज भी नही मिलता था, किताबे भी नही मिलती थी, खाने का सामान भी नही मिलता था । क्या सरकार का ध्यान इधर नही गया ? पिछले छ. महीने के अन्दर कोशिश की गई है, देश के अन्दर लगभग 5 हजार होस्टलों के अन्दर विद्यार्थियों को मिला कर ऐसे कन्ज्यूमर्स स्टोर्स खोले गए हैं, सोसाइटीज खोली गई हैं जिससे जरूरी सामान उनको उपलब्ध कराया जाय । इसी छ: महीने के अन्दर कोशिश की गई है 75 हजार से ज्यादा ऐसे बुक बैंक हमने देश के अन्दर खोले हैं जिससे हमारे गरीब विद्यार्थियों को पुस्तक मिल सके । इसी बीच में यह कोशिश की गई है कि हम उनकी छात्रवृत्ति को बढाए और आज हमारे विद्यार्थी को इस बात का एहसास हो रहा है कि इस संकट के जमाने मे उनका भी अपना एक कर्तव्य है । उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए मुझे पूरा विश्वास है वह अपना कदम उठाएगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मजदूरों की हिस्सेदारी की चर्चा की कि प्रबन्ध में उनकी कितनी हिस्सेदारी है ? हम यह नही कहते कि हमने ने पूरा मुकम्मिल और आदर्श कदम उठा लिया । लेकिन एक पहली शुरूआत हुई है, एक सरकारी निर्णय के मुताबिक पहली बार आदेश दिए गए है इस देश के कारखानों को और हमें खुशी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकाश कारखानों में आज मजदूरों की प्रबन्ध मे हिस्सेदारी हो इसके लिए कदम उठाए गए है । हम यह नही कहते कि उसके अन्दर मनेजमेंट मे मजदूरों को हिस्सेदारी पूरी मिल गई है लेकिन सही बात है कि उस लेवेल के ऊपर जहा उन्हे बैठना है काम करना है खुशी की बात है जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार अधिकाश कारखानों में प्रबन्धकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों द्वारा एक साथ बैठ कर आपसी बातचीत से ऐसे रास्ते निकाले जा रहे है जिससे मजदूर उसके अन्दर हिस्सेदार बनाए जाय । हमारा यह पहला कदम है । हम आशा करते है कि यह कदम और आगे बढेगा और सही माने में इस देश का मजदूर, यहां का श्रमजीवी इस बात का एहसास करेगा कि इस देश की पैदा की हुई सम्पत्ति के अन्दर उसका हक है । उसको पैदा करने में उसकी प्रतिभा, उसका अनुभव और उसका ज्ञान जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और मुझे इसमें

कोई शक नहीं है कि हमारा देश इससे लाभ उठाएगा ।

आज हमारी कठिनाइयां है । हम एक ऐसे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे है जो अभूतपूर्व है । उसमें हमारा पहला प्रयास है कि हम इस देश में पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए अगर इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारना है तो हमारे देश में पब्लिक इन्वेस्टमेंट निरन्तर हम को बढ़ाना पड़ेगा । जब तक इस बात को हम नहीं करते है तब तक हमारी आर्थिक व्यवस्था कमजोर रहेगी । जब तक हमारे नये उद्योग नहीं लगते है जब तक जनता की कमाई उत्पादन के कामों में नहीं इस्तेमाल की जाती है जब तक सरकार के अपने साधन नहीं बढ़ते है तब तक आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती ।

बार बार इसी सदन में कहा गया है और मैं खुद महसूस करता हू कि इस देश में सबसे बड़ा साधन इस देश का 80 प्रतिशत व्यक्ति है जो गावों में बसता है खेती करता है । उसकी भलाई के लिए साधन इकट्ठे करने पड़ेंगे । हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा । हमने खुद कोशिश की है कि हम अपने देश में बिजली की और पानी की शक्ति को बढ़ाए । 100 करोड़ रुपया हमने इसके लिए अतिरिक्त आवंटित किया है जिससे हम ज्यादा बिजली पैदा कर सके और ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था कर सके । 85 करोड़ रुपया हमने उन राज्य सरकारों को दिया है जिनकी बहुत सी योजनाएं अधूरी थी लेकिन जिन को पूरा करना जरूरी था । उसके लिए हमने उनको यह रुपया दिया है ताकि इस काम को वह कर सके । हमारी कोशिश है कि 11 लाख हेक्टेयर जमीन अतिरिक्त हम इस साल सिंचाई के अन्दर ला सके, उसमें हम सिंचाई की व्यवस्था कर सके । हमारी कोशिश है हम जानते है जो गांधी जी कहा करते थे और जवाहर लाल नेहरू कहा करते थे कि हिन्दुस्तान गांवों में बसता है उस गांव की जनता की जिन्दगी में तबदीली लाने के लिए जरूरी है कि हम उसके लिए पानी दे, बिजली दे, हम उसकी जमीन का ठीक से पुनर्वितरण करें । कोशिश इस बात की की जा रही है । कमजोरियां रही है । हमारे कानून बने है । कानूनों की मरम्मत भी हुई है । लेकिन कानून ठीक से नहीं लागू किए जा सके । इसीलिए राष्ट्रपति जी ने इस बात को कहा है कि इस देश के अन्दर केवल सरकारी मशीनरी के माध्यम से हम विकास के काम को नहीं कर सकते ।

जनता का सहयोग हमारे लिए जरूरी है । पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि हमारे देश की प्लानिंग में पीपुल्स इन्वाल्वमेंट जरूरी है । इसमें हम देश के लोगों का सहयोग चाहते है । वह हमें सुझाव दे कि कैसे प्रशासन में तबदीली करें कैसे जनता और सरकार के सहयोग को ज्यादा प्रभावकारी बनाया जाये । सरकार ने हमेशा जनता से सहयोग की अपेक्षा की है । हम आशा करते है कि जो गम्भीर प्रश्न हमारे देश के सामने खड़े है उनको हल करने में जनता हमारी सहायता करेगी ।

16.00 hrs.

हमारे देश के सामने कृषि को ठीक ढंग से पुनर्गठित करने का सवाल है । मैं समझता हू जब तक देश खाद्य के मामले में आत्म-निर्भर नहीं बनता, हमारी आर्थिक व्यवस्था कमजोर रहेगी । यह बात दूसरी है कि पानी अच्छा बरस जाये, प्रकृति हमारा सहयोग कर दे लेकिन हमेशा प्रकृति के ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं होना है । ऐसी स्थिति का निर्माण करना होगा कि पानी के अभाव में गावों में फसल न सूखे जाये । ऐसी स्थिति लानी है कि बिजली के अभाव में उद्योग-धंधे न बन्द हो जाये । ऐसी स्थिति लानी होगी कि किसान को उसके उत्पादन की ठीक कीमत मिल सके । किसान को यह महसूस हो सके कि देश के बनाने में उसका भी अपना योगदान है और उसको वह दे सके । आज जो वातावरण इस

[श्री चन्द्रजीत यादव]

देश में पैदा हुआ है उसमें हमारे देश के खेतिहर मजदूर, छोटे किसान मध्यम दर्जे के किसान इस देश की आर्थिक व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

तीसरा सवाल हमारे देश के सामने बैलेन्स आफ पेमेन्ट का रहा है। पिछले चार पांच वर्षों मे देश के सामने सबसे बडी कठिनाई यह रही है कि आयात के ऊपर अरबो रुपए खर्च करने पडे। आज सरकार की तीसरी महत्वपूर्ण कोशिश है कि हमने अपने देश मे हम निर्यात को बढ़ाये। और आयात को कम करे। जिन चीजो का हम आयात करते थे आज कोशिश की जा रही है अपने देश मे ही फर्टिलाइजर पैदा करे अपनी जरूरत के मुताबिक। कोशिश की जा रही है कि हम अपने देश म जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा करे। हम अपने देश मे पट्रोल पैदा करे इजीनियरिंग गुड्स पैदा करे। इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है। सरकार ने जो नीति निर्धारित की है उसम इस बात पर जोर होगा कि हम अपने आयात को किस तरह से कम करे और उस पैसे का बचा कर देश के आर्थिक विकास म लगाये। देश मे जो नया वातावरण पैदा हुआ है उसका देश की जनता न अपार समर्थन दिया है। मुझे बहुत विश्वास है इस देश की जनता म। हमारे देश के राष्ट्रीय नताओं ने हमेशा इस देश की जनता मे उसकी शक्ति मे और उसकी बुद्धिमत्ता म विश्वास किया है। इसीलिए गाधीजी ने कोई दूसरा रास्ता नही चुना था। जब दुनिया के सबसे बडे साम्राज्यवाद का मुकाबला किया तो गाधी जी ने एक ही रास्ता चुना कि इस देश की जनता के पास जाये और उसका सहयोग हासिल करे। पडित जवाहर लाल नेहरू ने भी उसी रास्ते को आगे बढाया। कांग्रेस पार्टी ने भी उस सिद्धान्त को आगे बढ़ाया। सन् 1971 मे जब प्रतिक्रियावादी ताकतों ने चुनौती दी थी और जब कांग्रेस का बहुमत नही रह गया था उस वक्त हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी अगर चाहती तो तानाशाह बन सकती थीं लेकिन उन्होंने वह रास्ता नही चुना। उन्होंने कहा इस देश के सामने दो विकल्प है। एक विकल्प में हमारी पार्टी रहेगी, बैंकों का राष्ट्रीकरण करना है प्रिवीपर्स को समाप्त करना है, भूमिहीनों को भूमि देने के लिए भूमि सुधार करना है और नौजवानो के भविष्य को बनाना है। दूसरा विकल्प प्रतिक्रियावादियों के महागठबन्धन का था। एक जबर्दस्त चुनौती उन्होंने दी थी लेकिन श्रीमती इन्दिरा गाधी को पूरा विश्वास था कि गाधीजी जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की उस राष्ट्रीय परम्परा के ऊपर यदि हम जनता के सामने जायेगे अपनी सही बात को लेकर तो जनता हमारे साथ खडी होगी। इस प्रकार 1971 मे जनता ने कांग्रेस को अपार बहुमत और समर्थन दिया। इसलिए श्रीमन मैं कहना चाहता हू कि आज एक नया वातावरण देश मे पैदा हुआ है हम चाहते है कि तमाम देशभक्त शक्तिया हम चाहते है देश की तमाम प्रगतिशील ताकते हम चाहते है कि देश की वे तमाम ताकते जो प्रगति और समाजवाद म विश्वास रखती है मिलकर सब काम करे। हमारी प्रधान मन्त्री जी ने चण्डीगढ म हमारे महाअधिवेशन मे देश की जनता को आवाहन करते हुए कहा है कि इस देश की कराडो जनता के लिये समाजवाद के अलावा दूसरा रास्ता नही है। हमने अपने अनुभव से सीखा है कि हमारा भविष्य उस सिद्धान्त के साथ उस लक्ष्य के साथ बधा हुआ है और हम पूरा भरोसा है अपने प्रधान मन्त्री जी के नेतृत्व मे जिनके नेतृत्व मे हमने उस बडे सकट का मुकाबला किया है और आज भी कर रहे है। हमे इस बात का अहसास है कि हमारी जनता की आर्थिक कठिनाइया है हम इस बात का भी अहसास है कि हकारे देश के बहुत से इलाके पिछडे और गरीब है हमे इस बात का भी एहसास है कि आज भी पूरी मेहनत करने के बावजूद जनता का बहुत बडा भाग पेट भर रोटी भी नही पा रहा है.

लेकिन हम कृत-सकल्प हैं, हमारा लक्ष्य है—देश की गरीबी मिटाना, हमारा लक्ष्य है इस देश की करोड़ों गरीब जनता की आखों से आसू पूछना। जब तक यह विश्वास हमारे साथ है—मुझे तनिक भी सन्देह नही है—हमारे देश की जनता हमारी इन नीतियों का समर्थन करेगी।

इन्ही शब्दों के साथ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिये जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हू।

कुमारी मणिबेन पटेल (साबरकंठा): चेअरमैन साहब, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर क्या कहा जाय, कुछ समझ नही आता है। अगर सचमुच देश मे बहुत ज्यादा शान्ति है, सब जगह अनुशासन आ गया है, तो फिर आपातकालीन स्थिति क्यों रखी जा रही है और जब तक आप इसको बनाये रखना चाहते है? इस प्रकार का गलतबयानी करने से क्या फायदा है कि मोरारजी भाई ने हिसा करने को कहा था। मुझे एक उदाहरण तो दीजिये—जिस में उन्होंने ऐसा कहा था

श्री राम सहाय पांडे अभी बतलाता हू, मणिबेन।

कुमारी मणिबेन पटेल बीच मे न बोलिये।

सभापति महोदय जब आपकी टर्न आये तो बता दीजियेगा।

श्री राम सहाय पांडे . मणिबेन, मेरे पास डाक्यूमेन्ट है।

कुमारी मणिबेन पटेल गवर्नमेंट कोई चीज गलत छाप दे तो उसको क्या कहा जा सकता है।

मैं बतला रही थी कि इन्दिरा जी ने लिख कर दिया था कि मीसा का उपयोग पोलिटीकल लोगों के लिये नहीं होगा, लेकिन उसका उपयोग पोलिटिकल लीडर्स के लिये किया गया और उनको एकान्त में, Solitary Confinement में रखा गया है। जयप्रकाश बाबू की तबियत खराब हुई, महताब और नवल किशोर की हालत खराब है। आखिर उन्होंने क्या गुनाह किया है, अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है तो उन पर मुकदमा चलाओ, उनको सजा दो। लेकिन ऐसा नही करते है और कहते है कि लोग हमारे साथ है, लोग आप की तारीफ करते है। अगर ऐसा है तो फिर यह रोक टोक क्यों है? पार्लियामेंट में आने के दर्वाजे क्यों बन्द किये है? आप के पास तो मोटर है सरकारी पट्रोल है आप जा सकते है, लेकिन हमारे जैसे को घूम कर आना पड़ता है। मैं पूछती हू पार्लियामेंट के दरवाजे बन्द करने की क्या जरूरत है। यह कैसा शासन है कैसा अनुशासन है, सरकार ऐसा क्यों करती है?

आप कहते है कि आप ने घूस बन्द कर दी है—लेकिन मैं आप को रेलवे की एक बात बतलाती हू—यह दिसम्बर महीने के आखिर की बात है। एक पति-पत्नी थे, उन्होंने जाने का तय किया तो उन को तीन टायर मे जगह दे दिया बाद में लड़की ने भी जाने का तय किया तो उसको दो टायर में जगह दिया। पति ने कहा कि मैं उधर सो जाऊगा और लड़की अपनी मा के पास सो जायेगी तो उन को कहा गया कि ऐसा नही होगा। मा और लड़की को किसी तरह से एक ही बर्थ पर सोना पड़ा और वह जगह भी दूसरे को पैसा लेकर दी गई थी। आप इन सब बातों को क्या जाने आप तो हवाई जहाज मे और सिक्योरिटी के बीच जाते है। आप के मिनिस्टर लोग भी हवाई जहाज में जाते है लेकिन मैं थर्ड क्लास मे सफर करती हूं—इस लिये मैं इन सब बातों को बतला सकती हू।

आप कहते है कि रेलवे मे पहले से बहुत सफाई हुई है—मैं तो समझती हू कि

[कुमारी मणिबेन पटेल]

सफाई पहले से कम हो गई है। मेरे अपने उपर बारी की पटरी गिर गई थी, नसीब में था इसलिये बच गई (व्यवधान) आप कहते हो कि सब चीजों के दाम गिरे है, कोई तकलीफ नहा है। मैं आप को एक गहिणी की बात बताना चाहती हू। उस महिला ने कहा कि मिट्टी का तेल महगा हो गया गैस महगी हो गई बिजली, पेट्रोल महगा हो गया। अनाज और सबजी ज्यादा हो गया इसलिये सस्ते मिलते है। आप स्टेट्स को कहते हो कि इतने दाम पर मिट्टी का तेल और गैस देनी चाहिये। मगर उधर आप स्वय इन चीजों के दाम बढा रहे है तो कैसे वह कम दाम पर लोगो को यह चीज दे सकती है। तो किस प्रकार से एक सामान्य महिला गुजर करती है वह मैंने आप से कहा।

आप कहते हों कि गुजरात मे अनुशासन नही है, हिंसा हो रही है। मै आप को बताऊ कि विधान सभा के चुनाव हुए उस मे 67 हिंसा के किस्से हुए जिस म 4 खून हुए। अभी पचायत चुनाव म 27 हिंसा के किस्से हुए और उस में 2 खन हुए जिन पर कार्यवाही चल रही है। आप केवल वहा के चीफ मिनिस्टर का बदनाम करना चाहते हो। जो आप कहते हो वह तो अखबारो म छपता है, लेकिन जो हमारा चीफ मिनिस्टर कहता है वह अखबार मे नही छपता। यह कैसी सेंसरशिप है? आप की पार्टी का तो सब छपता है, लेकिन विरोधी दल जो कहता है उस को जनता के सामने नही आने दिया जाता है। आप का सब लोगो की बात जनता के सामने आने देनी चाहिये जनता अपने आप फैसला करेगी कि क्या और किस की बात ठीक है। आज खाली प्रधान मत्री का गाना गाया जाता है लेकिन स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो विधान सभा म भी कहता है वह नही छपता, उस को रेडियो पर भी बोलने का अधिकार नही है, सही बात को कहने का उस को अधिकार नही है। यह तो आटोक्रेसी इन दी सार्व आफ डेमोक्रेसी चल रही है।

मैं आप को बताऊ कि मुझे पकडा गया, तीन घटे रखा गया लेकिन पार्लियामेंट के बुलेटिन मे यह आज तक नही आया। ऐसे ही काम होना चाहिये। अग्रेजों के राज्य में सब का न्याय मिलता था लेकिन आज यहा पर जिन को चाहे पकड लो। आप ने स्वय कहा था कि मोरारजी के खिलाफ एम० आइ० एम० ए० का उपयोग नही करेंगे लेकिन सबसे पहले आप ने उन पर ही उस कानून को लाग किया जेल मे आप कितने लोगों को रख कर आप डालना चाहते है? ग्वालियर की राज माता को गायत्री देवी को आप ने किस तरह से रखा? उन को कई दिनों तक वेश्याया के साथ रखा और इतनी गन्दी जगह रखा कि उन्होंने खाना तक नही खाया। गायत्री देवी ने कहा था कि मैं राजनीति से निकल जाती हू, फिर भी आप ने उन को नही छोडा। तो ऐसा अन्याय तो नही होना चाहिये। कम से कम लोगो को न्याय तो मिलना चाहिये। वैसे तो न्यायालय भी अब आप के साथ है फिर भी व्यक्ति को अदालत के सामने जाने का अधिकार तो मिलना ह, चाहिये। क्या आप इसी तरह से अनुशासन चलाना चाहते हो? हमारे मुख्य मत्री जो कुछ विधान सभा म कहते है, सभाओं मे कहते है म्यूनिसिपल बार्ड-इलेक्शन्स की सभाओं मे कहते है वह कुछ भी अखबार में नही आता। जितना आप को पसन्द हो उतना ही आ सकता है और अखबारों मे भी जो अखबार आप को पसन्द है उन की सेंसरशिप नही होगी और जो अखबार आप के विरुद्ध है वे जो बातें लिखते है उस की एक एक लाइन की उस के एडवरटाइजमेंट की सेंसरशिप होनी चाहिए। यह आप का न्याय है? यह सही बात आप करती है? जरा सोचिये। आप कहती है कि जनता आप के साथ है लेकिन उस के साथ क्या होता है?

अब मैं चंडीगढ़ की बात लूं। वहां आप का वार्षिक अधिवेशन हुआ। जो हम ने सुना है, उस को मैं कहती हूं। हमें सुनने को मिला कि वहां पर कई लोगों को खाना नहीं मिला और ओढ़ने को नहीं मिला। वहां इन चीजों का इन्तजाम ठीक नहीं था। ...(व्यवधान). जो बात मुझे कहनी है वह मैं कहूंगी। देखिये, आप नाराज क्यों होती हैं। यह आप ने सामने अनुशासन हो रहा है। ये आप का डिसिप्लिन मान रहे हैं। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। . . .) (व्यवधान) नहीं नहीं, हम को कोई डर नहीं है। इस से इन की शोभा बढ़ती है और इनकी पार्टी को शोभा बढ़ती है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी जब दूसरी पार्टियों के लोग बीच बीच में बोलते हैं तो क्या शोभा बढ़ती है ?

कुमारी मणिबेन पटेल : मैं इस पार्लियामेंट में आज से नहीं हूं। . . (व्यवधान) . .

SHRI P. M. MEHTA: In spite of the instructions from the Leader of House, the hon. Members are misbehaving here. You should control the hon. Members who are misbehaving. Kindly do it.

कुमारी मणिबेन पटेल : मैं पार्लियामेंट में बहुत दिनों से हूं और मुझे यह देख कर बड़ा दुख होता है। मैं तो आना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे भेजा गया। इन बातों से क्या पार्लियामेंट की शान रहती है। आप ने स्पीकर साहब को भी निकाल दिया। स्पीकरशिप ऐसी जगह है कि उस के बाद स्पीकर साहब को ऊंची जगह देनी चाहिए। आप ने उठा कर उन को मिनिस्टर बना दिया। यही आप का शासन। जो मुझे सही लगेगा मैं कहूंगी। आप ने अपनी पार्टी के उन लोगों को जो आप के विरुद्ध बोले जेल में डाल दिया और जो आप की 'हां में हां' मिलाते हैं उन को पार्टी में ले लिया। दूसरी पार्टी से अगर कोई आए तो कोई हर्ज की बात नहीं है और दूसरी पार्टी से आप के यहां आ कर वह प्रतिवादी हो गया चाहे वह जनसंघ का हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो तो या जनता कांग्रेस का हो। हमारी पार्टी में अगर कोई आता है, तो वह प्रगतिवादी नहीं है।... (व्यवधान) .. आप शान्ति से रहें और अच्छी बात करें। एक दिन आप का भी आएगा जब आप का काम भी पूरा हो जाएगा। हम हिंसा नहीं चाहते हैं। हम तो गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं। आप गांधी जी का नाम लेती है लेकिन आप के वहां दारू पीने वाले है, शराब पीने वाले है। हम ऐसे लोगों को अपने यहां नहीं रखते।

श्री शंकर देव (बीदर) : अध्यक्ष महोदय, आज के इस विक्षुब्ध वातावरण में मैंने जो अनुभव किया है, उस चीज को आप के सामने पेश करना चाहता हूं। आजादी से पूर्व हम लोग कर्तव्य के वातावरण में थे और प्रत्येक नागरिक त्याग, तप और सेवा के लिए तयार था। आजादी आई, अधिकार आ गये, सम्पत्ति का अधिकार, भाषण का अधिकार, संगठन का अधिकार आ गया। परिणाम क्या हुआ? परिणामतः त्याग की जगह भोग आया, तप की जगह विलास और सेवा के स्थान पर शोषण। अनुशासन की जगह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आ गई, फीडम आफ एक्सप्रेशन आ गया। सम्पूर्ण भारतीय आकाश में अधिकारों के मुक्के ही मुक्के नजर आने लगे, कर्तव्य या सेवा के जुड़वे हाथ कहीं नहीं। संविधान के निर्माता विधान में कर्तव्य लिखने का कर्तव्य भूल गये। संविधान में केवल अधिकार दिये, पर कर्तव्यों की कहीं सूची नहीं। वे *इसी भ्रम में रह गए कि धर्म प्रधान भारतीय* जनता के लिए शायद कर्तव्य की सूची की आवश्यकता नहीं।

पिछले 28 वर्षों में हमने केवल अधिकारों के आनन्द लिए। सम्पत्ति के अधिकार के

[श्री शंकर देव]

तहत हमने खूब लूटा, शोषण किया। भाषण और संगठन के अधिकार के तहत मन मानी बकवास करते रहे। सभ्यता अनुशासन और शिष्टाचार की हत्या की। रोज हड़ताल प्रदर्शन, नारेबाजी गाली गलोज आदि चलते रहे। मंत्रियों, मुख्य मंत्रियों तथा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों सभी पर खूब कीचड़ उछाली गई। अनेक मंत्रियों, मुख्य मंत्रियों और चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी सम्पत्ति को रखने के अधिकार का दिल खोल कर लाभ उठाया। विद्यार्थियों ने फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन का आनन्द लिया। पूंजीपतियों और सत्ताधारियों ने भी सम्पत्ति को रखने का आनन्द लिया। दोनों में होड़ चली। विद्यार्थियों ने मुक्के दिखाए तो सत्ताधिकारियों ने धक्के दिए। धक्का मुक्की चलती रही। शिक्षक जो गुरुजन कहे जाते हैं जहां से केवल कर्तव्यों की ध्वनि आनी चाहिए, वहां भी हड़ताल आदि की आवाज सुनाई देने लगी। यहां तक कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों के जो कभी अपना सर्वस्व समर्पण करने को तयार थे, उनके भी संगठन बने और उन में पैंशन बढ़वाने के अधिकार की आवाज सुनाई देने लगी।

अधिकारों की होली खेली गई। खून रंग उड़ा, रंग के साथ कीचड़ और मैला भी एक दूसरे पर उड़ता गया। किसी भी समाचार-पत्र को आप उठा कर तबदेख लेंत आप के हाथ को कीचड़ ही लगता। सिवाय कीचड़ के उन में कुछ नहीं रहता था।

खैर, अब हमें संविधान में कर्तव्यों की सूची बनानी होगी। केवल अधिकारों और कर्तव्यों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, उन में संतुलन होना चाहिए। बेलेंस इन में आपको लाना होगा। आजादी के पूर्व कर्तव्य और आजादी के पश्चात् के अधिकारों, दोनों में आपको समन्वय करना पड़ेगा। बापू ने यही चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि धर्म और राजनीति को अलग अलग मत करो, एथिक्स और पालिटिक्स अलग अलग नहीं है दोनों को मिला कर चलो। आजादी के पूर्व जब हम गुलाम थे तो हमारे कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। गुलामों के केवल कर्तव्य होते है, अधिकार नहीं होते। वेतन भी अगर लेना होता था तो उसके लिए प्रार्थनापत्र देना पड़ता था और कहना पड़ता था कि हमें वेतन दो। अधिकार पत्र नहीं दिया जा सकता था। इसी प्रकार आजाद व्यक्ति की आजादी भी कर्तव्यों से बांध कर रखनी पड़ती है कहीं वह सीमा से बाहर न हो जाए। आजादी अपना पराकाष्ठा पर पहुंच कर गुलामी बन जाती है। भारत इसी कर्त्तव्यहीनता के कारण एक बार गुलामी भुगत चुका है। अब उस में पुन परीक्षण करने की हिम्मत नहीं है। तात्पर्य यह है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक है पर स्वतंत्र रूप में अधूरे है। आजादी को गुलामी में बदलने के पूर्व हां यह काम हमको करना पड़ेगा।

तमाम चीजों को सोच कर ही और गम्भीरतापूर्वक विचार करके ही मैं जिस परिणाम पर पहुंचा हूं उसको मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस पर गम्भीरता से सोचें। हो सकता है कि इसका कोई परिणाम न हो लेकिन मैं अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता हूं और मेरी जो समझ है उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हम अधिकारों और कर्तव्यों के समन्वय की बात सोच रहे है। यह केवल बीच की अवस्था है। समाज का इससे आगे बढ़ना है। जहां सारे अधिकार कर्तव्यों में लीन हो जाते है और केवल कर्तव्य ही रह जाते है। इसीलिये गीता ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्तव्य करना ही हमारा अधिकार है। कर्तव्य करो और अधिकार भूल जाओ। कर्तव्य करने के पश्चात् मुड़ कर मत देखो। यह न देखो कि कर्तव्य के पीछे हमारे अधिकार भी आ रहे

हैं या नहीं। नेकी कर और समुद्र में डाल। आज हम अभी तो पहली सीढ़ी पर हैं जहां केवल अधिकार हैं। उसके पश्चात् अधिकार और कर्त्तव्य का समन्वय हम को करना पड़ेगा। यह दूसरी सीढ़ी होगी। तीसरी और अंतिम सीढ़ी जो होगी उसके मुताबिक केवल अन्त में कर्त्तव्य ही कर्त्तव्य रह जाएंगे और उस समय हमारा गीत होगा, बुराई के बदले भलाई किए जा। यदि अचानक लड़ाई हो जाती है तब ईंट का जवाब पत्थर नहीं होगा, थप्पड़ का जवाब गाल होगा। दो व्यक्तियों में भी वार्तालाप हो तो पहले आपकी आवाज सुनाई देगी। लोगों की आवाज नहीं होगी।

भारतीय संविधान की आधारशिला गीता के इस आदर्श पर स्थापित हो, यही मेरी कामना है। मैंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है जिसका नाम है "मौलिक अधिकार भूल गये"। मौलिक अधिकार याद रह गये, मौलिक कर्त्तव्य भूल गए। "फंडामैंटल राइट्स एमर्टेड, फंडामैंटल ड्यूटीज फारगौटन"। इसकी एक कापी मैंने प्रत्येक मैम्बर को दी है। हमारे सदस्य इसको पढ़ सकते हैं, आशा है इससे कुछ प्रेरणा मिलेगी।

अन्त में एक बात मैं यह कहना चाहता हूं—राष्ट्र को राष्ट्र नहीं कहते, बल्कि राष्ट्रीय एकता को राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्रीय एकता गई तो राष्ट्र गया। वह राष्ट्र न रह कर भीड़ बन जाता है। भीड़ पहले भेड़ों की हुआ करती थी, इसलिये उसका नाम भीड़ पड़ा। बाद में मनुष्य भेड़ों की तरह इकट्ठे होने लगे तो उनको भी भीड़ कहने लगे। भारत को भीड़ नहीं राष्ट्र बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह विनम्र विनती माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हमारे संविधान को रि-ड्राफ्ट करना पड़ेगा और उसके अन्दर फंडामैंटल राइट्स के साथ साथ फंडामैंटल ड्यूटीज को भी अटैच करना पड़ेगा, तब हमारा देश आगे बढ़ सकता है।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Burdwan): Mr. Chairman, Sir, starting from the Address of the President to the speech which we have heard just now, an attempt has been made to justify the Emergency on the basis of vague generalisations and mere abuses and vilification of the Opposition parties without specifying the supposed treasonable activities on the part of the Opposition parties. I am very sorry that having been swayed by emotions and probably encouraged by the presence of the Prime Minister, a sober and responsible Minister as we thought him to be, Mr. Chandrajeet Yadav himself chose to use this occasion to vilify the CPI(M) wholly on a wrong and mis-leading basis because, realising that they cannot justify the Emergency on any positive ground, the best thing is to go on beating the Opposition with whatever stick comes handy. That is why, it was said that there has been a sort of a ganging up between the right reactionaries and the CPI (M). Sir, it is known that this is wrong and that this is an absolute calumny. What has been done? Only on a very important issue like the civil liberties, there had been cooperation and we, Sir, certainly support anybody or seek the support of anybody who will raise their voice of protest against the deliberate denuding of the personal and civil liberties in this country by a repressive Government. Whoever will come and support us, we shall certainly seek their support and give mutual support. This is done only on this basis.

Now, Sir, as Miss Patel rightly said, when BLD people join Congress they become progressives over-night. When ex-rulers and ex-zamindars joint or join the ruling party, they certainly become progressives. When Swatantrites and when Jan Sanghis join the Congress, they became progressive. Do not apply such double standards everywhere. This is my request.

You have declared Emergency. The people of the country know why. You

[Shri Somnath Chatterjee]

declare Emergency on the plea of internal disturbances, when there was already an Emergency. Because of the powers under the Constitution of India, which you wanted to exercise or which you did not want to take the trouble of having obligations under, you could do it under the existing Emergency of 1971 All the powers, the Defence of India Rules and so on, have not been promulgated now. They were actually promulgated in 1971 and this is now being used under the new Emergency Not a single extra constitutional power was obtained by proclaiming this new Emergency Then, what was this Emergency for? Was it for economic reasons? Then, there is a specific provision under the Constitution, Article 360, for declaring a financial emergency You did not take recourse to that. When there was rampant inflation, when the whole economy was out of gear, as Dr Rao has said as he has reminded us, when the Government of India was not functioning so far as the finances of the country were concerned you did not take recourse to financial emergency And what emergency powers for internal disturbance are necessary to meet an economic situation? Sir, 'internal disturbance has been used as a plea because the position of a particular individual became at stake This is the reality It should be understood I am sure hon members opposite realise it in their own heart of hearts But they cannot say so The press in this country has been gagged The Opposition has been mercilessly gagged Their own people have been gagged Today the whole intention has been to create a fear psychosis in the country to bring about a feeling of terror in the minds of the people People are not allowed to open their lips. This is a stark reality in this country No good denying it. If you deny it, you are denying it for the purpose of record only not in your own heart of hearts.

What I was asking the Government, the Prime Minister and others was this What extraordinary powers did you need for which a second Proclamation was made? Now, if there was internal disturbance alone, why have you brought out so many other justifications, please, for this emergency? How can you, so to say, take the pretext of financial difficulties? How can you take the pretext of late running of trains for internal disturbance? This party has been in power since independence in this country If the trains had not been run in time, it is very easy to go on blaming the workers Why have you not been able to inculcate a sense of discipline among the workers? Why have you not been able to make them feel part and parcel of this country make them feel that they are one with the administration? Why are they alienated from you? Why are the common people alienated from you? You have no answer You never ask yourselves those questions For everything that is not happening properly in this country, an emasculated Opposition is supposed to be responsible You ridicule the opposition and say "They people are not with you' but you hold that every emasculated and miniscule Opposition, according to you supposedly responsible for the ruination of this country You have been in uninterrupted charge of the government of the country You have not delivered the goods to the people Poverty has been accentuated People's miseries have increased a hundredfold, and you say you are not responsible for that

That is why I say that your right to govern this country now is based on repressive powers. You cannot function without Draconian laws. You cannot function under ordinary laws of the country The Constitution of India which 25 years ago had been commended to the country by no less a person than Jawaharlal Nehru, that Constitution does not suit you, because

it gives some powers even now to the people of the country. You do not like the people of this country to have any power. You do not want that the people of this country can raise a voice of protest? That is why you have come up with proposals, those obnoxious proposals, like that are being circulated, the source of which has not been denied.

As I was saying, if discipline was the reason, then a false reason has been given in the Proclamation of Emergency that internal disturbances were there which threatened the security of the country. If Mr. Jayaprakash Narayan had been guilty of treason, try him for treason. Give him exemplary punishment under the laws of the land. If Morarji Desai, or for that matter any person, has been guilty of sedition try him. Give him an opportunity Let the people of the country know. Mr. Jayaprakash Narayan has been arrested. He is a Right reactionary. In the name of fighting fascism and Right reaction, you have arrested MPs like Mr. Jyotirmoy Bosu and Mr. Noorul Huda. Do they belong to Right reactionary parties? You have arrested trade union workers You have dismissed trade unionists, government servants, under MISA. You have detained them You have dismissed them under art. 311(2) without even letting them know what is their wrong. It is, therefore, very easy. Even the present Constitution, as it stands today, gives enormous powers to the Government A government servant can lose his job in a minute. A person can be kept in detention indefinitely. Even his right to move the court is extremely limited What have you done? You are afraid to face the people. The Supreme Court of India has given clearance to the Prime Minister's election. One of the Judges who upheld her election had made an observation. I do not know whether she has had the time to go through the judgement which has been delivered in her own case. Mr Justice Chandrachud has observed that law should not be what the king emperor thinks is law; it should be decided in the anvil of constitutionality; it should be tested on the principle whether it is for public good. One of the Supreme Court Judges who had held in her favour has reminded the people of the country that it was not the attitude. Today an attempt is being made to stifle popular and democratic movements and stifle the ventilation of the people's grievances. If I say something here which is not to your liking, the people outside will not know; they do not know that there is another version possible on a particular issue People may think: we have sent him to Parliament: we want to know whether our representative toes the line of Government or he has some alternative proposals to make. But now people will not know. Look at today's papers and see how Mr. Samar Mukherjee's speech had been reported. It is a travesty of reporting parliamentary proceedings. Is this the way you are going to take the country along the path of progress?

Mr. Chairman, I want to make this appeal to the hon. Members opposite through you: do not feel that patriotism is your monopoly; or the desire to do good to the country is only your monopoly. We are as much anxious that this country should be governed and governed properly; we want that this country should proceed on right lines, if my line is a little different does it mean that I do not have patriotism? If I do not want the zamindars, the landed gentry and the black marketeers to control our country, does it mean that I am not patriotic? If I want to say something which the people of the country want me to say should I not be allowed to say? If a judge delivers a judgement which you do not like, you say that the judge is wrong and therefore you want to take away the court's powers. Why are you so arrogant? You do not want anybody to judge your action. Why should not the judges decide whether you do something rightly or wrongly? It is a system which has worked for

[Shri Somnath Chatterjee]

so many years. Take the last amendment of the Constitution which this Parliament adopted. We were willing parties to it. We had been demanding that the Constitution should be so amended that no vested interests can take advantage. We have enlarged the powers under article 31 of the Constitution; we have given enormous powers to the Government. But how has this Government utilised those powers? What legislation has stood in their way? How have the courts stood in their way? In the way of any single welfare legislation? We on this side have extended our support even to a capitalist and reactionary government as this when they thought of welfare legislation. Whether they were implementing that or not, we had extended them full support. Let them give one example of one single welfare legislation which had been held up by us in Parliament? I challenge them. On the other hand, in the name of bringing about a balanced society, egalitarian society and welfare and socialism in this country, they have reduced the quantum of bonus without reducing the cost of living. They have taken away the rights of the workers even to hold meetings and demonstrations. They have not even the right to go to their managers to ventilate their grievances. There is a case in regard to Bank of India, I am not going into merits because the matter is *sub-judice*. It is a nationalised bank and I want to tell the hon. Members what happens there. The authorities there issued a circular deducting the salaries of the employees, because their representatives had gone to a meeting with the manager for ventilating employees' grievances who even entertained them. But after the meeting the manager issues a notice to them: you did not work during the time you came to see me and therefore you are not entitled to wages for that period.

Is this the way of getting the willing co-operation of the ordinary people of this country? Is this the way you want their participation in your so-called nation-building? Mr. Chairman, Sir, the position is this. In the garb of emergency, what is being sought to be done is to create and maintain a hegemony. We are opposed to that. The attempt is to create and maintain a particular attitude of Government which is not in tune with the national aspirations of this country. You are utilising this not for the betterment of the people because the inflation has been contained. It is said that Emeregncy should remain and continue not because of inflation but because of other economic reasons and therefore elections should not be held. See how the reason is put forward by this Government. Sir, what is the position in the economic field? What is the position in the small industries, small-scale industries like bulb manufacturing industries? Mr. Maurya is here. He has got the statistics fully. The small-scale industries are almost closed down. The wagon building industries in West Bengal are completely at a stand-still. J. K. Aluminium is being closed. Hindustan Motors have introduced a rotational system of lay-offs of the employees.

Now, who is coming to their protection? Are you using Emergency powers against the management of Hindustan Motors? You have got all the powers under the Sun. You don't care for the people's rights under Article 19 and under Article 14 you have suspended them. But you have not suspended Article 31 which guarantees property rights. You have forbidden my right to form an assembly and the right to free speech. You have taken away my right of equality to be treated equally amongst equals. But you have not taken away the right of the propertied class. That is why Article 31 has not been touched. This is the true position of this Government.

Sir, in the jute industry, what is happening? Concession after concession has been made but lay-off and

closure are continuing. More lay-offs and more closure and more retrenchment are continuing. Now, are you using your unlimited emergency powers against these closures, lay-offs, lock-outs and retrenchments? Not a single instance. In the Jute Mills, even the jute growers are not getting concessions. Conceshions have been given to the jute mills but jute growers are not getting even the support price. Same is the thing with regard to the Textile Mills. In those mills which have been taken over by the Textile Corporation, the workers are extending all support, not a single complaint has been made against workers. They are doing extra work. But they are in doldrums because the management is still as bad as it was. There is a huge stock piling. No attempt has been made to have the stocks cleared. The retailers cannot even take them, far less the consumers because of high cost of textile goods.

Sir, this is the position in this country and we are only told that something was being done for which Emergency must be imposed Therefore, I request my friends, through you Sir, with all sense of responsibility do not take the people of this country for a ride. Try to do something good for them. If the people are with you, why are you afraid of them?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) सभापति जी, राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ है, मैं उस का हृदयपूर्वक समर्थन करता हूं । अभी थोड़ी देर हुई हमारे शमीम साहब ने भाषण किया था—वह इस वक्त यहां मौजूद नहीं हैं—ऐसा मालूम पड़ता है कि उन को न किसी का भाषण पढ़ने की इच्छा है, न सुनने की इच्छा है, बस सिर्फ मनमानी बोलने की इच्छा है । मैं उन के लिये ो अशआर कह कर अपना भाषण शुरू करूंगा,—

मगर ऐसे नादान का क्या ठिकाना,
जो दर्द ही को दवा जानता है,
जो समझाये कोई बुरा मानता है,
बुराई को अपनी भला मानता है ।

इस देश में क्या हो रहा है —उनकी समझ में नहीं आ सकता । अगर कोई समझाये तो बुरा मानते हैं और उस की बुराई को अपनी भलाई मानते हैं । इस लिये उन के साथ वहस करना फिजूल है । इस लिये अब मैं अपना भाषण शुरू करता हूं ।

हमारे श्री सोमनाथ चैटर्जी ने अभी फरमाया था कि देश में अपोजीशन की तरफ से तरक्की के कारणों में कोई रोडा नहीं अटकाया गया है । मैं उन की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं—सीपलिस्ट पार्टी आफ़ इण्डिया का क्या काम था—जिस वक्त से देश को आज़ादी मिली, उन का काम यह था कि जहां कहीं भी अंग्रेजी के शब्द लिखे हुए हों, उन को मिटाना । इस के सिवाय उन का और कोई नजरिया नहीं था । डी० एम० के० का काम यह था कि जहां कहीं हिन्दी के शब्द नजर आयें उन को मिटाना । जनसंघ का क्या काम था—100 मील के किराये में अगर 25 पैसे का भी इज़ाफ़ा किया जाय तो सत्याग्रह करना, रेल की पटरी पर बैठना । कम्यूनिस्ट पार्टी आफ़ इण्डिया क्या करती रही है —वह भी सुन लीजिये —1974 में पूरे 365 दिन उन्होंने हड़ताल कराने की कोशिश की—यह अपोजीशन का नक्शा रहा है, तरक्की के हर काम में उन्होंने रुकावट डाली । इसी लिये प्रधान मंत्री जी ने कहा था—1965 से 1975 तक पूरे दस सालों में दस दिन भी ऐसे नहीं मिले, जब कि कुछ शान्ति से किया जा सके । यह रवैया हमारे अपोजीशन का अब तक रहा है, यह इन की हिस्ट्री है । इसी लिये प्राइम मिनिस्टर ने मजबूर हो कर 25 जून को एमरजैन्सी लागू की ।

[श्री एम० राम गोपाल रेड्डी]

अब यह कहना कि अपोजीशन के लीडरों को जैल में रखा गया है— यह सही नही है। अपोजीशन के लीडरों को जेल मे नही रखा गया है, गैस्ट-हाउसेज में रखा गया है, हमारे स्वर्गवासी शमीम के देश मे रखा गया है वे अपने कश्मीर को स्वर्ग समझते हैं—इस लिये श्री एल० एन० मिश्रा को स्वर्गवासी बनाया है वहा उनको हर तरह की सुविधा दी गई है ताकि वे लोग अपनी आत्मकथा इत्मिनान के साथ लिख सके, अपने सस्मरण मैमायर्स लिख सकें और वे लोग लिख रहे है इन्ट्रास्पैक्शन कर रहे है कि हम ने देश मे पिछले 25 सालो मे जो काम किया है, वह अच्छा किया है या गलत किया है। इस को सोचने के लिये ही ऐसी जगह मे रखा गया है और मैं उम्मीद करता हू कि वे लोग इस नतीजे पर जरूर आये होंगे कि पिछले 25–27 सालो म इस देश मे उन्होने जितनी बद-खिदमती की है, हानि पहुचाई है, उसी का नतीजा है कि हमारे ऊपर एमरजेन्सी लगी हुई है, इस के लिये इन्दिरा गान्धी की गवर्नमेंट पर या उनकी पार्टी पर कोई दोष नही है।

मैं पूछना चाहता हू कि देश के कल्याण के लिये आपने कौन से कदम उठाये है। यह कहना कि हम ने हर उस मेजर का स्पोर्ट किया है जो देश के कल्याण के लिये यहा लाया गया, तब फिर मैं पूछना चाहता हू— रोजाना इस सदन मे तीन-चार घटे तक जो चीखो-पुकार होती थी, क्या वह देश के हित मे थी। आज हमारे सोम नाथ चटर्जी और दूसरे लोग जिस तरह से आर्ग्यूमेन्ट्स कर रहे हैं क्या वे उसी तरह से पहले नही कर सकते थे? उस वक्त तो आर्ग्यमेन्ट्स का तरीका डिस्कशन का तरीका छोड़ कर हुल्लडबाजी का तरीका अख्तियार किया गया था। आप ने उस वक्त क्या किया था—विद्यार्थी वर्ग को अपने स्कूल जाने से रोका, उन को एक्जामिनेशन मे बैठने से रोका उन को नकल करने के वास्ते मजबूर किया, देश मे हर तरफ बदुनजमी फैलाने की कोशिश की, यह सब गवर्नमैन्ट की लीनिएन्सी की वजह से हो सका। इसी लिये हमारी प्रधान मत्री जी ने कहा—हम लोगों को आज जो सुविधाये मिली है आजादी मिली है उस का नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इस वास्ते इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। इमरजेंसी के बाद पहली दफा 25 साल मे देश सही रास्ते पर चल रहा है। हर आदमी समझता है कि देश के वास्ते उसे कुछ काम करना है आज आप मजदूरों का सहारा लेकर उन की बात कर रहे है। क्या हम मजदूरों के लीडर नही है केवल आप ही है? यह विचार आप का गलत है। हमारी पार्टी आल इडिया पार्टी है हम भी उन की नमाइन्दगी करते है।

यह कहना कि हम लोग चुनाव से डरते है, गलत है। आप देखिये कि गुजरात मे अपोजीशन की सरकार है लेकिन वहा जो हाल मे चुनाव हुए हैं उन मे विरोधी दल हार गये हैं। तो हम चुनाव से डरने वाले नही है। काग्रेस का हर आदमी समझता है कि चुनाव एक मेरफुल नेसैसिटी है। हमारे क्षेत्र के लोग कहते है कि अगर चुनाव हो तो आप लोग ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। लेकिन हम चाहते है कि जो रेलगाडी पटरी पर चल रही है और देश का कल्याण हो रहा है इस वास्ते छोटे मोटे इलेक्शन के चक्कर मे न पड़ कर, उस का लक्ष्य न कर के एक साल के लिये हमारी पार्टी ने चुनाव का पोस्टपोन करने का सुझाव दिया है।

एक नई चीज है जिस को बहुत से सदस्य नहीं समझते होंगे और वह यह कि जितने हमारे हार्बर्स हैं वहां जगह जगह गोदाम बने हुए हैं जिनका इस्तेमाल स्मगलड

गुड्स बाहर से लाने और ले जाने के वास्ते होता है । मैं चाहता हूं कि हमारा शिपिंग मंत्रालय इस ओर ध्यान दे और ऐसे गोदामों को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये जिस से उन का उपयोग शुगर ऐक्सपोर्ट के लिये और फर्टिलाइजर के इम्पोर्ट के लिये किया जा सके । जब तक गोदाम खाली रहेंगे तो उन में सामान रखा जायगा ।

हम शुगर ऐक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं । 1200 करोड़ रुपये का तेल हर साल हम इम्पोर्ट कर रहे है । तो निर्यात भी चीनी का 1200 करोड़ रुपये का होना चाहिये । लेकिन अभी 600 करोड़ रुपये का ऐक्सपोर्ट शुगर का हो रहा है जो बहुत कम है । मैं चाहता हूं कि सरकार ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर के शुगर ऐक्सपोर्ट को बढ़ाये ।

एक और बात है कि जो शुगर फैक्टरीज कोआपरेटिव सैक्टर में आ रही हैं और जिन की लागत 2 करोड़ या उस से ज्यादा है उन के वास्ते कुछ कन्सेशन्स दिये जा रहे है । अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर के 2 करोड़ से कम खर्च करता है तो उस को कंसेशन्स नहीं मिल रहे हैं. सम्पत कमेटी के अनुसार इस बारे में मेरा निवेदन है कि आप को एक क्वास डेट मुकर्रर करनी चाहिये उस के बाद से जितनी भी शुगर फैक्टरीज आये देश में उन सब को मसावी तरीके से वह कंसेशन्स मिलने चाहिये । अगर ऐसा नहीं होगा तो शुगर इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी, उस का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा और आप ऐक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर सकेंगे । इसलिये जो भी कंसेशन्स नई शुगर फैक्टरीज को सम्पत कमेटी के अनुसार मिल रहे है वह सब नई कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज को मसावी तरीके से मिलने चाहिये । 2 करोड़ रुपये की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये । अगर आप मेरा सुझाव मानेंगे तो इस से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और काफी विदेशी मुद्रा हम को मिलेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) अध्यक्ष महोदय मैं कल से अपोजीशन और रूलिंग पार्टी के सदस्यों के भाषण सुन रहा हूं । आरोप और प्रत्यारोप यही मैं देख रहा हूं और किसी ने कोशिश नहीं की कि स्थिति को सुलझाया जाए । मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि अब मामला शान्त किया जाए । जय प्रकाश जी को छोड़ दिया गया तो कोई आसमान नहीं टूटा । महताब जी को भी छोड़ दिया गया और उन्होंने जय प्रकाश जी को लिखा है कि अब स्थिति बदल गई है जिस पर फिर से विचार किया जाए । आप इमर्जेंसी भले ही रखिये लेकिन अब समय आ गया है जब कि आप विरोधी दलों के नेताओं और दूसरे लोगों को छोड़े ताकि वे बैठकर सोच सकें कि इस स्थिति में क्या करना है । यह कोई आपके लिए शान की बात नहीं है कि सारे नेताओं को आप गिरफ्तार रखें । आप अगर यह चाहें कि वे आप से माफी मांगे तो ऐसा वे कर नहीं सकते हैं और यह संभव नहीं है । इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि इमर्जेन्सी भले ही कायम रखी जाए लेकिन नेताओं को छोड़ दिया जाए : मैं मानता हूं कि इमर्जेन्सी से बहुत फायदे भी हुए हैं लेकिन नेताओं को छोड़कर आप उनको मौका दीजिए कि वे सोच सकें कि अब इस स्थिति में क्या किया जाय । श्री जय प्रकाश जी को महताब जी ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि नई वर्तमान स्थिति को देखिये । इस तरह से लोगों के ख्यालात बदल रहे है और इसका फ़ायदा उठाइए और कोशिश कीजिए जिससे मामला सुलझ जाए । सब बड़े बड़े नेता जेलखानों के अन्दर बन्द है और जब तक आप उन्हें बन्द रखेंगी उस समय तक दुनिया में आपकी बदनामी नहीं मिट सकती । मैं समझता हूं कि देश का हित इस में ही है कि देश के नेताओं को जो देशभक्त है, जो देश के दुश्मन नहीं हैं, उन्हें आप छोड़ दें । अगर आपके काम

[प्रो० एस० एल० सक्सेना]

अच्छे हैं तो वे आपका समर्थन करेंगे। इमर्जेन्सी से बहुत फायदा हुआ है। देश में अनुशासन आया है, विद्यार्थियों के अन्दर जो शरारत थी वह खत्म हो गई है लेकिन यह सब डर के कारण है और अभी कोई उनके अन्दर चीज जमी नहीं है। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि एमर्जेन्सी को कायम रखिये। इससे फ़ायदे हुए हैं लेकिन नेताओं को जो देश के प्रति वफ़ादार हैं उनको आप छोड़िये। बाहर जाकर वे आपका क्या बिगाड़ लेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उनको छोड़िये। आज होता क्या है। जो आपके कारखाने हैं उनमें जो आपके अफ़सरान हैं, वे कितनी शरारत कर रहे हैं। हमारे गोरखपुर के अन्दर एक फर्टिलाइजर का कारखाना है। उसमें सितम्बर 1975 में और फिर नवम्बर, 1975 में आग लग गई। बड़ा हल्ला हुआ कि करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। बड़ा हल्ला हुआ कि मैनेजर नालायक है और टेकनिकल आदमी नहीं है। मैं वहां देखने के लिए गया और मैनेजर से मिला। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस मैनेजर के जमाने में जितना प्रोडक्शन हुआ था फर्टिलाइजर्स का उतना पहले कभी नहीं हुआ। आग लगने में मैनेजर का कोई कसूर नहीं है। मैंने जो इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, उस को देखा और उसने मुझे बताया कि यू० पी० स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कमीशन की रिपोर्ट पर अमल नहीं किया। कारखाने को लगातार पावर दिये बगैर काम नहीं चल सकता है और यह कारखाना नहीं चल सकता। या तो कारखाना अपना पावर हाउस लगाये या उसको लगातार बिजली मिले। ऐसा न होने से वह केबिल्स जल गये और इसलिए आग लग गई। मैं कहना चाहता हूं कि लगातार इलैक्ट्रिसिटी न मिलने के कारण ऐसा हो जाता है। अभी श्री नरसिंह नारायण पांडे ने एक सवाल किया था और उसका जवाब यह दिया गया है :

"High-powered committees were set up by the Corporation on both the occasions. The Committee found that the first fire on 13-9-75 was due to bursting of the power cable; and the second fire on 14-11-75 was due to non-observance of safety regulations."

केबिल बिजली सप्लाई टूट जाने से जले। मैं पूछता हूं कि आपने यू० पी० इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन को क्या सजा दी। जांच कमीशन की जो रिपोर्ट थी वह इम्पलीमेंट क्यों नहीं की गई। उसके इम्पलीमेंट न होने से यह आग लगी और अब भी फिर लग सकती है। मैनेजर ने कहा कि कारखाना चलाना बहुत ही खतरनाक है अगर बिजली ठीक तरह से नहीं मिली। इसके लिये जो प्रोपोजल्स रखे गये हैं और कमिशन ने जो बातें कही हैं उन पर अमल किया जाए।

मैं चाहता हूं कि कमिशन की रिपोर्ट पर अमल न करने के लिए यू० पी० इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के मेम्बरों और चेयरमैन को सजा दी जाए जिन्होंने इतनी बड़ी गलती की और जिसकी वजह से इतना भारी नुकसान हो गया है।

17.00 hrs.

आपका जो 20 प्वाइंट प्रोग्राम है, वह बहुत अच्छा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन इसमें गलत काम भी हो रहे हैं। मैं आपको अपने जिले की बात बताता हूं। वहां जमीन बंट रही है। लेखपाल, कानूनगो आदि लोगों से, गरीब हरिजनों से, लैंडलेस लेबर से सौ सौ रुपया घूस लेकर जमीन बांटते हैं। यह हो रहा है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। शिकायत की जाती है तो कोई सुनता नहीं है। इस तरह का जो भ्रष्टाचार है इसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। आज पुलिस सुप्रीम पावर में है। लोगों को डराती धमकाती है कि तुम्हें डी आई आर में, मीसा में बन्द कर देंगे। पुलिस के जुल्म बहुत बढ़ गये हैं। इस चीज की तरफ़ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। जो विरोधी पार्टियों के लोग हैं और जिनको

आपने जेलों में बन्द कर रखा है उनको आप मुक्त कीजिये । उनका यह काम है कि जो जुल्म होते हैं, जो ज्यादतियां होती है उनके खिलाफ आवाज उठाये । आपने उनको बन्द कर रखा है । फीयर का जो वातावरण फैला हुआ है वह ठीक नही है । मेरी प्रार्थना है कि नार्मल सिचुएशन चूंकि हो गई है इस वास्ते आप कोशिश करे कि उनको छोड दिया जाए । सब लोग आपकी मदद करेंगे देश को आगे बढाने में ।

श्री परिपूर्णानन्द पन्यूली (टिहरी गढवाल): राष्ट्रपति जी ने 25 जून को आपात्कालीन स्थिति की जो घोषणा की, और पहली जलाई को प्रधान मन्त्री जी ने बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की जो घोषणा की, इसके लिए सारा राष्ट्र उनका कृतज्ञ है । आपात्कालीन स्थिति में जहा देश मे अनुशासन की भावना पैदा हुई है वहा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम ने देश को प्रगति और उन्नति की ओर ले जाने में एक नया मोड दिया है । अगर आपात्कालीन स्थिति की घोषणा न हुई होती तो स्वेच्छा से छिपे हुए धन और सम्पत्ति की जो पन्द्रह सौ करोड रुपये की घोषणा हुई है न हुई होती । यह केवल उसके कारण ही सम्भव हुआ है । आपात्कालीन स्थिति का ही यह प्रभाव था कि कारखानों, स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और तमाम क्षेत्रों मे अनुशासन और चुस्ती आई ह । उत्पादन बढा है भावों मे गिरावट आई है । यह भी प्रसन्नता की बात है कि नौ सौ अरब रुपये से अधिक की पूंजी हमारे राष्ट्रीय-कृत बैंकों में जमा हुई है । कारखानों में काम करने वाले मजदूर वही है, वही सरकारी कर्मचारी हैं वही स्कूलों और कालेजों में पढने वाले छात्र हैं, सारा समाज वही है जो आपात्काल की घोषणा के पूर्व था । लेकिन सब मे जो तबदीली आई है वह आपात्कालीन स्थिति का नहीं तो किस चमत्कार का परिणाम है ? किस चीज ने समाज के प्रत्येक वर्ग मे अनुशासन का मंत्र फूंका है ?

विरोधी पक्ष के मुट्ठी भर लोगों को छोड कर जो आज हठधर्मी के कारण वास्तविकता को स्वीकार करने मे इन्कार करते हैं, सारा देश आज एमर्जेन्सी के महत्व को समझता है, इसके लाभों को समझता है और अनुभव करता है । जिन्होंने पहले इस एमरजेंसी की आलोचना की थी वे भी अब स्वीकार करने लगे है कि एमरजेन्सी से भारत को हर तरह से लाभ हुआ है । आर्थिक स्थिति मे सुधार हुआ है । इसका इससे बडा प्रमाण और क्या हो सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना मे इस साल पच्चीस प्रतिशत तक अधिक राशि की प्लान के लिए व्यवस्था की गई है । यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे साधन बढे हैं । इससे आशा बधती है कि 1976–77 के बजट मे 70 से 75 अरब रुपये तक की व्यवस्था की जाएगी ।

मार्क्सवादी पार्टी के एक सदस्य ने कल तथा दूसरे ने आज भी सरकार की एमरजेंसी नीति की आलोचना की है । कल श्री समर मुखर्जी ने आलोचना की थी सेंसरशिप की । वह इस बात को भूल गए कि ऐसा करते हुए व अपने तर्क को ही काटने लगे है । एमरजेंसी के दौरान जिन अखबारों ने सरकारी कामकाज की आलोचना की उन्होंने उन्ही अखबारों के समाचारों को उन्होंने यहा पर उद्धृत किया है । इसका अर्थ यह है कि सेंसरशिप के बावजूद अखबारों को उस सीमा तक आलोचना करने का अधिकार था जो कि न्यायपूर्ण है ।

मान्यवर, ये लोग इस बात को साफ-साफ क्यों नही कहते कि फ्रीडम आफ दि प्रेस के नाम पर ये उन गैर-जिम्मेदार अखबारों की हिमायत करना चाहते हैं जो

[श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली]

कि कीचड़ उछालते रहे है, जो कि विध्वंसक तत्वों को समर्थन देते रहे है और जो हमारे देश को आजादी को खतरे मे डालना चाहते थे। उनको मालूम होना चाहिए कि फ्रीडम आफ दी प्रैस के नाम पर वे कितने घडियाल के आंसू बहायें, उस गन्दी पत्रकारिता को, यैलो प्रैस को, हमारा देश तिलांजलि दे चुका है जो हमारे जनतंत्र को खतरे मे डाल सकता था।

राष्ट्रपति जी ने एक महत्वपूर्ण बात प्रशासन मे सुधार लाने के बारे मे और उसे चुस्त करने के बारे मे कही। मै पुन निवेदन करना चाहता हू कि एमरजेंसी के समय आप प्रशासन का जितना शुद्धीकरण कर सकते हैं, सम्भवत उसके लिये आगे मौका रहे या न रहे। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी प्रगति रुकने का एक बहुत बड़ा कारण यह रहा है कि दिशाहीन निष्ठारहित और ढीला प्रशासन हमारे देश मे रहा है जो कि हमारी विफलताओं के लिये बहुत कुछ जिम्मेदार रहा है। प्रशासन को जब तक चुस्त नही किया जायेगा तब तक जो लक्ष्य हमने निर्धारित किये है, वह पूरे नही हो सकते उदाहरण के लिये राष्ट्रपति जी ने घोषणा की है कि हम आगामी तीन वर्ष मे बर्थ रेट एक हजार पर 30 करना चाहते है। इसी प्रकार हमारे आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम है। उनकी उपलब्धि तब तक सम्भव नहीं है जब तक हम प्रशासन को शुद्ध और चुस्त नही करते।

मान्यवर, प्रशासन का इफैक्ट पिछडे हुए इलाकों मे सब से अधिक है। वहा आज भी प्रगति कछुए की चाल से हो रही है। मैं आपका ध्यान एस्टीमेट्स कमेटी की 69वी रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हू। पृष्ठ 116 पर उन्होने सिफारिश की है --

"The Committee stress that in the interest of bringing about rapid development of these areas, Government should review critically the existing personnel policies and practices in respect of these backward areas and post the best and most efficient officers with about 7 to 10 years' service to these areas. They should be assigned specific tasks the performance of which should be taken special note of for future promotion."

मैंने यह बात इसलिए उद्धृत की है कि एस्टीमेट कमेटी के रिपोर्ट के बावजूद और प्लानिंग कमीशन की टास्क फोर्स 1972 की रिपोर्ट के बावजूद आज भी इस दिशा मे कोई प्रगति नही हो पाई। एस्टीमेट्स कमेटी ने 70वी रिपोर्ट मे बैकवर्ड एरिया इडस्ट्रियल डैवलपमेंट कार्पोरेशन की स्थापना की सिफारिश की थी आज तक उस दिशा मे भी कोई कदम नही उठाया गया है। मै आशा करता हूं कि इस दिशा में सरकार कदम उठायेगी। राष्ट्रपति जी ने उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए कुछ कदम उठाने की घोषणा की है जो समाज की सब से नीची सीढी पर है, जैसे गावों मे खेतिहर मजदूर, स्माल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स है। आज एक तरफ कृषि का फैगमैंटेशन हो रहा है और दूसरी तरफ बडी भूमि वाले बड़े-बडे काश्तकार मुट्ठीभर ऐसे लोग हैं। जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि भूमिहीन किसान और मार्जिनल फार्मर्स गाव छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं।

तमिलनाडू का एक सर्वे अभी हाल ही मे समाचारपत्रों मे छपा है। मैंने कल के या आज के पेपर मे पढ़ा है कि वहां की फैक्टरी के 77 6 परसेंट मजदूर वगैरा पानी न मिलने के कारण गाव छोड कर अपनी उदरपूर्ति के लिए शहरों मे आये है। जो स्थिति तमिलनाडू की है वह देश भर मे है। इसमे कोई शक नहीं है कि सरकार पानी और टैक्नोलाजी की सुविधा देकर किसानों को कुछ वर्षों तक और

गावों के रहने दे सकती हैं लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक चलने वाली नहीं है। जब तक सरकार कोई स्थायी कदम न उठाये मैं समझता हूं कि इसका स्थायी हल निकलने वाला नहीं। इसके लिए गावों में ग्रामोद्योग और एग्रो इंडस्ट्रीज कायम करनी होंगी।

आज साबुन तेल कपडा बर्तन आदि सब चीजें शहरों में स्थापित कल-कारखानों में पैदा होती हैं। अभी एक माननीय सदस्य आप यहां रहे थे कि फलां फैक्टरी में ले-आफ कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि ऐसी फैक्टरियां कल नहीं आज बन्द हो जायें तो कोई हर्ज नहीं। वास्तव में ये आवश्यक वस्तुयें गावों में बननी चाहिए और किसानों को उन के उत्पादन का मौका मिलना चाहिए ताकि वे आत्म-निर्भर हो सकें।

हमारे गावों में रीसोर्सिज की कमी नहीं है। रीसोर्सिज में मैनपावर सब से महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

17 11 hrs

[SHRI G VISWANATHAN *in the Chair*]

सब से आवश्यक बात यह है कि रीसोर्सिज यूटिलाइजेशन की व्यूह-रचना स्ट्रैटेजी का एम्पलायमेंट जेनेरेशन के साथ अटूट सम्बन्ध होना चाहिए उन को एक दूसरे के साथ इन्टेग्रेट किया जाना चाहिए। उस को आधार मान कर हम को आने वाली पीढ़ी की शिक्षा पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि खादी कमीशन जैसी संस्थाओं को इस दिशा में आगे आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि खादी कमीशन एक बहुत बड़ा हाथी बन गया है हमारी बेरोजगारी दूर करने में जिस का कोई विशेष योगदान नहीं है।

अन्त में मैं कुछ बातें उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में कहना चाहता हूं, जिन का किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश और काश्मीर को जो पर-कैपिटा केन्द्रीय सहायता मिलती है वह काफी नहीं है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। किन्तु मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के पहाडी इलाकों को कम से कम उतनी पर-कैपिटा सैन्ट्रल एड तो देनी चाहिए जो इस समय हिमाचल प्रदेश को दी जा रही है। मैं समझता हूं कि मेरे दोस्त डा० कर्णसिंह और श्री महाजन, जो काश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आते हैं और सदन में उपस्थित हैं इस बात से सहमत होंगे कि उत्तर प्रदेश के पहाडी इलाकों के साथ अभी भी सौतेला व्यवहार हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि शासन इस ओर ध्यान देगा।

जहां तक उद्योग-धन्धों का सवाल है पहाडी इलाकों में—काश्मीर नागालैंड मेघालय और उत्तर प्रदेश के पहाडी इलाकों आदि में—रीसोर्सिज की कमी नहीं है। वहां नैचुरल रीसोर्सिज हैं और मैनपावर भी बहुत ज्यादा है लेकिन उन में कोई समन्वय नहीं है। उन इलाकों की तरक्की तब हो सकती है जब कि वहां के नैचुरल रीसोर्सिज मैनपावर और टैकनिकल नो-हाऊ को कम-बाइन कर के वहां पर रिसोर्स-बेस्ड इंडस्ट्रीज स्थापित की जायें।

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के समय से यह मांग की जा रही है कि टिहरी-गढवाल में एक घडी का कारखाना स्थापित किया जाये लेकिन अभी तक यह नहीं हो पाया है। मसूरी हिल्ज के पास लाइमस्टोन और मार्बल के डिपाजिट्स हैं। डा० कर्ण सिंह वहां के विद्यार्थी रहे हैं और उन को इस के बारे में पूरा ज्ञान है। लाइमस्टोन पर आधारित कैमिकल्ज फैक्टरीज वहां पर स्थापित की जा सकती हैं। मसूरी हिल्ज में राक फासफेट

[श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूर्ली]

के भी डिराजिट्स है। वहा पर एक फास्फेट का बनिफिसिएशन प्लाट लगाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इस ओर भी ध्यान नही दिया गया है ।

अन्त मे एक महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू। टिहरी का बाध द्वितीय पचवर्षीय योजना से खटाई मे पडा हुआ है । वह एशिया का सब से बडा और ससार का दूसरे नम्बर का बाध होगा जिस से देश को न केवल बिजली और पानी मिलेगा बल्कि उस बाध के निर्माण से मैदानी इलाका मे बाढ की रोक-थाम भी हो सकेगी ।

मैं निवेदन करना चाहता हू कि शासन को इस क्षेत्र के विकास की दिशा मे कदम उठाना चाहिए और वहा पर उद्योग-धन्धे स्थापित करने के अलावा जल-विद्युत योजनाओ को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए ।

इन शब्दो के साथ मैं इस धन्यवाद-प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हू ।

SHRIMATI T LAKSHMIKANTHAMMA (Khammam) Mr Chairman, Sir, my grateful thanks are to Shrimati Indira Gandhi, the leader of the Congress Parliamentary Party Shri D K Barooah, the President of the Indian National Congress and also the members of the Executive Committee for expelling us from the party, thereby saving us from being a party to some of the wrong doings, such, as, the continuance of Emergency the suppression of freedom of thinking of the people and that of the press and such other things

I have no animously or anger against them I have only pity for them.

असतो मा सद् गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मा मृतं गमय ।।

These are the only words that I can repeat and say, that the Almighty may lead them from darkness to light from untruth to truth and from hypocrisy to righteousness

Today the whole country is in gloom, whether it is expressed or not expressed Does one word come in the press about the health of Shri Jayaprakash Narayan? He is a great son of this country Nobody can deny that Every one is concerned about his health and asks 'How is he and what has happened to him?" While in jail, both his kidneys were affected They are not functioning now Why has such a situation been brought about? Is it the way you should treat this great son of India? Whatever may be your political differences or fight with him is it the way how you should treat him? Is this the way how the Britishers treated the prisoners? If they had treated them in this way then what would have been the condition of Pandit Jawaharlal Nehru or the other leaders in jail? They would not have been saved for us to lead this country after independence So let every one who has a conscience in him rise in revolt against this kind of treatment meted out to persons like Shri Jayaprakash Narayan and other prisoners, including some of the Members who are absent here My heart goes out to them The whole country is praying today for the recovery of Shri Jayaprakash Narayan I hope the all-merciful God will save him for this country and he will recover I am one who believes in the supremacy of truth Truth will prevail *Satyamera jayate* It is written everywhere Whether you recognise it or you just say that only—It is only on your lips— the fact remains that truth is a great power and you cannot curb it Truth does not need anybody's support to assert itself If you are on the path of truth, it is well and good be happy, I wish you all well But if you are on the path of untruth—you

may gloat over your temporary glory because all these things are temporary....

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: The whole word is temporary.

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA: Why do you intervene? You had your say. Hear at least what your leader has said. She has appealed for discipline. Please do not intervene.

As I was saying, truth will assert itself. What is written above the Chairs? *'Dharma Chakra Pravarthanaya'*. When the wheel of truth moves —it may move slowly, but when it moves—it will move with such force that it will crush the untruth underneath it. This kind of untruth and hypocrisy cannot be there for long. You can have your 20-point programme. It is good. But how can you implement it when the foundation is not strong? What is its foundation? Its foundation is not truth. Truth alone can produce sincerity, and sincerity alone can produce sincere implementation and good results. As long as truth is not there, as long as these things are built on the base of untruth, it will be like a building built on the foundation of sand and such a building is bound to fall down Nobody need tell you this because the power of nature is such. There are certain concepts. When the Creator created. He had certain principles. Maybe, truth and untruth are His playthings, but truth will ultimately triumph. *'Satyameva jayate'*. This has been said by the sages. It can never be wrong. I want them to beware of this because I still have my love for them. Let them realise this basic truth. Truth is powerful, and when you are not on the path of truth, you are bound to fall. Why should you fall? Still I do not want you to fall. You can rise up. You may commit mistakes; you might have got into a vicious circle because of certain circumstances. But you have to get out of this vicious circle to save yourselves from the situation created by this vicious circle of untruth. Then you can rise up. There is nothing wrong.

To-day I want to tell one thing. More than anything to-day we remember Pandit Jawaharlal Nehru. The red rose is fading. We want a revival of the red rose What did he stand for? He stood for democracy, freedom of thinking and freedom of the press and I think he was the greatest democrat in the whole world. But what has happened to-day? Let us once again wish that there is a revival of the red rose and the fragrance will be there in the whole world and the people will breathe fresh air as the great Tagore has said, where the head is held high and where you have the freedom to feel and express.

One has to be sportive in politics. Politics after all is not an end in itself. It is only a means to an end. For Gandhiji it was only a means to an end. Whatever you are talking of discipline—I think Mr. Sathe was in the Chair before you took over—Mr. Sathe is a close associate of Acharya Vinoba Bhave. What did Vinobaji say? He said, self-discipline is more important ... (*Interruptions*) Because Satheji always goes to his Ashram and I see statements in the Press in his name. What did Vinobaji say of discipline? Discipline is service. Self-discipline can be achieved by *Tapasya* or control of mind or meditation. Where the mind is full of desire, full of lust for power and you talk of discipline, what discipline does it produce? See the *Karmayogi* who works without any attachment. You do all your work without any attachment and without lust for power or the chair. Did Jayaprakash Narayan want any chair? This lust will only produce indiscipline. These are the basic concepts and truths which nobody can go against

[Shrimati T. Lakhmikanthamma]

because that is our culture which is inherited and embedded in the culture of this country. I think they are more powerful and they can assert themselves. What is discipline? How can discipline be produced? Only when you have the basic detachment and love for your people and for your country which Pandit Jawaharlal Nehru had, real love and real discipline starts, then only the real love for the country starts and then only you can implement all your programmes successfully. Please do it. I do not dispute it. You do it but when you do it, create this foundation base so that will be successful in your endeavour

Our friend was talking about Bhagwati Jagran. I request, him...

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): It is better that I have come here

SHRIMATI T LAKSHMIKANTHAMMA: I request him not to enter the field which he does not understand because one has to understand it.

I think this girl Shrimati Roza Despande's husband

SHRI K. GOPAL (Karur) She is a girl!

SHRIMATI T LAKSHMIKANTHAMMA . has produced some book which was banned by his party...

SHRI INDRAJIT GUPTA The hon. Member may better not talk about things which she does not understand.

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA: I am trying to understand, but I do not deny things. You know when they split atom and when they further split it, they found only consciousness. Even in the Communist countries they keep away from talking of spiritualism because they feel that there is something

MR. CHAIRMAN: The hon Member's time is up.

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA: We are five members in our Party.

AN HON. MEMBER: What is your Party?

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA: The Congress Party for Democracy, of course.

I request let us be sportsmen in politics. There should be 'talwar' in the hands of both who are to fight or are fighting. But here it is like a greedy woman who wants radio for herself, a T.V. and then a newspaper.

You said that no dog barked when all these people were arrested. Situation is normal. What happened when Shri Mohan Dharia was arrested? How can both the statements be correct—no dog barked, situation is normal, arrests are continuing? One of the two statements is wrong

Shri Krishnappa spoke yesterday and my reply to him is:

जो देश की आजादी को बचाने वाले हैं—उन के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता उन्हीं के भाई-बहिन मा-बाप की आजादी को छीन नहीं सकते।

Politics should not be an end in itself That should be means to an end. I can compliment Shrimati Indira Gandhi for one thing—she is a perfect politician. I think none of these men can beat her. When Ravana was dying, Rama asked Lakshmna to go to Ravana to find out what is politics. Ravana said, "I shall not tell you everything but one thing."

साम, दाम, दण्ड, भेद जैसे भी हो सब को इकट्ठा करो।

It is not a great thing to have power. The great thing is to retain power. This can be done by *Sam, Dan, Dund, Bhed.*

जैसा केरल कांग्रेस के साथ भी हुआ--

Either you become a Minister or go to jail. It is all right as a master of politics. But politics is not an end in itself. It should be means to an end --ultimately to lead to what Mahatma Gandhi said the whole of karmayoga was means to liberation. It was used without attachment He used karmayoga to attain higher realisation, realisation of truth. God, whatever you may call it. Unless you have the ultimate realisation you cannot have peace of of mind.

All these worldly things are there and we shall have to leave all these things here Ultimate aim is important. That is what brings peace for the world.

सर्वे जन सुखिनो भवन्तु ।

श्रीमती सावित्री श्याम (आवला) सभापति महोदय, मैंने श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुना । वे मेरी बड़ी अच्छी मित्र है और मुझे इस बात का दुख भी है कि उन्हें हमारी पार्टी से जाना पड़ा ।

उन्होंने आज अपना भाषण थर्ड और डिसिप्लिन पर दिया--मैं उन से पूछना चाहती हू--जिस समय श्री मोरारजी देसाई ने यह आवाज लगाई--इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद--कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिये, उस समय यह सच्चाई का पाठ उन को क्यों नही पढाया ?

क्या एक साधारण नागरिक को यह अधिकार नही था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से हार जाने पर वह सुप्रीम कोर्ट मे जाये और उस के फैसले को माने? उस समय माननीय सदस्या ने यह पाठ मोरारजी भाई को क्यों नही पढ़ाया कि आप को यह नही करना चाहिये । इसी तरह से जब जयप्रकाश नारायण बिहार और सारे देश के अन्दर यह कह रहे थे कि बच्चो को स्कूल छोड देने चाहिये, असेम्बली के सदस्यो को इस्तीफा दे देना चाहिये तथा पुलिस और मिलिटरी को सरकार की आज्ञा नही माननी चाहिये तब श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा, जो आज सरमन देने खड़ी हुई हैं, ने जयप्रकाश नारायण को यह बात क्यो नही कही कि ऐसा उन को नही कहना चाहिये ।

जहा तक जेल मे रहने की बात कही गई, मैंने कुमारी मणिबेन पटेल का भाषण भी सुना जब उन्होंने कहा कि जेल के अन्दर बहुत तकलीफ है, तो मैं इस से सहमत नही हूं । अभी अभी उत्तर प्रदेश के एक नेता जो जिन्दगी भर कांग्रेसी रहे हैं, वह जेल से वापस आये हैं उन्होंने बताया कि वहा काफी आराम हैं, जिस से मुझे काफी प्रसन्नता हुई और आश्चर्य भी हुआ । सभापति महोदय, आप ने स्वय अनुभव किया होगा कि जेलो के अन्दर कितना आराम है, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को कोई पाबन्दी नही है, वहा जा कर उन को लिखने पढने का आराम मिलता है ।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने हमारा आह्वान किया है कि हम अपनी जिम्मेदारिया और कर्त्तव्यो को समझे । अगर हम चाहते हैं कि देश से गरीबी मिटे, जो लोग सदियो से दबे हुए हैं वह ऊपर आयें तो हम को अनुशासन से रहना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी । इस के लिए उन्होंने सारे देश का आह्वान किया है ।

किन स्थितियो मे इमरजेंसी लगाई गई, यह किसी से छिपा हुआ नही है । साधारण जन-जीवन अस्तव्यस्त था न बच्चे स्कूल जा सकते थे, न महिलायें आजादी के साथ बाहर निकल सकती थी, न कोई पढ सकता था । क्या साधारण जीवन का अस्तव्यस्त करने का किसी का अधिकार हो सकता था नहीं इसलिये इमरजेंसी लागु की गई ।

20 सूत्री कार्यक्रम नया नही है । कई बार हम ने कांग्रेस सेशन मे इस की घोषणा

[श्रीमती सावित्री श्याम]

की है और लागु करने की कोशिश भी की है। लेकिन ज्यो ज्यों लागु करने की कोशिश करते थे तो कदम कदम पर विरोधी दलो की तरफ से रोड़े अटकाये जाते थे ।

मैं मानती हू कि जब किसी को न्याय दिलाते हैं तो किसी को अन्याय भी मिलता है, खासतौर से उन लोगों को जिन के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं । वही रास्ते मे आये और रुकावटे डाली । इसलिये इमरजेंसी लागू करनी पडी। जब तक अनुशासन में रहने की देश को आदत न पड जाये तब तक इमरजेंसी को रखना चाहिये ।

17.34 hrs.

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

सभापति जी, काग्रेस पार्टी का एक प्रोग्राम है, उस ने देश की बागडोर को हाथ में लिया है और वह जनता के प्रति जिम्मेदार है । उस ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, हालाकि हम को कठिनाइया आती रही जैसे सुखा पडा, बाढ आयी, लेकिन काग्रेस पार्टी ने उन का मुकाबला किया और उन समस्याओं को हल किया । आज भी मजबूत लीडरशिप का यह तकाजा है कि सारे देश को एकता के सूत्र मे बंध कर अपनी मुसीबतों को दूर करना चाहिये ।

मैं मानती हू कि इमरजेंसी मे बहुत ज्यादा ताकत ब्यूरोक्रेसी के हाथ मे चली गई है । ऐसा नही है कि सरकारी कर्मचारियों का सहयोग नही मिल रहा है । लेकिन फिर भी कही कही कुछ ज्यादती होती है, और उस को हम अपने क्षेत्र मे भुगत रहे हैं । लेकिन जब हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को देश की मेन स्ट्रीम के साथ आना होगा और उन को देश के साथ चलना होगा ।

मैं दो तीन बातों की तरफ आप की आज्ञा से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । सब से पहले इस प्रोग्राम मे देश की गरीबी को हटाने का, गांवों की गरीबी को मिटाने का पैगाम है यानी हजारों की संख्या मे हमारे देश क्षेत्र मे और लाखों की संख्या में इस देश में जिन के पास जमीन नही थी और जो खेती का काम करते थे, उन को जमीन के पट्टे बाट दिये गये । जमीन से पट्टे देना बहुत अच्छी बात हुई । जिन लोगों के पास सरप्लस जमीन थी और ग्राम सभाओं की जो जमीन थी, वह उन को दे दी गई है लेकिन वे ऐसे टुकडे है जो कि पानी से बहुत दूर है । सभी जगह ऐसा है, मैं यह नही कहती लेकिन जहा पर पानी नसीब नही है उन को पानी दिया जाए । जब देश के अन्दर हम ने पैदावार को बढ़ाया है माडर्न टेक्नोलाजी से और परमात्मा की कृपा से, जैसा कि कहा गया वर्षा भी हुई, तो ऐसे लोगों को भी पानी मिलना चाहिए । वर्षा का हम ने आर्टिफिशयल इन्तजाम नही किया है लेकिन भगवान की कृपा से अच्छी वर्षा हुई और फसल अच्छी हुई । भावों को गिराने के लिए भले ही हम यह कहें कि हम बाहर से अन्न मगाएगे लेकिन वास्तव म आज हम इस स्थिति मे हैं कि हम को अन्न मगाने की जरूरत नही है । अन्न के मामले मे आत्मनिर्भर हम माडर्न टेक्नोलाजी और किसान की मेहनत से हो सकते है । वे जमीन के टुकडे जो छोटे छोटे लोगों को मिले है, उन लैंडलेस लोगों को मिले है जो खेती पर काम करते हैं, वे बैरन हो जाएगे और उजड जाएगे अगर उन को पानी नही मिलता है और यह राष्ट्रीय क्षति होगी । बाहर से अन्न मगाने से बैलेस आफ पेमेन्ट भी बढेगे । इसलिए मेरा सुझाव यह है कि राज्य सरकारों को ये आदेश दिये जाए कि जिन लोगों को जमीने मिली है उन को सब साधन जैसे कि बीज, पानी, फर्टिलाइजर्स मुहय्या किये जाए, जिस से वे अच्छे रिजल्ट दे सकें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों ने माडर्न टेक्नोलाजी को अपनाया और ज्यादा अन्न पैदा किया लेकिन रा-मटीरियल्स जो हैं वे किसान पैदा करता है, खाना जो है वह किसान पैदा करता है लेकिन आज हम देखते हैं कि इन्डस्ट्रियल रा-मैटीरियल्स की कीमत सस्ती है लेकिन उन से बने हुए सामान की कीमत महंगी है । इस का मतलब यह है कि जो मेहनत करता है, उस का जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है, जितना मार्जिन आफ प्रोफिट उस का होना चाहिए उतना उसका नही है । सरकार ने यह निश्चित किया है कि 105 रुपये क्वीटल के हिसाब से गेहू लिया जाएगा लेकिन सरकार ने उतना गेहूं लिया जितनी उस को जरूरत थी और बाकी गेहू किसान के पास छोड दिया गया । मैं ने हापुड़ की मडी में देखा है कि वहां पर 90 रुपये क्वोटल के हिसाब से गेहू बिका है ।

इसी तरह से रुई को हालत है । अबहोर और फाजिल्का में रुई की बहुत ज्यादा पैदावार होती है लेकिन वहा पर तीन और चार रुपये प्रति किलो रुई बिकती है लेकिन मैं यह देखती हू कि उस मे जो कपडा बनता है, मुझे ज्यादा इस बारे मे मालूम नही है कि क्या क्या बनता है, लेकिन खद्दिया, पापलीन और लट्ठा आदि जो कपडे है उन की कीमते नही गिरी है ।

इसी तरह से गन्ने की कीमत की बात है । किसान जो गन्ना पैदा करता है अपनी मेहनत से, अपने प्रोत्साहन मे और सरकार की मदद से, उस को उस की कीमत नही मिलती । तो समय का यह तकाजा है कि किसानों के खेत जो छोटे छोटे बट गये है उन को अच्छी कीमत मिलनी चाहिए । बडे बडे फार्म अब कम रह गये हैं और यह दूसरी बात है कि कुछ लोगों ने मिल कर अपने खेत बड़े कर लिये हों । इस तरह से एक तालमेल होना चाहिए कि इतनी कीमत किसान को मिलेगी और कन्ज्यूमर को इस भाव से चीज मिलेगी और जो मार्जिन आफ प्रोफिट होगा, वह कितना होगा । यह एकोनामी जो है, अर्थ-व्यवस्था जो है, यह वन-साइडेड पिक्चर है । एक इनटेग्रेटेड पिक्चर को रख कर ही प्रोग्राम को चलाना होगा ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि इस में सदेह नहीं है कि इम्जेन्सी के बाद से, बीस सूत्री कार्यक्रम के बाद से हमारे देश की राष्ट्रीय इन्कम 6 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है ।

हमारे पब्लिक सैक्टर में 15 प्रतिशत से अधिक की उत्पादकता बढ़ी है । चीजें सस्ती हुई हैं । आर्थिक कड़ाई जो बरती गई है उसके कारण हमारी हालत सुधरी है । मैं किताबी बात नही करती । मैं महसूस करती हू कि किताबें पढ़ने से कोई ज्यादा लाभ नहीं होता है । हमें इन्सान को पढ़ना चाहिए, इन्सान की आवश्यकताओं को पढ़ना चाहिए, समाज को हमें देखना चाहिए । वह आदमी जो बोल नहीं सकता है, कह नहीं सकता है, आप तक पहुंच नहीं सकता है, जो मूक है, जिस की जबान नहीं है, जो गूंगा है, वह क्या कहता है उसको आपको पढ़ना चाहिए, वह क्या चाहता है इसको आपको देखना चाहिए और इसकी आपको पूर्ति करनी चाहिए । आज डिमाड घटी है, इसका कारण क्या है, इसको आपको देखना होगा । हो सकता है कि लोगों को परचेजिंग पावर घटी हो और उस कारण से डिमांड घटी हो । ब्लैक मनी उनके पास नही रहा, होर्डिंग खत्म हो गया है होर्ड करने की ताकत नहीं रही है, इस वास्ते डिमाड घटी हो और उसकी वजह से स्लैकनैस आ गई हो डिमांड मे । लेकिन मे बडी चीजों की बात नहीं करती, उन लोगों की बात नही करती हूं जो टी वी, फ्रिज इस्तेमाल करते है और न मैं इन चीजों की बात करती हूं । लेकिन आप बरतनों की

[श्रीमती सावित्री श्याम]

बात की लें, लोहे के बने हुए सामान की बात को लें। अगर इनकी डिमांड घट जाए और इनका स्टाक जमा हो जाए तो क्या इसका यह नतीजा नही होगा कि जो आपने पैसा लगाया है, जो इसैंटिव दिया है, वह सब बेकार हो जाएगा। टैक्सटाइल की बात को ही आप ले। बीस करोड का कन्ट्रोल का कपडा आज जमा हो गया है। बम्बई की मिलें बन्द ही गई हैं। मजदूरो की छन्टनी होने लग गई है। बेरोजगारी बढने लग गई है। इस बात मे आपको बैलेंस रखना होगा। खरीदने की लोगो मे शक्ति बनी रहे इसको आपको देखना होगा। चीजो को लोग खरीदे और बरते, इसका आपको ध्यान रखना होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने हमारा ध्यान कल्चरल डैलीगेशन के आदान प्रदान की ओर दिलाया है। कुछ लोग यहा से जाते हैं दूसरे देशो मे पढे लिखे लोग जाते है और वहा से विदेशो से यहा भी ऐसे लोग आते हैं। इन के ऊपर भी हम को निगाह रखनी होगी। मैं रुडकी यूनिवर्सिटी की मिसाल यहा आपको देना चाहती हू। वहा कुछ लोग बाहर से आए है। उनके बीच मे बैठ कर जिस तरह से वहा के वाइस चासलर ने बातचीत की है डिनर और लंच पर, चाय पर उसकी तरफ भी हमारी निगाह जानी चाहिए। जहा हमे आन्तरिक लोगो से खतरा है, आन्तरिक तत्वो से खतरा है वहा हमे बाहरी तत्वो से भी खतरा है और उन से हम को सावधान रहना होगा। इस तरह का वातावरण हमे बनाना होगा कि कोई भी इंटरफीयर न कर सके और हम तरक्की कर सकें। हमारी प्रधान मंत्री हिन्दुस्तान के करोडो लोगो का प्रतिबिम्ब है उनकी आत्मा है। उनकी बात को हम पूरा कर सके, उनके प्रोग्राम को सफल बना सके, इस तरह का वातावरण हम को निर्मित करना होगा।

श्री राजदेव सिंह (जौनपुर) सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हू और आपको धन्यवाद देता हू। दो दिन के भीतर यहा बहुत सी बाते कही गई है। उनको दोहराना मैं नही चाहता हू। लेकिन कही कही उनका जिक्र तो हो ही जाएगा। यह कहा जाता है कि एमरजेंसी की क्या जरुरत थी। लेकिन मैं समझता हू कि देश मे छ महीने तक अगर एमरजेंसी लागू न की गई होती। तो हमारे देश को आजादी बाहरी और भीतरी दुश्मनो से बडे खतरे मे पड गई होती।

आज हरेक आदमी को सोचना पडता है कि किस तरह से अपनी आजादी की रक्षा की जाये। देश को 90 साल की लडाई के बाद जो आजादी मिली उसकी हिफाजत के लिए अगर 25 जून को एमरजेंसी न लगाई गई होती तो देश की क्या हालत होती। राजनीति यही कहती है कि बाहरी हमले होते और भीतर के लोग उनका साथ देते। हम यह नही भूलना है कि हमारे देश मे अभी नेशनल करैक्टर नही बन पाया है कितने लोग देश मे ऐसे है जो माई कंट्री फर्स्ट की बात सोचते है। आज एमरजेंसी मे एक करैक्टर बन रहा है लोग दफ्तरो मे ठीक काम करने लगे है।

अगर आज एमरजेंसी नही होती तो ठीक मानिये कि सडको पर विद्यार्थियो के जरिए हजारो बसे फूक दी गई होती, कालेजो मे भी बहुत सी चीजे जला दी गई होती। तो क्या एमरजेंसी बुरी बात है ?

मै एक बात सीधी सी जानता हू कि अगर कोई ऐसी चीज है जिससे देश बन रहा है लोगो की आदत राष्ट्रीय बन रही है तो अच्छा है या बुरा है। वह अच्छा है। शिक्षा रेल, राष्ट्रीय करैक्टर, सरकारी दफ्तरो के मामले में देखिए, आज जनता की बात

वे लोग कहते हैं, लेकिन जनता से पूछिये, जनता अब सुखी है। उसको रोज की हुडदंग-बाजी, और अखबारों में जो गन्दी-गन्दी चीजें पढ़ने को मिलती थीं, उनसे उसको छुट्टी मिली है।

कल एक वक्ता ने कहा था कि बिहार के लोग यहां तक कहते हैं, हम भी कहते हैं, कि जो एमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, उसे दो महीने पहले घोषित किया जाना चाहिए था।

जो लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस के भीतर रहता है तो प्रोग्रेसिव रहता है, और पार्टी छोड़ देता है तो रिएक्शनरी हो जाता है। आप खुद देखें। चिमनभाई पटेल कल तक बड़े बदमाश थे, गुजरात की तमाम पार्टियां व विद्यार्थीगण कहते थे कि जब तक वे नहीं हटेंगे हम चुप नहीं रहेंगे। लेकिन आज 5 पार्टियों का जो गठन है, वह सब उनके साथ हैं। वह समझते हैं कि इतना भी लोगों को नहीं मालूम कि जो पार्टियां गुजरात में राज्य कर रही हैं वह किस की बदौलत राज्य कर रही हैं। क्या चिमनभाई पटेल की बदौलत कर रही है और उनके सहयोग के कारण ? जो दो साल पहले बहुत बुरे थे और पूरा गुजरात, वहां की पार्टियां, वहां के छात्र उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे, आज उनके साथ हैं। यह तो हालत है। इस तरह की बात होते हुए भी लोग इस तरह की बातें करते हैं।

अभी 31 दिसम्बर खतम हुआ है, कुछ कन्सील्ड इनकम सामने आई है। क्या कोई कह सकता है कि अगर आज एमरजेंसी न होती तो क्या इतनी बड़ी कन्सील्ड इनकम ब्लैक मनी उभरकर सामने आती। कभी नहीं आ सकती थी। कुछ लोगों ने कहा है कि देश में डर का वातावरण है, भय का वातावरण है, लोग डर रहे हैं। अगर डरकर लोग अच्छा काम कर सकते हैं तो जरूरत डरवाने की है।

उधर के लोग डैमोक्रेसी की बात करते हैं। अगर उनका राज्य होगा तो उनकी पार्टियों और स्टेट में कोई भेद नहीं रहेगा और उसमें डैमोक्रेसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। उनके मुंह से बड़े ठंडेठंडे इस सदन में डैमोक्रेसी की बात निकलती है। अगर उनका राज्य होगा तो डैमोक्रेसी का पता नहीं चलेगा।

मैं प्रैस के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं। बड़े बड़े प्रेस किस के हैं? पूंजीपतियों के हैं। अभी हमारे सामने एक मामला है हिन्दुस्तान टाइम्स का। वहां के संपादक साहब को हटाया गया है, मुकदमेबाजी हो रही है। बिरला साहब उनको नहीं चाहते हैं। तो जो पूंजीपति चाहता है, और संपादक उसको नहीं लिखेगा तो उसको निकालकर बाहर कर दिया जायेगा। तो जितने बड़े बड़े अखबार हैं, जिनके ऊपर ये लोग आंसू बहा रहे है, सब बड़े बड़े पूंजीपतियों के है और पूंजीपति राष्ट्रीय सीमा, नेशनल बाउन्ड्री को नहीं मानता है। आज हमारे देश का पूंजीपति यह सोचता है कि अगर अफ्रीका में इंडस्ट्री लगाने से उसको फायदा है तो वह वहां पर लगायेगा, भले ही हिन्दुस्तान के लोग भूखे मरते हों।

भूतपूर्व अध्यक्ष, सरदार हुकमसिंह, की एक बात अभी तक हमारे दिमाग में है। उन्होंने कहा था कि हमारे अखबारों की विचित्र हालत है, अगर किसी मेम्बर पर कोई दूसरा मेम्बर चप्पल फैंकता है या हाथापाई होती है, या कोई ऐसी बात होती है, जो मर्यादाहीन है जो हाउस में नहीं होनी चाहिए, तो अखबार वाले मोटे मोटे अक्षरों में उस को निकालते है, और अगर कोई बहुत स्टडी कर के स्पीच देता है, तो अखबार में निकलता है कि श्री सी-एंड-सो आस्सो स्पोक। अगर अखबार वाले ये हरकतें जारी रखेंगे कि यहां जूतेबाजी हो और वे उस को मोटी मोटी सुर्खियों में छापे, तो

[श्री राज देव सिंह]

देश से उस का खराब असर होगा। उस से रकियन्ज, गूडा एलिमेंट्स एनकरेज्ड होंगे और सोबर एलिमेंट्स दुखी होंगे। इन्ही अखबारों के लिए हमारे मित्र आंसू बहाते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, ये अखबार बडे बडे पूजीपतियों के होते हैं, जिन का कोई देश नही होता है, जिन के लिए कोई राष्ट्रीय सीमा नही होती है। मामूली लोगो के जो छोटे छोटे अखबार निकलते हैं, वे डेमोक्रेसी, देश की स्वतन्त्रता और अपने देश की तरक्की मे विश्वास करते हैं। उन को हर तरह से एनकरेज करना चाहिए और बडे बडे अखबारो पर हमेशा के लिए ऐसी पाबन्दी लगानी चाहिए, जिस से वे देश के हित के विरूद्ध कोई काम न कर सके।

जहा से मैं आता हू, उत्तर प्रदेश के वे पद्रह जिले आर्थिक दृष्टि से हिन्दुस्तान के सब से पिछडे हुए जिले हैं। उन जिलो की आबादी इस समय चार करोड के करीब है। 1857 मे जो स्वराज्य की लडाई हुई थी, उस समय से ये पद्रह जिले देश की स्वतन्त्रता के लिए बडी बहादुरी के साथ लडते चले आ रहे हैं। इन नब्बे सालो मे जितनी भी लड़ाइया हुई, उन मे उन्होने बडी बहादुरी के साथ भाग लिया। 1942 मे बलिया जिले मे सात दिन तक अग्रजो का राज नही था, और आठवें दिन अखबार मे निकला था कि **बलिया रीकांकर्ड**—बलिया को फिर से जीत लिया गया है। उन जिलो के अनेक लोगो को फासी की सजा हुई थी और हजारो आदमी जेलो मे गए थे—तबाह हुए थे इस उम्मीद से कि स्वराज्य मिलने के बाद हमारी भी हालत सुधरेगी। लेकिन दुख के साथ कहना पडता है कि पच्चीस छब्बीस सालो के बाद भी उन गरीब जिलो की हालत वही है, जो स्वराज्य से पहले थी।

अग्रेज वहा के किसानो के लिए ट्यूबवैल नही लगाना चाहते थे, और नहर नही देना चाहते थे, क्योंकि वहा के लोग उन की नजर मे बागी थे। अपनी सरकार के आने पर वहा के लोगो को बडी आशायें हुई थी, लेकिन वे आशायें अभी तक पूरी नही हुई हैं।

दिल्ली और बम्बई मे साढे तीन लाख झुग्गियां उजाडी गई हैं। कब? जब कि सिर पर बारिश थी और उन मे यह ताकत आज भी नही है कि वह अपने लिए मकान खडे कर सके। आप जा कर देख सकते हैं मदनगिर के इलाके मे और दूसरे इलाको मे जहां इन झुग्गी वालों को ले जा कर फेका गया है और आज उन से 50 रुपए उस जमीन का जो उन को एलाट की गई है किराया मागा जा रहा है। उन के पास पैसा नही है कि अपने सिर पर छत खडी कर सकें। ऐसी हालत है। तो ठीक है, गरीबो को उजाड कर के दिल्ली को खूबसूरत बनाइए। टूरिस्ट आएंगे, आप को फारेन एक्सचेंज की आमदनी होगी। अभी हाउसिंग कमेटी की मीटिंग थी। इजीनियर लोग आए थे। उन्होने कहा कि लेबर नही मिल रहा है। कैसे मिलेगा? लेबर को तो आप ने 15 मिल दूर फेंक दिया। वही तो लेबर था। अब लेबर का काम वह करे जो दस दस मजिला मकानो मे रहते हैं। अब वह लेबर नही मिलने वाला है। अगर यही हालत रही तो दिल्ली मे लेबर की परेशानी होगी और कास्ट्रक्शन वर्क टूट जायगा।

इन शब्दो के साथ जो आप ने थोडा सा मुझे मौका दिया है उस के लिए आप को धन्यवाद देता हू और यह कहना चाहता हू कि चारो दिशाओ मे तरक्की हुई है एमेंजेसी की वजह से और जब एक राष्ट्रीय आचरण हमारे देश का बन जाय तभी आपत्कालीन स्थिति समाप्त की जाय। नही तो ये चन्द लोग जो पार्टियो के थे वह

क्या करते थे ? आखिर आज कितने आदमी बन्द किए गए हैं। हरएक पार्टी के 8–10 आदमी बन्द हैं, नेता लोग बन्द हैं। बाकी सब बाहर हैं, उन की पूरी पार्टी बाहर है। लेकिन वह सामने नहीं आते हैं।

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Mr. Chairman. The Prime Minister of this country has cut the Gordian, knot in the annals of Indian history and is taking this country from political freedom to economic freedom. The charter of economic freedom enunciated immediately after the emrgency has created an atmosphere of discipline and has led to increased production in the country. I often hear criticism about the declaration of emergency. the President's Address describes the situation and events that developed in this country leading to the need for taking such an action to protect this country and to give economic freedom to the down-trodden people. This is a new chapter which has been opened by the Prime Minister of this country and the persons who are obstructing and putting impediments on the road to prosperity and the establishment of egalitarian society should know this.

MR. CHAIRMAN: You can continue tomorrow.

18.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, January 8, 1976/Pausa 18, 1897 (Saka)

GMGIPNC M—1821 LS—978